हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

12.03.2025/1100/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 1458 (स्थगित)

श्री भुनेश्वर गौड़ : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

प्रश्न संख्या - 2389

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि क्या सरकार नाबार्ड के माध्यम से धनराशि लेकर इलैक्ट्रिक बसों को खरीद रही है? जिसके उत्तर में हां कहा गया है। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम इलैक्ट्रिक बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार है? इलैक्ट्रिक बसों के लिए प्रदेश में कितने स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन खोल दिए गए हैं? इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि कितनी इलैक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं? विभाग द्वारा जो Letter of Award(LoA) दिया गया है उसके अनुसार किस कम्पनी से और किस रेट पर बसों को खरीद रहे हैं? मैं चाहता हूं कि ये सब जानकारी माननीय उप-मुख्य मंत्री जी देने की कृपा करें।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड के माध्यम से जब भी कोई फैसला किया जाता है तो उनकी अनुमति भी ली जाती है। माननीय श्री जय राम ठाकुर की सरकार में भी रोप-वे लगाने के लिए विशेष अनुमति ली गई थी और उसके बाद एक रोप-वे प्रदेश में लगाया गया है। उसी प्रकार अब इलैक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशन्ज़ के लिए भी नाबार्ड की सेवाएं ली जा रही हैं। माननीय सदस्य ने बसों की खरीद की बात कही है तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हम शुरुआत में 1500 बसों को इलैक्ट्रिक बसों में बदलने की बात कर रहे हैं। हमारा फ्लीट बहुत बड़ा है और इन्हें इलैक्ट्रिक बसों में बदलने का कार्य एकमुश्त नहीं हो सकता

और इसे चरणबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार की भी कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे हमें एकमुश्त पैसा मिल सके।

12.03.2025/1100/डी.सी.-एन.जी./2

इसके लिए हम केन्द्रीय मंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने हमें बताया था कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में लगभग एक लाख बसों को इलैक्ट्रिक बसों में बदला जा रहा है। ऐसे में कम्पनियों के पास आपको बसों की सप्लाई जल्दी देने के लिए समय नहीं है। हम अपने स्तर पर भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने एक बार टेण्डर लगाया था लेकिन कोई कम्पनी ने उसमें भाग नहीं लिया। हमने फिर दोबारा से टेण्डर लगाया है और इस बार दो कम्पनियों ने टेण्डर भरा है। इनमें से एक M/s Olectra Greentech Ltd. है.

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

12.03.2025/1105/DC-PB/-1

प्रश्न संख्याः 2389 क्रमांगत...

उप मुख्य मंत्री जारी...

इनके साथ फाइनेलिटी हो रही है। क्योंकि जो पहले इलैक्ट्रिक बसें खरीदी गई थीं उसमें उनकी मरम्मत का प्रावधान नहीं था इसलिए वे बसें जो खरीदी गई है उनकी मरम्मत न होने के कारण जगह-जगह खड़ी हो गई है और उनकी मरम्मत और मेंटेनेंस बहुत हैवी है। इनकी बैटरी ही चेंज करनी हो तब भी बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए इस बार टैंडर में बस की खरीद और उसकी 10 साल तक मरम्मत का प्रोविजन किया गया है। इस बस की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये के आसपास है और इसनी 10 साल की मरम्मत 40-45 करोड़ रुपये के आसपास पड़ेगी। अभी इन 30-40 बसों को खरीद की बात चल रही है। पिछले कल भी कैबिनेट में यह विषय रखा गया था और हमने कैबिनेट को भी सूचित किया है। इसके इलावा जो टाइप-II बसें लेने की बात है उसमें अभी केन्द्र सरकार की आपत्ति है।

बसें जिस प्रकार से बन करके आती हैं उन्हें पहाड़ी इलाकों में चलाना मुश्किल है। इसलिए हमने कहा था कि पहाड़ी इलाके के मुताबिक बसों की बॉडी चेंज करने की अनुमति दी जाए। आदरणीय सड़क परिवहन व राज्यमार्ग मंत्री श्री गडकरी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार इन नॉर्म्ज को नहीं बदल सकते, उन्होंने कहा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह हमारे केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है। लगभग दो वर्ष हो चुके हैं हम लगातार हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट लॉट फाइनल होता है तभी जाकर इलैक्ट्रिक बसों को खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

12.03.2025/1105/DC-PB/-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन बसों को चलाने का ट्रायल पूरा किया है? जिस तरह आपने कहा कि इनकी रिपेयर-मेंटेनेंस पर बहुत खर्चा आता है और सवा करोड़ रुपये के लगभग बस पड़ेगी। इसलिए हमारी डिज़ल से चलने वाली बसें हैं उनकी तुलना में कितना आर्थिक बोझ प्रदेश पर पड़ने वाला है? क्या इसकी तुलना सरकार ने की है? या सिर्फ हरित क्रांति को चरितार्थ करने के लिए सरकार ने इस एंगल को इग्नोर कर दिया है कि कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा? अध्यक्ष महोदय, दूसरा में पूछना चाहता हूं कि सरकार पहले चरण में 327 बसें रखरीद रहे हैं। तो 327 बसों को के लिए चार्जिंग स्टेशन की क्या व्यवस्था है? जैसा मैंने पूछा भी था और आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या उन रूट्स पर चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं? आप पिछले दो सालों से विधायक प्राथमिकता में विधायकों से इलैक्ट्रिक बस के पांच-पांच रूट्स लिए हैं तो क्या आप आश्वासन देंगे कि अगर ये 327 बसें आती हैं तो सभी विधान सभा क्षेत्रों को बराबर बस रूट दिए जाएंगे?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इलैक्ट्रिक बसें खरीदना एच0आर0टी0सी0 के वश का काम नहीं है। मैं इस सदन को ईमानदारी से बता रहा हूं कि विभाग ने प्रदेश सरकार को यह बता दिया था कि ये बसें एच0आर0टी0सी0 नहीं खरीद पाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार विभाग को बसें खरीदने के लिए पैसा दे रही हैं।...(व्यवधान) सरकार कहीं से भी पैसा दे सकती है, यह उनके बजट की बात है।

अध्यक्ष : ...(Interruption). Please do not interrupt in between.

उप- मुख्य मंत्री : मैं इस विषय को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की कंट्रोवर्सी में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हमारे लिए हैल्पफुल हैं। वे हमारे साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लीट को कैसे चेंज करना है और इसके लिए लगातार बात हो रही है। हमें हिमाचल प्रदेश सरकार इन बसों के लिए पैसा दे रही है

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1110/a.p./h.k./01

प्रश्न संख्याः 2389 क्रमांगत.....उप-मुख्य मंत्री द्वारा जारी.....

लेकिन बात यह है कि हमें हिमाचल प्रदेश सरकार इन बसों के लिए पैसा दे रही है इनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन बनने है उनके लिए 110 करोड़ रुपये भी आ गये हैं और हमारी पेट्रोलियम कंपनियों से भी बात हो रही है और तीनों पेट्रोल की कंपनिया लगातार पैसा देख कर हमारे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हमारे साथ in agreement हैं, हमारे चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे। आप जो कह रहे है कि सारा हिमाचल इन इलेक्ट्रीकल बसों को अफॉर्ड कर सकता है। अभी मैं पीछे स्विट्ज़रलैंड गया था वहां पर अभी तक डीजल की बसें चल रही हैं तो अगर हम कहे कि हम यहां पर डीजल की बसें बंद कर देगें तो मुझे नहीं लगता की हम यह कर पाएंगे। एच0आर0टी0सी0 250 डीजल बसें खरीद रही है। हमारे से पहले माननीय श्री बिक्रम जी भी 250 बसें खरीद की गये थे पर वो आई नहीं थी। जब हमारी सरकार बनी तो उसके दूसरे महीने के बाद वह बसें आई। लेकिन हम इस बार 36-37 सीटों वाली छोटी बसें ही खरीद रहें हैं। डीजल की बसें हम एच0आर0टी0सी0 से खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रीक बसों का सारा दारोमदार राज्य सरकार पर है, उसका चार्जिंग व खरीद का पैसा राज्य सरकार देगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिक्रम सिंह जी।

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष जी जब सरकार बनी थीं तो मैं आदरणीय उप-मुख्यमंत्री जी से बात की थी और इस सदन में भी बोला था कि यह जो आप इलैक्ट्रीकल बसों की बात कर रहें है यह व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पर आने में बड़ी दिक्कत होगी। पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख बसों की मांग है और यहां पर इतनी manufacturing ही नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और डिले होगा। यह बसें अभी नहीं मिलेगी। ऐसा मैंने पहले भी कहा है और अभी भी बोल रहा हूं। आपकी मंशा ठीक है लेकिन यह व्यवहारिक तौर पर नहीं होगा। लेकिन जो एच0आर0टी0सी0 की हालत इस समय हो रही है। आपने जो डीजल बसों को खरीदने का प्रपोजल है जब तक alternative नहीं होता तो क्या डीजल बसों के प्रपोजल को बढ़ाया जाएगा?

12.03.2025/1110/a.p./h.k./02

अध्यक्षः माननीय उप-मुख्मंत्री महोदय।

उप-मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ट्रासपोर्ट मंत्री रहे हैं और व्यवहारिकता से अवगत है और अगर इलैक्ट्रीक बसों में डिले होता है अभी तक 297 इलैक्ट्रीक बसों की डिलीवरी की बात है उन्होंने 11 महीने मांगे है। तो इसका मतलब यह है कि अभी समय लगेगा और अगर हम ज्यादा दबाव डोलेंगे तो हो सकता है कि 6 महीने में गाडिंया मिल जाएं और उसकी अन्तिम स्थिति में लगभग हम पहुंच गये हैं लेकिन हम अपने तौर पर 250 डीजल बसें और 100 टेंपो ट्रैवलर खरीद रहें हैं उस परचेज को हम शीघ्र करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य हंस राज जी।

श्री हंस राज जी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम यह निवेदन है कि हमारे चंबा में जितने भी रूट्स हैं जब यहां पर cloud burst हुआ था और कोविड के बाद से हमारे कई रूट बंद हुए है जैसे आइल की तरफ हमारी बस जाती है या चंबा से तीसा की तरफ बसें जाती हैं। हालांकि चंबा डिपो में बसें नहीं हैं। वहां पर मेंटेनेंस के लिए जो वर्कशॉप में स्टाफ है वह बिल्कुल ही बंद हो गई है। इस बारे में वहां में कर्मचारी और कई लोग हमसे कई बार

गुजारिश कर चुके हैं। तो क्या आप माननीय सदन को और वहां के लोगों को आशवासन देगें कि आप इसे चालू रूप में ले आएंगे और इसके साथ ही जितने रूटों पर हमारी बसें सिर्फ खड़ी रह गई हैं तो क्या उनकी जगह रिप्लेस करके चंबा को भी नई बसें उपलब्ध करवाई जाएगी ऐसा मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं?

अध्यक्षः माननीय उप-मुख्मंत्री महोदय।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने आदेश दिये है जो गाड़ी 15 साल चल गई है उसको ऑफ रोड करना है और सरकारी क्षेत्र की कोई भी गाड़ी, चाहे आप बसों की बात करें, किसी भी विभाग में 15 साल से ऊपर की गाडी चलाई नहीं जा सकती और एच0आर0टी0सी0 में 9 लाख कि0मी0 से ऊपर जो गाड़ी चल जाती है उसको भी हम ऑफ रोड या ऑक्शन कर देते हैं।

ए0टी0 द्वारा जारी .....

12.03.20205/1115/AT/ HK /.1

प्रश्न संख्या : 2389 जारी .....

श्री उप मुख्य मंत्रीः

अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो 15 साल गाड़ी चल गई है उसको ऑफ रोड करना है और सरकारी क्षेत्र की कोई भी गाड़ी जो है चाहे वह बसिज की बात है बसों के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में 15 साल से ऊपर की गाड़ी चलाई नहीं जा सकती है और एच0आर0टी0सी0 में 9 लाख किलोमीटर जो गाड़ी चल जाती है उसको भी हम ऑफ रोड कर देते हैं तो इस साल हमें लगता है कि जो गाड़ियां चल रही हैं आप यह तो नहीं कह सकते कि वे गाड़ियां नॉर्म्स पूरा नहीं कर रही हैं लेकिन आप यह कह सकते हैं कि नॉर्म्स पूरा करते हुए भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है हमारी यह कोशिश है कि हम इस साल के दौरान लगभग 600 ,650 नई गाड़ी डाल दें ताकि जो माननीय सदस्यों की मांग है उसको हम पूरा कर सकें । कोशिश है कि जो आपके ड्राइवल और दुर्गम इलाके हैं उसमें जहां कम सवारी है **जहां हम टेंपो ट्रैवलर खरीद रहे हैं 100 का**

आर्डर हमने दे दिया है 100 और खरीदने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जगत सिंह नेगी जी भी यही बात कर रहे हैं आपका इलाका काफी टफ है **तो हम वहां पर टेंपो ट्रैवलर्स भेजने की कोशिश करेंगे और बाकी स्थान पर जो डीजल की बसें जानी हैं वहां डीजल की भेजेंगे और नॉर्मल प्लेस में इलेक्ट्रिक बसें भेजने का प्रयास करेंगे** ।

श्री रणधीर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महादय,मैंने पूछा था कि 2 साल से विधायक प्राथमिकता में पांच-पांच बस रूट हर विधायक से लिए जा रहे हैं भी आपने बसें खरीदी नहीं और आप 11 महीने और बता रहे हैं पता नहीं और कितना समय लगेगा । हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से सथान हैं जहां बसें बंद हुई है फोरलेन बनने से खासकर एक क्षेत्र जो स्वारघाट तहसील मुख्यालय को जोड़ता है चाहे वह हमारी छरोल , कलर पंचायत है ऐसी जो पंचायतों के लिए पहले नेशनल हाईवे था सारी बसें चाहे इंटरस्टेट व अन्य रूट वाली बसें वहां से जाती थी अब वह सारे बंद हो गए तो वहां पर नए रूट हमने प्रोपोज़ किए थे आब एलेकट्रिक बसों का अभी तक भी सपना ही है इसलिए क्या आप आश्वासन देंगे कि जो आप नई बसें खरीद रहे हैं उनमें से हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहां-जहां बसों की जरूरत है जो बस रूट हमने विधायक प्राथमिकता को दिये है वहां पर बसें चलाने का आश्वासन देंगे ?

12.03.20205/1115/AT/ HK /.2

उप मुख्य मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय ,हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां न तो हवाई सेवाएं हैं और ना ही यहां पर रेल सेवाएं हैं और है अगर है भी तो बहुत लिमिटेड सब कुछ जो है रोड ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर कर रहा है और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी एच0आर0टी0सी0 50वां साल मना रही है और गोल्डन जुबली साल में प्रवेश भी किये है और इस बात पर विवाद भी है सर कुछ लोग कहते हैं कि यह कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ कहते हैं कि यह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और मैं तो इसको वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं क्योंकि जितने भी घाटे के रूट हैं हिमाचल प्रदेश में वह सारे एच0आर0टी0सी0 चलती है जितनी भी रियलिटी सफर है चाहे महिलाओं को हम 50%

सफर करवाते हैं या 29 ,30 तरह के और सफर है वे सारे एच0आर0टी0सी0 करवाती है और उसके बाद हम इसके ड्राइवर कंडक्टर को ज गवर्नमेंट का जो पे स्केल्स देते **हैं फिर हम ऑ0पी0एस0 भी एच0आर0टी0सी0 को देने का फैसला कर चुके हैं** रोज लगभग चार से पांच लाख लोग एच0आर0टी0सी0 में ट्रेवल कर रहे हैं तो इसलिए एच0आर0टी0सी0 उतनी ही महत्वपूर्ण है । जैसे हम शिक्षा विभग की बात करते हैं जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों को घर आंगन तक पहुंचने में एच0आर0टी0सी0 की बहुत बड़ी भूमिका रही है मैं सभी मान्य सदस्यों को अस्वस्थ करना चाहता हूं कि कोशिश हमारी रहेगी कि हम 1000 के आस पास जो पुरानी बसें हो गई है उन को जल्दी से रीपलेस कर पाएं और 600 का ऑडर हमने दे दिया ह वाकियों का हम दे देगे और **आपको मैं आश्वशत करना चाहता हूं कि जिन के मन में आशंकाए है कि यह रूलीग पार्टी को नई बसें दे दी जाएंगी ऐसा नहीं कि जाएगा सारे प्रदेश में संतुलित बसें हम अलौट करेगे** ।

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1120/md/yk/1

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या - 2390

प्रश्न संख्या : 2390

Shri Vinod Sultanpuri : Hon'ble Speaker, Sir, I am very thankful to the Hon'ble Minister and I must say that he is a dynamic Minister as well. Sir, I would like to supplement इसमें segregation of waste material के ऊपर बहुत डिटेल दी है परंतु हम गांवों में यह पा रहे हैं कि वहां पर मिक्स्ड हो रहा है और सेग्रीगेशन नहीं हो रही है। Because we are not using it right now. Now, there are lots of technologies in place. Instead of segregating the garbage, the garbage can be segregated by using the machine and by it the problem of waste material can be resolved. So, I request the Hon'ble Minister कि आप इसे कंसिडर करें और मैं बताना भी चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शडयाना पंचायत ने अपने पैसे से क्लैक्शन के लिए इलैक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है। मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जो सबसे सुंदर, क्लीन और प्लास्टिक फ्री गांव होगा उसके लिए आप अवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करें तथा उसकी

मोनिटरिंग भी हो। I think it will clean Himachal and also good for all of us. Our State is a tourist destination and it looks nice when we have clean hills. Thank you.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे पास Solid Waste Management Component है। उसके तहत विभिन्न पंचायतों में काम किया जा रहा है। पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी इम्पावर किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

Speaker : Please maintain order in the House. Hon'ble Member, Shri Kewal Singh Pathaniaji, kindly pay attention if you want ask the supplementary. Let the Hon'ble Minister reply, thereafter you can ask.

12.03.2025/1120/md/yk/2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वैट वेस्ट मैनेजमैंट के लिए हमारे पास पूरी स्टेट में लगभग 1473352 हाउस होल्ड हैं। जिसमें से 593625 हाउस होल्ड वैट वेस्ट मैनेजमैंट कर लेते हैं और बाकी जो 319027 फैमिलीज रह गई हैं उनको कम्युनिटी कम्प्सोट पेस्ट पिट्स द्वारा लगभग 126000 इंडिविजूअल कम्प्सोट पेस्ट पिट्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो 434000 बचे हैं उसके लिए हम लोग तरह-तरह के निकाल रह रहे हैं। अभी हमने कुछ मशीन्ज भी प्रक्योरमैंट की हैं और वे कुछ जगह वेस्ट मैनेजमैंट के लिए लग भी गई हैं और कुछ जगह लग रही हैं। अभी गाड़ी की बात की गई तो गत वर्ष हमने 193 ई-व्हीकल्ज के एच0पी0एस0ई0डी0सी0 के थ्रू टेंडर किया था। उसकी अभी प्रक्योरमैंट नहीं हुई है। आने वाले वित्त वर्ष के लिए कूड़ा उठाने के लिए हम 800 और ई-व्हीकल्ज ला रहे हैं। हमें गांवों में तो कहीं समस्या नहीं आती और हम यहां पर सभी गांव के परिवेश से हैं। परंतु जहां पर टूरिस्ट्स का फुटफॉल ज्यादा है जैसे यदि हम कुल्लू-मनाली, कसौली, चम्बा-डलहौजी, शिमला में नालदेहरा, कुफरी या शिमला के आसपास जो पंचायतें पड़ती हैं, हम वहां पर इस समस्या को ज्यादा फेस कर रहे हैं। इसके लिए हम गाड़ी की भी प्रक्योरमैंट कर रहे हैं। हम इसके लिए अच्छे स्टैप्स उठा रह रहे हैं

और लोगों को गाइडैंस देकर इंम्पावर कर रहे हैं। हमने अम्बुजा, अल्ट्रा टैक और बागा सिमेंट प्लांट्स के साथ कुछ एम0ओ0यूज0 साइन किए हैं कि हमारा कुछ प्लास्टिक वैस्ट वहां जाकर भी जलाया जा सके। इसके अतिरिक्त हमने यह मैटर कुछ फाउंडेशन्ज के साथ भी टेकअप किया है जोकि इस स्वच्छता अभियान के तहत समय-समय पर काम कर रही हैं। आपने जहां तक कसौली की बात की है कि एक नई मशीन आ गई है जिसमें सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

12.03.2024/1125/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 2390 जारी----

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी---

जहां तक मुझे आपने कसौली के बारे में बताया कि अब नई मशीन आ गई है जिसमें सैग्रीगेट न करना पड़े क्योंकि वैट वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को अलग-अलग करने की बहुत बड़ी समस्या रहती है और कई बार काम करने के लिए लोग भी नहीं मिलते। उसको हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं विभाग को कहूंगा कि इसको एक्सप्लोर करके हम तुरंत आपको जवाब देंगे। अगर आपके पास भी उसका कोई समाधान है, ऐसी मशीन की जानकारी है तो वह आप हमें दें ताकि उसके बारे में हम पता कर सके और सभी टूरिस्ट स्थलों के आसपास और जहां ग्राम पंचायतों में अर्बनाइजेशन हो रही है, वहां हम लोग वह मशीन लगा सके।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि एक अवार्ड सिस्टम होना चाहिए। **इसके ऊपर विचार किया जाएगा कि हम पात्र पंचायत को अवार्ड दें ताकि लोग और जागरुक हों।**

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दे दिया है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मंत्री महोदय ने डिटेल में बताया कि हिमाचल प्रदेश में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक पंचायत को, दूसरी पंचायत को पिट्स के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। क्या पूरे ब्लॉक का कोई कंसोलिडेट प्लान है कि कहीं एक ही जगह पैसा

दिया जाए और वेस्ट मैनेजमैंट युनिट एक ही जगह बनाई जाए? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी बनी और उसका सारा कूड़ा कलैक्ट करके मेरी ग्राम पंचायत में एच.आर.टी.सी. की वर्कशॉप के साथ लगभग 5-6 साल फेंकते रहे। उस समय अनुराग शर्मा जी कमिशनर थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा उन्होंने राजस्थान की किसी फर्म के साथ एम0ओ0यू0 साइन किया और उस कूड़े की ऑक्शन से कॉर्पोरेशन को लगभग 4.47 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। पहले किशनगढ़ से बड़े-बड़े ट्राले आते थे अब उसमें 90 परसेंट की कमी आई है। वहां ग्राम पंचायत सुधेड़, गलोह, वार्ड नं0 - 3, वार्ड नं0 4 में लोगों का रहना ही मुश्किल हो गया था। मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा अर्बन डवलपमेंट डिपार्टमैंट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर जो काम किया है उसी तरीके से किया जाए और जो

12.03.2024/1125/केएस/वाईके/2

मंत्री जी कह रहे हैं, अलग-अलग की बजाय ब्लॉक वाईज़ या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कंसोलिडेट हो। यह नहीं कि अलग-अलग पंचायतों में चार लाख रुपया इसको दे रहे हैं, तीन लाख रुपया इसको दे रहे हैं, दो लाख रुपया इसको दे रहे हैं। कंसोलिडेट प्लान हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ी डम्पिंग साइट थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसमें बड़ा सफलतापूर्वक काम किया है तो उसको भी रैप्लिकेट करके जो माननीय मंत्री महोदय ने डिटेल में चाहे ई.व्हीकल की बात की है या दूसरे जो रूरल डवलपमेंट ने प्लान बनाए हैं, उनके बारे में कहा, मैं इस पर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी बोल रहे हैं, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि विभाग के पास कोई भी युनिट सैटअप करने के लिए पैसे पर्याप्त हैं। परंतु दिक्कत वहां आती है जब हम किसी भी पंचायत में युनिट लगाने जाए तो उस पंचायत के लोग विरोध करते हैं कि वह यहां पर नहीं लगनी चाहिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर आप अपनी स्वेच्छा से, वहां के एन0ओ0सी0 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमैंट का कोई भी प्लांट जब लगता है, चाहे वैट वेस्ट का लगे या सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट का प्लांट लगे, लोग विरोध पर उतर जाते हैं और सम्बन्धित विधायक ही हमसे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि यहां नही लग पाएगा। तो किसी ने भी, यह मैं आपको कंसोलिडेटिड बोल रहा हूं, पिट्स के

लिए ठीक है कि हम लोग 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपये दे रहे हैं परंतु हमारे पास पर्याप्त पैसा है। अगर आपके पास कोई भी जगह है, जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा प्लांट लग सकता है, आप हमें आइडैंटिफाई करें ताकि हम लोग आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको कार्यान्वित कर सके। जहां तक माननीय सदस्य ने धर्मशाला का उदाहरण दिया, वहां पर भी हमारे विभाग के सहयोग से कई फाउंडेशन्ज़ काम कर रही हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमैंट के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट से तरह-तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। यह काम हम लोग ऑर्गेनाइजेशन्ज़ और एन0जी0ओज़0 के साथ मिलकर शिमला में भी शुरू कर रहे हैं।

अगला प्रश्न अ0व0 की बारी में--

12.03.2025/1130/AV/AG/1

प्रश्न संख्या : 2391

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के लिए 485.97 करोड़ रुपये की राशि आई थी जिसमें से 421.60 करोड़ रुपये खर्च हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरी राशि के खर्च न होने के क्या कारण है और जो राशि खर्च नहीं हो पाई उस राशि का क्या हुआ? इसी तरह से प्रश्न में आगे सूचना दी गई है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रम संख्या 1 पर Strengthening of Existing Schools के ऊपर कोई भी धनराशि खर्च नहीं हुई। इसी में क्रम संख्या 6 पर Library Grant शीर्ष के तहत भी वर्ष 2024-25 में कोई राशि खर्च नहीं हुई, इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी ने समग्र शिक्षा के संदर्भ में अपना प्रश्न रखा है। इसमें इन्होंने विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि के लैप्स होने के बारे में जानना चाहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप तुलना करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारा समग्र शिक्षा का लगभग 95 प्रतिशत पैसा व्यय हुआ है और इस वर्ष यह त्रुटि न रहे इसके लिए कार्य किया जा रहा है। आपने उदाहरण के लिए जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में Strengthening of Existing

Schools और Library Grant के बारे में पूछा है कि अभी इनमें पैसा व्यय नहीं हुआ है तो आपने उत्तर में देखा होगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 336.74 करोड़ रुपये की राशि में से हमें अभी केवल दो किस्तें मिली हैं। मैं कुछ रोज़ पहले हमरे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी के पास गया था और मैंने उनसे बाकी बची राशि हेतु आग्रह किया है कि उनको भी जल्दी जारी किया जाए। उन्होंने पिछले हफ्ते ही हमारी 151 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है। **इस राशि से निश्चित रूप से शेष बचे कार्य पूरे कर दिए जाएंगे।**

समाप्त

12.03.2025/1130/AV/AG/2

प्रश्न संख्या : 2392

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से इंदौरा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिविल अस्पताल इंदौरा और सिविल अस्पताल गंगथ के अंदर रिक्तियों के संदर्भ में जानकारी मांगी थी। माननीय मंत्री जी ने उनमें रिक्तियों के बारे में जानकारी दी है परंतु सिविल अस्पताल इंदौरा और सिविल अस्पताल गंगथ, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल हैं तथा ये वहां पर लगभग डेढ़ लाख जनसंख्या सर्व करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले ही सिविल अस्पताल इंदौरा और सिविल अस्पताल गंगथ के दौरे पर गए थे। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि सिविल अस्पताल इंदौरा में डाक्टर्ज़ की 11 में से 7 पोस्ट्स खाली हैं। इसी तरह से गंगथ सिविल अस्पताल में डॉक्टर्ज़ की 5 में से 3 पोस्ट्स खाली हैं। वहां पर जो दो डॉक्टर्ज़ हैं उनमें में से भी केवल एक ही डॉक्टर अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और एक डॉक्टर मातृत्व अवकाश पर है। वहां पर यह सिलसिला काफी महीनों से चल रहा है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी और विभाग से यह जानना चाहता हूं कि उन दोनों अस्पतालों में ये डॉक्टर्ज़ के रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न खासकर डॉक्टर्ज़ के रिक्त पदों से संबंधित है।

टी सी द्वारा जारी

12.03.2028/1135/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्या : 2392 क्रमागत्

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ..... जारी

विशेष रूप से डॉक्टरों की कमी से संबंधित है। Government is always in continuity. We are trying our best but मैंने माननीय सदस्य के साथ इन दोनों ही अस्पताल का स्वयं दौरा किया है और माननीय सदस्य के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कुल 126 सृजित पदों में से 78 पद भरे हुए हैं जबकि 48 पद रिक्त पड़े हुए हैं जिनका विवरण इस प्रश्न के लिखित उत्तर में भी दिया गया है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्य मंत्री के मार्गदर्शन व सहयोग से हम दिन-रात कार्य कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि स्टाफ की कमी, डॉक्टरों की उपलब्धता व अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। **We are trying to fill in 200 posts of Doctors out of about 1500 paramedics including nursing staff and various others for which the case has gone to the Commission**. I think there is a written test on 16th. 61 OTAs on regular basis पर भरे जा चुके हैं। हाल ही में 28 लैब टेक्नीशियनों की भी नियुक्ति भी की गई है। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को वैज्ञानिक तरीके से दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डेंटल डॉक्टरों के 33 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। **33 Dental Doctors (batchwise) are also being taken. We are trying our level best and I do appreciate the concern shown by the Hon'ble Member. Certainly, at the moment, we are having a shortage,** लेकिन मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में पूरी तरह सतर्क है और सभी कमियों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। **इस क्षेत्र में विशेष सुविधाओं, चाहे वह लैब, आई0सी0यू0 या लेबर रूम से संबंधित हो या अन्य आवश्यक संसाधनों से संबंधित हो, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।**

श्री डी0एस0 ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सिविल अस्पताल कियार में ए0ओ0 की 10 पद स्वीकृत हैं लेकिन वहां पर केवल एक ही

डॉक्टर कार्यरत हैं और बाकी पद रिक्त हैं। सिविल अस्पताल सलूनी में एम0ओ0 के 8 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वहां भी केवल एक ही डॉक्टर कार्यरत हैं और 7 पद रिक्त हैं। सूण्डला में एक पद एम0ओ0 का स्वीकृत है, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। इसी प्रकार बरंगाल पी0एच0सी0 में एकमात्र स्वीकृत पद रिक्त पड़ा है। ये पद पिछले 2 वर्षों से खाली हैं। यह एक दुर्गम क्षेत्र है और हमने कई बार मंत्री महोदय से आग्रह किया है कि इन स्थानों

12.03.2028/1135/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। **मैं सदन के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किहार, सलूणी, सूण्डला और ब्रंगाल में डॉक्टरों के पद कब तक भर दिए जाएंगे**?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यदि वे इस प्रश्न को अलग से करेंगे तो मैं उसका निश्चित रूप से जवाब दूंगा। फिर भी इन्होंने प्रश्न पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि मैं इन सब जगहों में तो नहीं जा सका। हमारी वरिष्ठ सदस्य, Smt. Asha Kumari ji had taken me to 2-3 places. किहार सलूणी व सुण्डला अस्पतालों में बहुत सारी समस्याएं हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी है, **लेकिन मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि किहार, सलूणी और अन्य जिन स्थानों का आपने उल्लेख किया है, वहां जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी।** स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन सभी क्षेत्रों के लिए स्टाफ का पैटर्न तैयार कर दिया गया है और शीघ्र ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें, निश्चित रूप से इन स्थानों पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। **Please wait for some time. You will definitely get. I will give you answer of the separate question if you ask for because this was a specific question asked by the Hon'ble Member. I am fully prepared on your question. I know Kihar and Salooni. I will certainly go for visit also.**

Speaker: All these supplementaries are arising because you assured this House that shortly the vacancy position in the Health Department will be filled up. You have admitted that there is a vacancy position in the Health Department. So that is why all these supplementaries are arising because you yourself initiated all these supplementaries. Now I will again allow Shri D.S. Thakur.

डी0एस0 ठाकुर एन0एस0 द्वारा.... शुरू

12-03-2025/1140/ns-as/1

प्रश्न संख्या : 2392----- क्रमागत

श्री डी0 एस0 ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जब भी मैं कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न करता हूं (***) मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि मुझे डल्हौजी की जनता ने चुन कर भेजा है और मैं वहां का विधायक हूं, जनप्रतिनिधि हूं। मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है कि मेरे क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से पोस्टें खाली पड़ी हैं इनको कब तक भर दिया जाएगा? क्या आप इन पदों को शीघ्र भरेंगे?

Speaker: Hon'ble Minister, you may give assurance that how long you will take to fill-up all these vacancies in the near future. ...(Interruption) Please don't refer to the Member one who is not present in the House or Member of this House. Please don't refer and that will not be part of the record.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से पूर्ण रूप से अवगत हूं and I assure you that soon after this Session of the House will be over, मैं उन तीनों जगहों को पर्सनली विजिट भी करूंगा। Because I know they are remote areas and certainly they deserve attention from us. We will definitely work on the concerns which you have. मैंने जो लिस्टें पढ़ी हैं, उनमें पैरा मेडिकल, ओ0टी0ए0 या जितने भी पदों की भर्ती हो रही है तो उसमें आपको भी शेयर दिया जाएगा।। assure you it will definitely be filled.

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सिविल अस्पताल, गंगथ व इन्दौरा में डॉक्टर्ज की पोस्टें कब तक भरी जाएंगी? माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों सिविल अस्पताल, गंगथ में विजिट किया था तो इन्होंने अस्पताल की स्थिति को देखते हुए वहां पर दो डॉक्टर्ज डेप्यूट किए। लेकिन वहां पर दोनों ही डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये पोस्टें कब तक भरी जाएंगी और अगर कहीं पर

सरप्लस डॉक्टर्ज हैं तो क्या उनकी तैनाती वहां पर की जाएगी? क्योंकि डॉक्टर्ज न होने की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरप्लस डॉक्टर्ज को सिविल अस्पताल, गंगथ व इन्दौरा में लगाया जाएगा?

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

12-03-2025/1140/ns-as/2

Health Minister: Mr. Speaker, Sir, the concern of the Hon'ble Member (Indora) is really very genuine and I remember that I deputed two doctors because I didn't find them on duty. Really speaking the problem is, मैं इस सदन में मौजूद सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि हमें कभी-कभी मानवीय चीजों को जरूर सुनना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं सुनना चाहिए कि जो डॉक्टर्ज वहां भेजे गए हैं, वे वहां से चले जाएं। श्री मलेन्द्र राजन जी का प्रश्न बड़ा स्पैसिफिक है and he is right. Because I didn't find doctors there so I ordered that two doctors will be posted there and secondly those doctors reported also. तो होता क्या है कि डॉक्टर्ज जाकर पता नहीं किन-किन लोगों के पांव छू लेते हैं और अपना तबादला करवा लेते हैं। यह भी बड़ी मुसीबत है। मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि बांटने के बाद I must quote here that in one particular place i.e. Baragaon where it took me six months to depute one doctor. This place connected from either side whether you go from Kingal or from anywhere. This place is very good. But that doctor took six months to join there. I remember when the Secretary, Health Services gave him Show Cause Notice only then he joined. So that is the problem. But as far as your health institution is concerned, those two doctors will be join there and they perform their duties properly. **I assure you that within a week doctors will be available there.**

12-03-2025/1140/ns-as/3

प्रश्न संख्या : 2393

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में हमारी पिछली सरकार ने तीन अटल आदर्श विद्यालय शुरू किए थे। एक धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के मढ़ी, कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्र के गैहरा और नाचन विधान सभा क्षेत्र के गुडहैरी में अटल आदर्श विद्यालय बन कर तैयार हो गए हैं।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

12.03.2025/1145/RKS/AS-1

प्रश्न संख्याः 2393 जारी

श्री विनोद कमुार... जारी

अध्यक्ष महोदय, सरकार बार-बार इस बात को कहती है कि हम विपक्ष के विधायकों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अटल आदर्श विद्यालय, धर्मपुर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। नाचन विधान सभा के अटल आदर्श विद्यालय, गुडैहरी का 65 प्रतिशत कार्य आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय पूरा हो चुका था। मैंने शेष कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट सत्र में भी माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी से बात की थी। माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के इस विद्यालय के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए हम 20 करोड़ रुपये स्वीकृत कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में भी यह कहा गया कि आपके विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 20 करोड़ रुपये भेजा जाएगा। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि वह पैसा किस ट्रैक से भेजा गया है? क्या वह पैसा पैदल चलकर आ रहा है? जब माननीय मुख्य मंत्री या मंत्री जी आश्वासन देते हैं तो क्या उसके बाद अधिकारी आपकी बात नहीं मानते? अटल आदर्श विद्यालय, गुडैहरी का जो 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का कार्य हुआ है जो आज की तारीख में धूल

फांक रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या आप उस विद्यालय के शेष कार्य को पूर्ण करवाने के लिए राशि जारी करेंगे?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वह सत्र अधूरा होगा जिसमें माननीय विधायक इस प्रश्न को नहीं उठाएंगे। यह बात इनके समर्पण को दर्शाती है। हम इस कार्य को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और आप भी इस बात से जरूर सहमत होंगे। इस कार्य के पूरा न होने का कारण धन का अभाव है और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। आप तीन अटल आदर्श विद्यालय की बात कर रहे हैं, हालांकि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इन विद्यालयों को स्थापित करने के लिए 28 स्थान चिन्हित किए गए थे। इस कार्य को एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था और हमारा प्रयास भी यही है कि हम इनकी पूर्ति करें। आप इस बात से सहमत होंगे कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हमारी सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत जो कार्य चल रहे हैं उसमें हमने एक स्कूल के लिए अधिकतम राशि 3.50

12.03.2025/1145/RKS/AS-2

करोड़ रुपये से ऊपर नहीं दी है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने अटल **आदर्श विद्यालय, मढ़ी के लिए पहले लगभग 7.40 करोड़ रुपये जारी किए थे और अब 5.00 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए हमने वित्त विभाग से मामला टेक-अप किया है। हमारा प्रयास है कि आपका यह स्कूल शीघ्रातिशीघ्र फंक्शनल हो जाए।** जहां तक आप अटल आदर्श विद्यालय, मढ़ी की बात कर रहे हैं, वर्तमान में वहां पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की शैक्षिक गतिविधियां चल रही हैं। जैसे पिछली सरकार की भी गाइडलाइन्स थीं और हम भी इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए एक एस.ओ.पी. तैयार करेंगे ताकि आने वाले शैक्षिक सत्र में मढ़ी और गुडैहरी अटल आदर्श विद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो सके। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने गया था। मैंने इन संस्थाओं के निर्माण कार्य के लिए वहां पर लगभग 62 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए आग्रह किया है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास धन का अभाव है और इन तीन विद्यालयों में ही लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा 68 विधानसभा

क्षेत्रों के लिए 150 करोड़ रुपये का आउटले रखा गया है। **माननीय सदस्य, आप हमारे ऊपर विश्वास रखें, हम अपने संकल्प में जारी हैं और आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का अटल आदर्श विद्यालय शीघ्र फंक्शनल होगा।**

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि यह प्रश्न न लगता तो यह सत्र अधूरा रह जाता।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

12.03.2025/1150/बी.एस./डी.सी./-1

प्रश्न संख्याः 2393 क्रमांगत...

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर यह प्रश्न सदन में नहीं लगता तो शायद ये प्रश्न अधूरा रहता। परंतु आप सरकार की कार्यशैली देखिए, सरकार प्रश्नों को ले करके कितनी गंभीर है। पिछले दो वर्षों में यह प्रश्न छः बार लग चुका है और अब ये सातवीं बार विधान सभा में लगा है। लेकिन सरकार की तरफ से केवल और केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि सरकार कितनी गंभीर है? आज भी मंत्री जी की ओर से कहा गया कि कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र को पैसा दिया उसी तर्ज पर नाचन विधान सभा क्षेत्र को भी पैसा दिया जाए। कृपया, आप बता दीजिए कि यह कार्य होना है, तब भी ठीक है और अगर नहीं होना है तब भी आप हाथ खड़े कर दीजिए कि हमसे यह कार्य नहीं होना है। उसके बाद यह बात खत्म हो जाएगी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही उत्तर में कह दिया है कि सरकार प्रयासरत है

12.03.2025/1150/बी.एस./डी.सी./-2

प्रश्न संख्याः 2394

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, लियो बाइपास सड़क का मामला मैंने पहले भी सदन में उठया था और इसमें इस सड़क को बी0आर0ओ0 के अधीन करने के लिए मामला उठाया था परंतु बी0आर0ओ0 से अभी तक इसके लिए औपचारिक सहमति अपेक्षित है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि बी0आर0ओ0 स्वयं इसमें कोई पहल नहीं करेगा। क्योंकि लियो बाइपास हमारा सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, न सिर्फ इससे पूरी लाहौल-स्पिति घाटी को लाभ होगा परंतु सीमा क्षेत्र के लिए भी यह गहुत जरूरी है। इसके लिए 20 वर्षों में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि व्यय हो चुकी है। परंतु इसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब इस सड़क का लगभग दो किलोमीटर का पैच बचता है, उसे पूरा करने के लिए भी करोड़ों रुपये की राशि की जरूरत है। क्योंकि इसमें पूरा हार्ड रॉक पोर्शन है। यह मांग पूरी स्पिति घाटी और जिला किन्नौर की है और यह बहुत बड़ी डिमांड है कि इस सड़क को बी0आर0ओ0 के अधीन किया जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सड़क को बी0आर0ओ0 के अधीन करने के लिए कोई पत्राचार कर रही है? क्या केन्द्रीय नेतृत्व के संज्ञान में इस सड़क को लाया गया है? मैं इसकी अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहती हूं।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा विधायक महोदय ने कहा है कि लियो बाईपास सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह लाहौल स्पिति को जोड़ने का कार्य करती है और कई बार हमारे विभाग ने बी0आर0ओ0 के साथ पत्राचार भी किया है। मगर इस बारे में उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। तदुपरांत अधिशासी अभियंता काजा मंडल के पत्र दिनांक 29.02.2024 द्वारा कमान अधिकारी 108 आर0सी0सी0 समधों को राज्य सरकार के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए आग्रह किया गया है तथा इस बारे में सीमा सड़क संगठन बी0आर0ओ0 के क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराते हुए लियो बाइपास सड़क को सीमा सड़क संगठन के क्षेत्राधिकार के हस्तांतरण की प्रकिया प्रारंभ की जा चुकी है। अधिशासी अभियंता लोक

12.03.2025/1150/बी.एस./डी.सी./-2

निर्माण विभाग, काजा के पत्र, 08.11.2024 के द्वारा कमान अधिकारी 108 आर0सी0सी0 समधों को पुनः लियो बाइपास सड़क को उपरोक्त निर्णय के अनुसार हस्तांतरण करने हेतु आग्रह किया गया है जिसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं विधायक महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि we will rake this issue. Rather take up this issue at the highest level और मैं जब अगली बार दिल्ली जाऊंगा तो केन्द्रीय रक्षा मंत्री जी से इस विषय को ले करके अवश्य बात करूंगा और भी अन्य जनजातीय क्षेत्रों के इस प्रकार के इश्यू हैं जिनमें हम लोक निर्माण की सड़कों को जो खास करके सीमा क्षेत्र में है, **उनको बी0आर0ओ0 को सौंपना चाहते हैं। इस विषय पर हम डिटेज जानकारी बी0आर0ओ0 को निकटतम भविष्य में देने का पूरा प्रयास करेंगे।**

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

12.03.2025/1155/DT/DC-1

प्रश्न संख्या : 2395

डॉ. हंस राज : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है, वह विस्तार से दी गई है। जैसा मैंन कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा के दौरान भी कहा था कि जो हमारी चम्बा-तीसा की मुख्य सड़क है, उसमें एक तो हमने कोटी से बढ़ो और बढ़ों से लेकर कफाड़ी इसमें सी.आई.आर.एफ. के अंतर्गत क्या डी.पी.आर्ज. बनाकर दिल्ली भेजी गई हैं या सिर्फ प्रपोजल भेजी गई हैं? क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे की इसको पूरा करेंगे? इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री से ये भी पूछना चाहता हूं कि जो हमारे गांव छूटे हुए है, उनमें एक तो जो मंगली सड़क का उन्नयन हुआ था उसमें 6 से 7 करोड़ रुपये के लगभग खर्च किया गया था। मंत्री जी ने कहा कि उसमें

ब्लैक स्पॉटस नहीं हैं; उसमें बहुत सारे ब्लैक स्पोटस हैं। यहां तक कि बाइक-स्कूटर को भी पास देने के लिए स्पेस नहीं है।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मेरे क्षेत्र मे कुछ एक पंचायत पूरी तरह से छुटी हैं। इसमें विभाग ने कहा कि जैसे गिफ्ट-डीड नहीं हुई है, फारेस्ट क्लीयरेंस का मसला है, जैसा मैं कल कह रहा था कि हमने 246 सड़कें बनाई हैं। अभी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इनमें जियो-टेगिंग हो रही है, उसमें लगभग 32 सड़कों की जियो-टेगिंग हुई है। क्या आप माननीय सदन को और चुराह की जनता को ये आश्वासन देंगे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो गांव छुटे हुए हैं जिनमें गवाड़ी, चन्डरू, देहरा-पिसोगा, सिंड-कठवाड़, अखरोट-दांडू इसकें अतिरिक्त करमूंड, अलवास, चीनकरोड़ और बड़ंतर का हमारा क्षेत्र जहां पर सड़क की व्यवस्था ही नहीं है। बंजल-टेपा हमारी ऐसी पंचायत है जो बिल्कुल भी सड़क के साथ नहीं जुड़ी है, वहां पर हमनें टेंपररी व्यवस्था की थी। क्या आप सदन को आश्वासन देंगे कि इन स्ड़कों का काम निकटतम भविष्य में शुरू करवायेंगे? एक तो 87 करोड़ रुपये की प्रपोजल सी.आर.आई.एफ. के अंतर्गत गई है वह पैसा बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो मैंने मंगली वाला जिक्र किया यह भी और दुसरा जो मैंने यह गांव गिनवाएं हैं, इनके लिए क्या आप मुझे आश्वासन देंगे कि इनको आप विभाग के साथ कंवर्जन करके या बैठकर एक सिंगल विंडो बनाने का उपाय करें। जो मैंने बंजल, बशोग और चंडरू का जिक्र किया है वहां 11 किलोमीटर दूर से लोगों को पीठ पर उठाकर नीचे लाया जाता है।

12.03.2025/1155/DT/DC-2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो चरणों में यह सवाल पूछा है। प्रश्न के पहले भाग में इन्होंने ब्लैक स्पॉट के बारे में जानकारी लेने का विषय रखा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्लैक स्पॉट अधिकृत करवाये जाते थे। लेकिन वर्तमान में सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें परिवहन और लोक निर्माण विभाग के पास यह कंवर्जेंस अमाउंट रखा जाता है जिससे इस अमाउंट को बांटा जाता है। इसमें अलग-अलग ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया

जाता है और फिर उसके डिपोजिट का पैसा लोक निर्माण विभाग को मिलता है जिस पर आगे कार्य किया जाता है। इसमें पूरी जानकारी माननीय विधायक जी को दी गई है कि जिला, चम्बा में 12 ब्लैक स्पॉटस चिन्हित किये गये हैं जिसमें भरमौर, चम्बा, डलहौजी, तीसा, चुवाड़ी और सलूनी डिवीजन हैं, जो लिखित उत्तर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, वह स्वतः वर्णित है कि कहां-कहां पर इसमें कार्य हुआ है। ब्लैक स्पॉटस के लिए हमें जहां-जहां के लिए भी पैसा मिलेगा, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।

प्रश्न के दूसरे भाग में जिनमें इनके द्वारा पर्टिकुलर रोड्ज के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए निवेदन किया है, जिसमें मुख्य रूप से चड़ा से ज्योड़ी सड़क है, इसमें फोरेस्ट से संबंधित क्लीयरेंस पेडिंग है। इसके बारे में मैंने आज सुबह ही अधिकारियों के साथ चर्चा की है। केवल यही सड़कें नहीं बल्कि हम पूरे प्रदेश का डाटा बना रहे हैं और विशेषतौर में इसमें एफ.सी.ए. के केसिज हैं। ऐसे केसिज किस-किस स्तर पर रुके हुए हैं, उसको हम अपने विभाग की ओर से एक्सिपडाइट करने का प्रयास करेंगे। जब विधायक प्राथमिकता की बैठक हुई थी, उसमें ये कहा है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में इसे एक्सिपडाइट करने के लिए ये कमेटी हर जिला में बनाई गई है, लेकिन हम इसको करेंगे। बाकि दो अन्य सड़कें चरड़ा से महुआ तक और चरड़ा से प्रभा, इन दोनों मामलों में गिफ्ट डीउ अवेटिड है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से केवल इन्हीं सड़कों के लिए नहीं परंतु सभी सड़कों के लिए यह बात माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग आने वाले समय में जहां पर हमें गिफ्ट डीड नहीं मिली है, उन सड़कों के ऊपर कार्य नहीं करेगा।

श्री एन.जी. द्वारा जारी...

12.03.2025/1200/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 2395 ..... जारी

लोक निर्माण मंत्री.....जारी

उन सड़कों पर कार्य नहीं करेगी। मेरा इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि जहां पर भी गिफ्ट डीड की समस्या आ रही है, हमारे माननीय विधायक (डॉ0 हंस राज जी की ओर इशारा करते हुए) बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और 'कंधार नरेश' हैं, ये अपने क्षेत्र के लोगों पर अपना पूरा प्रभाव बना कर हमारे विभाग को गिफ्ट डीड दिलवा सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप (माननीय सदस्य, डॉ0 हंस राज जी की ओर देखते हुए) सभी से चर्चा करें और हमारे विभाग को संबंधित जमीनों की गिफ्ट डीड उपलब्ध करवाएं और हमारा विभाग आपके क्षेत्र में सड़कों को बनवा कर देगा। वह चाहे हम सी0आर0एफ0 में बनाएं, चाहे पी0एम0जी0एस0वाई0-4 में बनाएं, हम सभी मिलकर काम करेंगे लेकिन उसके लिए जमीनों को लोक निर्माण विभाग के नाम पर करना पड़ेगा। लोक निर्माण के ऊपर लगभग 1200 करोड़ रुपये की देनदारियां लम्बित हैं। हमें यह कॉल लेनी पड़ेगी कि आने वाले समय में सड़कें बनानी हैं या लोगों को कंपनसेशन देना है, that call in the larger interest of the state has to be taken.और उस पर हम बिलकुल क्लियर हैं कि हम तभी सड़कें बनाएंगे जब विभाग के नाम पर सभी गिफ्ट डीड्स हो जाएंगी। धन्यवाद।

प्रश्न काल समाप्त

12.03.2025/1200/एच.के.-एन.जी./2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अधिकृत माननीय उप-मुख्य मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

उप-मुख्य मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न कागजातों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन एवं औद्यानिकीय उपज विपणन बोर्ड (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा जारी लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित); और

ii. बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, शिमला का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित)।

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

12.03.2025/1200/एच.के.-एन.जी./3

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2024-25), कल्याण समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

1. समिति का अग्रेत्तर कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना" से सम्बन्धित समिति के 37वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) पर बने 14वें कार्रवाई प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के प्राप्त विभागीय उत्तरों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

3. समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "पोषण अभियान योजना" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

12.03.2025/1200/एच.के.-एन.जी./4

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा

अध्यक्ष : अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, Shri Lokender Kumarji was the last speaker and in the list Shri Ranbir Singh Nikka is the left out and the so is the case in the Congress list also Mr. Sudershan Singh Babloois the left out. The revised list from the Parliamentary Affairs Minister and revised list

from Shri Sukh Ram Chaudhary proposes now to a new name. I am inviting Shri ...(Interruption) Shri Jai Ram Thakurji, you want to say something regarding this? Leader of the Opposition Shri Jai Ram Thakur who wants to intervene the speaker.

12.03.2025/1200/एच.के.-एन.जी./5

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। इस माननीय सदन में जो जनप्रतिनिधि चुन करके पहुंचते हैं और उनके विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के रूप में लम्बे समय से एक व्यवस्था बनाई गई है। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के माध्यम से धनराशि जारी करने के लिए हम सभी विधायक अपने-अपने जिलाधीष (उपायुक्त) महोदय को चिट्ठियां भेज रहे हैं। उपायुक्त महोदय उन चिट्ठियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करके विभागों को तो भेज रहे हैं लेकिन उसके लिए पैसा जारी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार के निर्देश हैं कि 10 हज़ार रुपये से ज्यादा के बिलों को ट्रेजरी से पास न किया जाए। हमारे इस बजट सत्र के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा और नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले हमारी विधायक क्षेत्रीय विकास निधि की जो धनराशि लम्बित पड़ी है, जिसे हमने खर्च नहीं किया है.....

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

12.03.2025/1205/HK-PB/-1

व्यवस्था का प्रश्न जारी...

श्री जय राम जी जारी...

उसे खर्च करने में भी कठिनाई आ रही है। हमने चिट्ठियां सैंक्शन करके डिप्टी कमीश्नर्ज़ को भेज दी है और डिप्टी कमीश्नर्ज़ ने आगे चिट्ठियां कनवे कर दी हैं और उन्होंने भी चिट्ठियां सैंक्शन करके कनवे कर दीं हैं लेकिन पैसा रीलीज़ नहीं किया जा रहा है। यहां पर मसला ट्रेज़री का है और यह चिंता का विषय है। अगर ये पैसा नहीं जाता है तो अगला वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। हमारी विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैंडिंग पैसा जो खर्च नहीं हुआ है क्या उसे लैप्स माना जाएगा? हम सब लोगों के लिए यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में नहीं है। मुझे मालूम नहीं है वह कहां है, भाभी जी को मालूम होगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह बहुत गम्भीर विषय है, पिछले कल भी हमने सदन में कहा कि वृद्धा पेंशन और हैंडीकेप पेंशन नहीं दी जा रही है। हमारी ऐच्छिक निधि की भी वही स्थिति है। वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और नया वित्तीय वर्ष शुरू होने को है। विधायकों की जो ऐच्छिक निधि और विधायक क्षेत्र विकास निधि है उसका क्या होगा? सही मायने में यह एक मात्र निधि विधायक के हाथ में है। जहां अपने क्षेत्र के विकास के लिए जहां उनको आवश्यकता अनुभव होती है वह तुरंत पैसा सैंक्शन करते हैं और पैसा सैंक्शन होने के बाद तुरंत सैंक्शन कनवे करने के बाद कार्य शुरू होना चाहिए परंतु इसमें विलम्ब हो रहा है साल समाप्त होने जा रहा है परंतु पैसा नहीं है। पंचायत प्रधान बोलते हैं कि सैंक्शन आ गई है परंतु पैस नहीं है। यह हमाने लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। हम समझ सकते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि एक मात्र जरिया रह गया है विकास के लिए विधायक के पास और सरकार ने उसको भी बंद कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हम सब के लिए पीड़ादायक परिस्थिति है। सरकार इसमें आदेश करे कि जो विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में ऐच्छिक निधि और विधायक क्षेत्र विकास निधि को स्वीकृति दे रहे हैं उसे तुरंत प्रभाव से ट्रेज़री से रीलीज़ करवाया जाए।

12.03.2025/1205/HK-PB/-2

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी आप बोलें।

उप-मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदेश मुख्य मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रहे हैं और इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। हम इनका सम्मान करते हैं। हम इनकी कही किसी भी बात को टाल नहीं सकते। इनकी सूचना के लिए मैं कहना चाहता हूं कि विधायाक निधि ट्रेज़री द्वारा रीलीज़ कर दी गई है।...(व्यवधान) आप पता करवा सकते हैं (विपक्ष के सदसयों को बोलते हुए।)...(व्यवधान)।

Speaker: No interruption please.

उप-मुख्य मंत्रीः (श्री जय राम ठाकुर जी ओर देखते हुए) ऐसा नहीं है। देखिए आप...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री...(व्यवधान) एक मिनट सुनिए। माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय इस सदन को विश्वास दिला रहे हैं कि जो यह बोल रहे हैं वह सही और दुरुस्त है तथा वह इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। अगर सही नहीं होगा तो there are other methods also for which he can be proceeded. Hon'ble Deputy Chief Minister, you can speak.

उप-मुख्य मंत्री : देखिए हमने नेता प्रतिपक्ष की बात सुनी तो अब आप हमारी बात भी सुनिए। नेता प्रतिपक्ष कुछ घण्टे लेट होते हैं। पीछे इन्होंने कहा कि एच0आर0टी0सी0 की पेंशन नहीं दी गई और मेरे पास अभी मोबाइल में है जिस दिन हमारी रैली थी उससे...(व्यवधान) देखिए विपक्ष से हम झूठ नहीं बोल सकते। हम सार्वजनिक मंच या सदन में हकीकत ही कहेंगे। **मैं साभी सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अपनी विधायक निधि जितनी भी बची है उसे अवेल करें, पैसा जारी कर दें।**

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1210/a.p./y.k./01

उप-मुख्य मंत्री द्वारा जारी .....

जो भी आपकी ऐच्छिक निधि है उस पैसे को आप जारी कर दें। और आपका पैसा यहां से रिलीज कर दिया गया है। हमारी अभी विधायक दल की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ एक

सदस्यों ने यह बात ध्यान में लाई थी। इसका फैसला भी उसी दिन कर दिया गया था कि हम पैसा रिलीज कर रहे हैं, इसलिए यह पैसा रिलीज कर दिया गया है और चीफ सैक्रेटरी साहब ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसमें यह दोहराय नहीं है कि आपने बोला और हम in anticipation यहां बात कर रहे हैं।

दूसरा, यह आपने बोला की कुछ तबको को पेंशन नहीं दी गई है। लेकिन आप विधवा और सहारा को पेंशन जाती हैं। उनके लिए भी फैसला हो चुका है कि और उनके खातों में बहुत जल्दी पेंशन डाल दी जाएंगी क्योंकि 17 मार्च, 2025 को बजट पेश होने वाला है फिर 20-21 मार्च, 2025 के आसपास तो ट्रेजरी भी बंद होने शुरू हो जाती है। इसलिए यह सारी चीजें हमारे ध्यानार्थ हैं और प्रदेश सरकार के हालात जैसा आप दिखा रहे हैं वैसे स्थिति सरकार की नहीं हैं। सभी को उनके ड्यूज अदा किये जाएंगे।

अध्यक्ष : अब मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो आगे चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आखिरी सदस्य बोले हैं। As per the revising list, now I am inviting the Hon'ble Member Shri Ram Kumar from the Congress Party to initiate the debate.

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है उसके लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान सरकार ने ढ़ाई वर्ष के कार्यकाल पूरा करने के उपरांत लगभग 10 गारंटियों में से छः गारंटियां पूर्ण की है। और सबसे बड़ा काम जो चुनावों के वक्त कहा गया था कि हम पहली केबिनेट में कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 लागू करेंगे। हमारी सरकार ने पहली केबिनेट में यह गारंटी पूर्ण की थी। युवाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने केलिए अनेकों प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो पिछली सरकार के समय में खराब छोड़ी गई थी। उसके सुधार में दिन-प्रतिदिन ...(व्यवधान)

12.03.2025/1210/AP/YK/02

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी। Hon'ble Deputy Chief Minister wants to intervene in relation to the earlier issue.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष जी ने अभी मसला उठाया था उसमें जो मुझे सूचना मिली है Social Security Pension Scheme के 360 करोड़ रुपये को रीलिज कर दिया गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार की बिगड़ी हुई वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए हिमाचल सरकार दिन रात आत्मनिर्भर हिमाचल, प्रदेश को आर्थिक रुप से सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत 3,517 ग्राम पंचायतों में से 2 लाख 8 हज़ार के अधिक अभ्यासशील किसानों व 2 लाख 87 हजार प्रशिक्षित किसानों को कवर किया गया है। मक्का व गेहूं की फसलों को क्रमशः 30 व 40 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य एम0एस0पी0 प्रदान किया जा रहा है। जिसके लिए पूरे देश भर के किसान दिल्ली में लगभग एक वर्ष तक ढेरा जमाएं बैठे। और लगभग 700 किसानों ने अपनी जान की आहुतियां दीं। जहां तक मैं अपने राज्य की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने फसलों के लिए एम0एस0पी0 को जारी किया है। राज्य में केसर व हींग की खेती को बढावा देने के लिए कृषि से सम्पन्नता योजना प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

12.03.20205/1215 /AT/YK /.1

श्री राम कुमार जारी.....

राज्य में कैंसर व हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि से सम्पन्नता योजना प्रदेश कर द्वारा आरंभ की गई है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 60324 हींग के पौधे 10583 किलोग्राम केसरकंद वितरित प्रदेश कर द्वारा की वित्त किए गए हैं वर्तमान में राज्य के चुनिंदा क्षेत्रों में हींग तथा केसर की खेती शुरू कर रही है जिससे हमारे किसान

समृद्ध होंगे किसानों की आय में वृद्धि होगी भारत सरकार के व खोखले दावे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के किसानों की आय को दुगनी कर रहे हैं पर वह तो नहीं हुआ लेकिन हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार यह महत्वपूर्ण कदम उठा रही है हिमाचल प्रदेश में गोपाल योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के गौ-सेवा आयोग द्वारा लगभग 12 करोड़ 50 लख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है

(**श्री मोहन लाल** ब्राक्टा सभापति **पदासीन हुए**)

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रूपये की धनराशि गौ सेवा आयोग के माध्यम से गौ सदनों के निर्माण के लिए प्रदेश कार्यरत जारी कर दी गई है इसके अतिरिक्त कार्य मछली फार्म नालागढ़ में करसर्कुलेटरी जल कृषि प्रणाली में पेगेषियस और रूपचंद मछली के पालन को सफलतापूर्ण आरंभ कर दिया गया है तथा मुख्यमंत्री कार्य मत्स्य पालन योजना के तहत 80% अनुदान के साथ निजी क्षेत्र में 18 हैक्टैयर में नए तालाबों का निर्माण किया गया है वर्तमान सरकार ने इस कार्य में लगभग 80% सब्सिडी बेरोजगार युवकों के लिए जारी करने का फैसला किया है जो लोग इस तरह का मत्स्यपालन का काम करेंगे वर्तमान सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 96 लाख 64 हजार कार्य दिवस सृजित का 6 लाख 36हजार परिवारों को रोजगार प्रदान किया है वह योजना जो मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी और अब की भारत सरकार इस योजना को बंद करने के तत्पर है इसमें लगभग 34% रोजगार महिलाओं को दिया गया है मनरेगा के तहत 138913 कार्य पूरे कर चुके हैं 1252 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं राज्य में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ₹ 300 मजदूरी दर अधिसूचित

12.03.20205/1215 /AT/YK /.2

कर हमारी सरकार द्वारा राज्य के गैर जनजाति क्षेत्र में अपनी निधि से 64 रुपए अधिक मजदूरी प्रदान की जा रही है इसके अलावा इस वर्ष में 216 करोड़ पर अतिरिक्त राशि मनरेगा कामगारों को दी जाएगी समाज के कमजोर वर्गों के प्रति हिमाचल सरकार प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा सुख आश्रय योजना प्रारंभ की गई थी

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ ली पहले सचिवालय जाने की बजाय वह सुख श्रेय जहां पर वह बहुत बच्चे रहते थे उनसे जाकर मिले और इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया इस उद्देश्य से वर्ष 2024 में 4242 लाभार्थियों के पक्ष में 11 करोड़ 70 लाख रुपये की राजधन राशी प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है । वर्तमान सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2024 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय क्रमशः500 ,400 और ₹300 की बढ़ोतरी प्रदेश की गई है सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री को हर वक्त चिंता रहती है कमजोर वर्गों को जो सबसे नीचे और सबसे पिछली लाइन में खड़े हैं उनको कैसे सिदृढ़ करना है उसके लिए मान्य मुख्यमंत्री हमेशा योजना बनाने के वार में सोचते रहते हैं सभी अनुसूचित रोजगारों के काम करने वाले कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 1 अप्रैल 2024 से बढ़कर ₹400 प्रतिदिन किया गया है दो वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन की जो प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई ,उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं । बर्ष 2024 की रीपोट जो जनवरी, 2025 में जारी हुई उसमें हिमाचल प्रदेश के बच्चों को पढ़ने के सर्थ में सवसे आगे माना गया है इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम पीछे जाना शुरू हो गया था

(श्री कुलदीप सिंह पठानिया अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1220/md/ag/1

श्री राम कुमार जारी----

इस रिपोर्ट के अधिकांश मापदडों में हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा में देश भर में श्रेष्ठ राज्य रहा है। इसके लिए मैं दोबारा माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई दूंगा और प्रदेश सरकार द्वारा SMC और आई0टी0 शिक्षकों के मानदेय में 1900 रुपये और अंशकालीन जल वाहक मानदेय में 600 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए विशेष पैकेज जो माननीय मुख्य मंत्री व हमारी प्रदेश सरकार ने दिया है। इसमें विभिन्न स्तरों की

प्रतिस्प्रधाओं के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बढ़ोतरी करके प्रारंभिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाले खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन तथा अन्य खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाले खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाले खेलों में भाग लेने पर सम्मान रुप से 500 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। प्रदेश के खेल होस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तथा 400 रुपये की डाइट मनी प्रदेश सरकार द्वारा दा जा रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत आरक्षण की योजना के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान 65 खिलाड़ियों को विभिन्न बोर्डों, निगमों आदि में नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त खेल कोटे में 20 खेलों को शामिल करने का मामला विचाराधीन है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 के दौरान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यहां पर उस दौरान माननीय पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने बहुत बडा उदाहरण दिया था। हमारे नालागढ़ क्षेत्र से संबंधित श्री अजय ठाकुर जी जिनको डी0एस0पी0 के पद पर तैनात किया गया। वे कबड्डी में अन्तर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। मैंने और माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा जी ने जब उनकी नौकरी के लिए इस केस को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया तो अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले हमारे सब-इंस्पैक्टर से ऊपर किसी भी खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी गई थी। यह कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा फैसला था कि श्री अजय ठाकुर जैसे गोल्ड मेडलिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को डी0एस0पी0 के पद पर तैनात किया गया जिससे कि दूसरे खिलाड़ियों का मनोबल भी ऊंचा हुआ। आज हमारे नालागढ़ क्षेत्र के हजारों खिलाड़ी सुबह रोड्स पर होते हैं और अपनी खेल स्प्रधाओं की तैयारी कर रहे हैं।

12.03.2025/1220/md/ag/2

प्रदेश में एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, निराश्रित महिलाओं व विकलांग माता-पिता के बच्चों के लिए इन्दिरा गांधी सुख शिक्षा योजना आरंभ की गई है। वर्तमान वर्ष में इस योजना के अंतर्गत अब तक एक करोड़ पचास लाख रुपये व्यय कर 18 वर्ष की आयु तक के लगभग 15000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 5065 लाभार्थियों की पहचान इस योजना के अंतर्गत की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो चिट्टा अपना पांव पसार रहा है उसके लिए प्रदेश सरकार ने एक बहुत बडा फैसला लिया है। अभी हाल में जो हमारे एस0पी0, बद्दी तैनात हुए हैं उन्होंने ऐसे लगभग 10 मामले चिट्टे के पकड़े हैं और उसमें सौ ग्राम तक का चिट्टा छापा मारकर पकड़ा है। जिसके लिए मैं एस0पी0 को बधाई दूंगा और उनको धन्यवाद भी करूंगा। हमारी सरकार ने नशे से संग्रहित सम्पत्तियों व अपराधियों को अक्षम करने के लिए वर्ष 2024 में एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अवैध व्यापार के माध्यम से अर्जित की गई 11 करोड़ रुपये की अर्जित की गई चल व अचल सम्पत्तियों को जब्त किया है। जांच क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से फौरेंसिक प्रयोगशालाओं के उन्नयन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने नार्कोटिक्स और संगठित अपराध के एक विशेष कार्यबल एस0टी0एफ0 को मंजूरी देकर हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। नार्कोटिक्स और मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध की तरफ विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक संसाधनों, शक्तियों और स्वायत्तता के साथ एक समर्पित इकाई होगी। जिला सिरमौर के दाड़ो-देवरिया पंचायत के कोटला-बड़ोग में 5.34 करोड़ रुपये की लागत से नशा मुक्ति का पुनर्वास केंद्र विकसित किया जा रहा है जिसमें एक साथ सौ बैड की सुविधा होगी। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि हमारा नालागढ़-बद्दी में बोर्डर एरिया पड़ता है। इस एरिया में बहुत सारे प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा वहां पर भी एक ऐसा नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाए। मैं इसके लिए माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जितने भी अस्पताल हैं उसमें चाहे जिला सोलन का होस्पिटल, बद्दी या नालागढ़ का अस्पताल है उनमें एक-एक वॉर्ड उन लोगों के लिए आरक्षित किया जाए

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

12.03.2025/1225/केएस/एजी/1

श्री राम कुमार जारी---

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि हमारे जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वह सोलन का है, बद्दी का है या नालागढ़ का अस्पताल है उनमें जो लोग नशे में संलिप्त हैं, एक-एक वार्ड उनके उपचार के लिए आरक्षित किया जाए। मेरा मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि जैसा जिला सिरमौर में नशामुक्ति केंद्र बन रहा है, उसी तरह नालागढ़ और बद्दी में भी बनाया जाए।

मुख्य मंत्री विधवा एकल निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना, 2025 प्रदेश द्वारा अधिसूचित कर दी गई है। 50 हजार से कम के आवास निर्माण हेतु 3 लाख रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और हिमाचल प्रदेश की ऐसी पहली सरकार है जिसने यह काम किया है।

हिमाचल प्रदेश में भू-जोत अधिनियम, 1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए बेटों के बराबर अधिकार इस सरकार ने दिया है। वर्तमान सरकार प्राथमिक स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में 01 अप्रैल, 2024 से वृद्धि कर उन्हें 24.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क रख-रखाव योजना (MMSRY) के अंतर्गत 29.12 करोड़ रुपये की लागत से 2,743 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों में 6.97 लाख वर्गमीटर का पैचवर्क पूर्ण किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब पिछले वर्ष आपदा आई तो मेरे क्षेत्र में पहाड़ी एरिया की लगभग सभी सड़कें खराब हो चुकी थीं। विशेष आग्रह पर इन्होंने लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये भी कुछ दिन पहले हमारे कसौली डिविज़न और नालागढ़ डिविज़न के लिए जारी किए हैं जिससे हमारे दून क्षेत्र की खराब सड़कों पर पैचवर्क और रिपेयर वर्क होगा।

लोक निर्माण कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने निविदा प्रकाशन समय अवधि को 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने का जो ऐतिहासिक फैसला किया है, इसके लिए भी मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करुंगा। क्योंकि इससे पहले 14 दिन से 1 महीने

तक टेंडर ही नहीं खुल पाते थे। इससे हमारे कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता रहेगी।

प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं में 2 लाख 26 हजार 462 जल नमूनों और फील्ड टैस्ट किट के माध्यम से 94 हजार 173 जल नमूनों का परीक्षण किया गया। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी एक प्रयोगशाला हमारे क्षेत्र में भी लगाई जाए क्योंकि हमारे क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता बहुत ही खराब हो चुकी है और हमारे पास हार्ड वाटर है। हमारा जो सीवर सिस्टम वहां पर चल रहा है, वह खुले तौर पर नालों में जा रहा है। रॉकी स्ट्रेटा होने के कारण हमारे एरिया में सीपेज सिस्टम से हमारा ग्राउंड वाटर खराब हो चुका है। मैं चाहूंगा कि जो हमारी घनौली-रोपड़ वाली नहर है, उसमें हमारा 15 प्रतिशत शेयर है। वहां से नहर के माध्यम से हमारे नालागढ़ और बद्दी एरिया के लिए, जैसा कि उप-मुख्य मंत्रीजी, आपने अपने बद्दी टूअर पर भी कहा था कि नहर के माध्यम से हमारे एरिया की जमीन को सिंचित करने के लिए एक खाका तैयार किया जाए, डी0पी0आर0 बनाई जाए क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते हज़ारों ट्यूबवैलों के माध्यम से दिन-रात हमारे एरिया के पानी का दोहन हो रहा है और हज़ारों ट्यूबवैल चल रहे हैं जिससे हमारा ग्राउंड वाटर लैवल बहुत ही कम हो चुका है इसलिए आने वाले समय में इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे एरिया में एयर क्वालिटी भी बहुत ही खराब हो चुकी है। उद्योग विभाग के डायरैक्टर भी यहां पर बैठे हैं। वहां औद्योगिक क्षेत्र के जो सीवर सिस्टम बने हुए हैं, वे फट चुके हैं, लीक हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। उनके निपटारे के लिए विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत है। या तो उनको खाली करवाएं या उनको सी.टी.पी. प्लांट से विशेष पाइप लाइन जोड़कर करें। हमारे बद्दी के नाले में सीवर सिस्टम का पूरा पानी खुलेआम खोला जा रहा है जिससे हमारे लोगों की सेहत खराब हो चुकी है। वर्ष 2012 से 2017 के कार्यकाल के दौरान मैंने यहां एक प्रश्न उठाया था। उस समय माननीय कौल सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे। हमारे लगभग 278 लोग उस समय कैंसर से पीड़ित थे जिनकी मृत्यु हुई थी। उस समय एक सर्वे हुआ जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर पाया गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

श्री राम कुमार------ जारी

उसके बारे में एक सर्वे हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार का कैंसर पाया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां की एयर क्वालिटी और ग्राउंड वॉटर की विशेष तौर पर टैस्टिंग करके प्रदेश सरकार इस मामले का समाधान करे।

पिछले वर्ष भारी वर्षा व प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मेरे एरिया के साही, शिल्ल, सुनाणी, दाड़वा और कुठाड़ क्षेत्र में उस दौरान लोगों को बहुत हानि पहुंची थी। पहले जहां मकान गिरने पर डेढ़ लाख रुपये की राशि मिलती थी, उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा तीन लाख रुपये की घोषणा करके वह राशि दी गई। यही नहीं, जिनके घर गिरे उनके पास अगर जमीन नहीं है तो प्रदेश सरकार द्वारा उनको दो-दो, तीन-तीन बिस्वा जमीन आबंटित करने का फैसला लिया गया जिसके लिए में माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां पर अभी माननीय राजस्व मंत्री जी नहीं बैठे हैं। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी हमारे साही क्षेत्र के दौरे पर आए थे। वहां पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन सौ प्रतिशत तबाह होकर ढांक बन चुकी हैं। उस एरिया में टमाटर और मटर की खेती होती थी मगर अब वह जमीन खेती लायक नहीं बची है। प्रदेश सरकार ने जैसे ऐलान किया था कि जिन लोगों के घर गिर गए उनको जमीन दी जाएगी तो उसी तर्ज़ पर मैं यह चाहूंगा कि जिनकी कृषि योग्य भूमि खराब होकर ढांक बन चुकी हैं उनके लिए भी हमारी सरकार कोई नीति बनाए। हमारे जिन लोगों की जमीन प्राकृतिक आपदा में तबाह होकर ढांक बन गई हैं उसके बदले उनको उसी एरिया में खेती योग्य जमीन देने हेतु प्रदेश सरकार कैबिनेट में फैसला लेकर इस संदर्भ में अमलीजामा पहनाने की कोशिश करे ताकि उन लोगों के साथ न्याय हो सके।

प्रदेश सरकार ने ईको टूरिज्म पॉलिसी लाई है जिसके माध्यम से हमारे राज्य के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है। स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसैसिंग के अंतर्गत 19 परियोजनाएं अनुमोदित कर 3.29 करोड़ रुपये की स्वरोज़गार अनुदान राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल विंडो प्रणाली के तहत 149

औद्योगिक प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे बनलगी क्षेत्र में लगभग

12.03.2025/1230/AV/AS/2

200 बीघा जमीन अभी बिना आबंटन और बिना प्लॉटबंदी के पड़ी है। उस जमीन के लिए कोई रोड भी नहीं था। मेरी वहां पर निजी भूमि है और मैंने उसके लिए रोड बना दी है। इस जमीन के प्लॉट काटने से भी प्रदेश सरकार को आमदन होगी और हमारे नौजवान साथी वहां पर टमाटर और दूसरे प्रोडक्ट्स की यूनिट्स लगाना चाहते हैं। हमारे बरोटीवाल-बनलगी-स्पाटू रोड की डी0पी0आर0 तैयार हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि उस डी0पी0आर0 के लिए एक चरण में लगभग 25 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये की राशि देकर उस रोड को चौड़ा करने का काम किया जाए ताकि हमारा बनलगी औद्योगिक क्षेत्र उभर सके और वहां के हमारे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिल सके।

हमारी सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न वाहन श्रेणियों के परमिट जारी किए हैं। इससे लगभग 46000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे पहले जो यहां पर बाहर से ट्रांसपोर्टर अपनी बसें और ट्रक चलाते हैं, उनके द्वारा लाखों रुपये की चोरी की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी ट्रक यूनियन के जो पिछले पांच साल चक्कर लगवाए क्योंकि उनकी एक महीने की अवधि बढ़ा दी जाती थी और उस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने और माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा ने जैसे ही प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इन लोगों की पेनल्टीज माफ की जाएं और उनके टैक्स के लिए समय-सीमा में बढ़ोतरी की जाए जिसके लिए अभी 31 मार्च तक की डेट बढ़ाई है जोकि तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे लाखों रुपये की जो डैड मनी पड़ी थी, वह भी प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा।

टी सी द्वारा जारी

12.03.2028/1235/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री राम कुमार जारी

इसके अतिरिक्त, निजी बस सेवाओं से संबंधित करों को भी व्यवस्थित किया गया है, जिससे प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस वर्ष 9.81 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह राशि पहले करदाताओं के पास निष्क्रिय पड़ी हुई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर रही है जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे।

प्रदेश सरकार प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रोपवे का निर्माण कर रही है। इस संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया था कि काली झूंडा के अटल कुंज क्षेत्र में एक कॉलेज की स्थापना की जाए। यह क्षेत्र कसौली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां लगभग 100 से 200 बीघा भूमि हिमुडा की उपलब्ध है। मेरा प्रस्ताव यह था कि इस भूमि का उचित उपयोग करते हुए कसौली तक रोपवे का निर्माण किया जाए। यदि प्रदेश सरकार इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करे तो इससे कसौली में शनिवार व रविवार को चंडीगढ़, हरियाणा और अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों से पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। यदि यह रोपवे विकसित किया जाता है, तो इससे प्रदेश सरकार को जी0एस0टी0 और अन्य करों के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोपवे परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके। ... (व्यवधान) प्रदेश सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए उठाए हैं जो पिछली भाजपा सरकार ने नहीं उठाए थे और वे कार्य इनको करने चाहिए थे। जैसा यहां माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार की आर्थिकी में ये एक बहुत बड़ा होल करके गए हैं और वर्तमान सरकार को उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। परंतु निकट भविष्य में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

Speaker : I would like to inform the Hon'ble House that the Hon'ble Former Speaker Shri R.R. Shastriji is also present in the VIP Gallery and former

Hon'ble MLA Shri Govind Ramji is also present and they are witnessing the proceedings of this august House. Now, I will request Shri Satpal Singh Sattiji to take part in deliberations.

12.03.2028/1235/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

अब मैं माननीय सतपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे चर्चा में भाग लें।

सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2025 को यहां प्रस्तुत किए गए अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, वह सरकार द्वारा लिखित रूप में तैयार किया गया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल महोदय वही बातें सदन में रखते हैं जो सरकार और कैबिनेट द्वारा स्वीकृत होती हैं। जब मैंने इस अभिभाषण को ध्यान से पढ़ा तो इसके पहले पृष्ठ के क्रम संख्याः 3 पर सरकार ने कहा है कि सभी गारंटियां पूरी कर दी गई हैं। इन्होंने इस अभिभाषण के पहले पेज से ही राज्यपाल महोदय से झूठ बुलाना शुरू कर दिया। हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

दूसरा, सरकार ने दावा किया है कि हमने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपये देने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस प्रक्रिया की कोई स्पष्टता नहीं है। जिस समय चुनाव हो रहे थे तो उस समय वर्तमान उप-मुख्य मंत्री जी ने जनसभाओं में स्वयं कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, दिसंबर के अंत तक पहली कैबिनेट बैठक में यह योजना लागू कर दी जाएगी और प्रत्येक महिला के खाते में 1,500 रुपये डाले दिए जाएंगे। उस समय कोई शर्त या चरणबद्ध प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था और कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक चुनाव लड़ रहे थे वे यही बात लोगों व विशेष रूप से महिलाओं को कह रहे थे। लेकिन अब जब यह योजना लागू करने की बात आई तो नई शर्तें जोड़ दी गई हैं।

तीसरा, सरकार ने गाय व भैंस के दूध खरीद में ऐतिहासिक वृद्धि और गोबर खरीद का जिक्र किया है।

एन0एस0 द्वारा.... जारी

12-03-2025/1240/ns-dc/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती------ जारी

आप लोगों ने कहा था कि हम उसको 100 रुपये किलो खरीदेंगे। आपने उस समय ऐतिहासिक वृद्धि नहीं कहा था कि हम ऐतिहासिक वृद्धि करेंगे। आपने 100 रुपये बोला था लेकिन 100 रुपये नहीं लिया। आपने यह दूसरा (***) इस अभिभाषण के अंदर प्रस्तुत करवाया। यहां पर वरिष्ठ कृषि मंत्री जी बैठे हैं और इन्होंने संगठन के बारे में भी कहा है कि कांग्रेस का संगठन पैरालाइज्ड हो गया है। इनके सुपुत्र श्री नीरज भारती जी ने भी बोला है कि सरकार में किसी की नहीं सुनी जा रही है और किसी के काम नहीं हो रहे हैं। सच बोलने की आदत किसी-किसी को होती है और अंतिम समय में सच ही निकलता है क्योंकि सरकार का भी अंत ही चल रहा है। जब संगठन ही पैरालाइज्ड हो गया तो सरकार भी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। इस उम्र में आदमी बिल्कुल सच बोलता है और यह दम चौधरी साहब ही दिखा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब गोबर खरीदना इनके गले की फांस बन गया है। सत्ता पक्ष बोलता है कि हमने गोबर खरीद लिया है। आपने यह नहीं बोला था कि हम लोग केंचुआ खाद खरीदेंगे। आप बताओ, अगर ऐसा आपके घोषणा-पत्र में है। मैं पिछले कल किसी की शादी में गया था। आप मेरे साथ बसदेहड़ा में चलें क्योंकि वहां पर गोबर की 50 ट्रालियां पड़ी हुई हैं। मैं वहां पर मंत्री साहब का बुक्का लेकर स्वागत करूंगा। वहां पर आपको गोबर टोकरियों या डिब्बों में भरना है तो भरें। उस समय हम भी हैरान हुए कि क्या गोबर खरीदने का काम सरकार का होता है? क्या सरकार गोबर खरीदने के लिए बनी है? लेकिन आपने ऐसा बोला है इसलिए हम आपको बार-बार बोलते हैं। हम भी बोल सकते थे कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। हमें पता है कि नहीं दिया जाएगा। इतना

पैसा नहीं है। ...(व्यवधान) दिल्ली में शुरुआत करने के लिए बोल दिया है। उन्होंने आप लोगों की तरह नहीं कहा था कि सारी महिलाओं को देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इन्होंने यहां पर राज्यपाल महोदय से झूठा अभिभाषण पढ़वाया है। उनके अभिभाषण को मीडिया पर दबाब डाल कर इस तरह से प्रस्तुत किया और उनके नाम पर इतनी बड़ी न्यूज लगा दी। हिमाचल प्रदेश में शायद यह पहली बार हुआ है। यह Breach of Trust है। यह उनके साथ विश्वासघात है क्योंकि राज्यपाल महोदय को अभिभाषण पढ़ना होता है। लेकिन उनके नाम पर न्यूज नहीं लगती है और आपने ऐसा किया है।

12-03-2025/1240/ns-dc/2

अध्यक्ष महोदय, इस दस्तावेज के पेज नम्बर-14 पैरा संख्या : 34 में शिक्षा के बारे में बोला गया है। शिक्षा मंत्री जी भले मानस आदमी है और शिक्षा में भी इनके विभाग ने स्कूली बच्चों की वर्दी में एक बड़ा कारनामा किया है। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के कार्यकाल में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने नाहन में आ करके हिमाचल प्रदेश के 9.50 लाख बच्चों को वर्दी देने की शुरुआत की थी, जिसे अटल वर्दी योजना के नाम से जाना जाता है। आपने उसमें भी लोगों को जाति के ऊपर बांट दिया। आपने कुछ लोगों की वर्दियां उसमें बंद कर दी हैं। आपने वर्दियां बंद करने के बाद उनको ड्राफ्ट भेजा कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की वर्दी लगाई जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने पैसा ही नहीं देना है तो मैं कैसा कपड़ा डालूं, इसको आप कैसे तय कर सकते हैं? आपने वहां पर 6 तरह की वर्दियां भेजी हैं और जो वहां पर लैक्चरर या टी0जी0टी0 लगे हुए हैं उन्होंने वे मुझे दिखाई हैं। अध्यक्ष महोदय, आज गरीब परिवारों के बच्चे ही ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसा कम है वही सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। आपने उन बच्चों के बीच भी अंतर कर दिया। आपने यह भी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। मैं शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और इसके लिए श्री राम कुमार जी ने बड़े विस्तार से बोला कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से अलग- अलग जगहों के ऊपर आप लोगों को जाना अलाउड नहीं है। माननीय मुकेश जी उप-मुख्य मंत्री हैं और मेरे जिला से संबंध रखते हैं। ये हरोली से स्वां नदी के पार ही घूमते रहते हैं। क्या वहां पर कोई लक्ष्मण रेखा लगी हुई है कि अगर वहां से बाहर निकलेंगे तो जल जाएंगे? आप हमारे क्षेत्र में आ करके देखें कि

8.44 करोड़ रुपये से श्री जय राम ठाकुर जी के समय से दिया हुआ सीनियर सैकंडरी स्कूल (ब्यॉज), ऊना की बिल्डिंग बन कर तैयार है। लेकिन उसके उद्घाटन के लिए किसी के पास समय नहीं है। वहां पर दो शिफ्टों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सुबह भी अध्यापक आते हैं और दोपहर के बाद भी अध्यापक आते हैं। हमने ऊना कॉलेज के अंदर 14 करोड़ रुपये से एक मल्टी पर्पज़ कम्पलैक्स बनाया है। वहां पर 5 तारीख को शिक्षा मंत्री जी ने एनुअल फंक्शन में जाना था लेकिन इनका कार्यक्रम रद्द हो गया। शायद बिल्डिंग का उद्घाटन था इसलिए रद्द हो गया। इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हो सका।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

12.03.2025/1245/RKS/डीसी-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती... जारी

इसके साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सनोली के लिए श्री जय राम ठाकुर जी के समय 45 लाख रुपये जारी किए गए थे। उस पाठशाला के चार कमरे बनकर तैयार हैं लेकिन जो थोड़ी-बहुत राशि और चाहिए उसके न मिलने के कारण शेष कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यह तो मैं सिर्फ अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र, ऊना की ही बात कर रहा हूं। आप सब लोग यह गुणगान कर रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर उठे हैं लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह स्तर किस तरह ऊपर ऊठा है? अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है। क्योंकि जो कम धनराशि से काम होने हैं वे भी अभी तक पूरी तरह से रुके हुए हैं। स्कूल के बच्चे परेशान हैं और कहीं ऐसा न हो जाए कि वे बिल्डिंगों के ताले तोड़कर अंदर घुस जाएं। अगर ऐसा ही रहा तो यह कार्रवाई हमें भी करनी पड़ सकती है। हमने विद्यार्थी जीवन में इस तरह की कई कार्रवाइयां की हैं। हम सोचते हैं कि आप भवनों का उद्घाटन करने आएं और हम आपका स्वागत करें। लेकिन आज 10-10, 12-12 करोड़ रुपये की लागत से बने भवन भी बिना उपयोग के ही क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ठेकेदार उन भवनों में दो-तीन बार रंग-रोबन कर चुके हैं कि इन भवनों का उद्घाटन होगा लेकिन बाद में वह कार्यक्रम रद्द हो जाता है। यह आपके शिक्षा क्षेत्र की स्थिति है। अभिभाषण के पेज नं0 25 के पैरा संख्याः 66 में सड़कों का जिक्र किया गया है। श्री जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में जो लोग बाहर से आते थे वे सड़कों की स्थिति को देखकर हैरान हो जाते थे। वे कहते थे

कि यहां बहुत अच्छे रोड बने हैं और चारों ओर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के पैच वर्क के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा है। पांच साल पहले महतपुर से संतोखगढ़ सड़क के लिए टारिंग हेतु 90 लाख रुपये व्यय किए गए थे लेकिन आज उस सड़क पर काफी गड्ढे पड़े हुए हैं। उस रोड का पैच वर्क भी नहीं हो पा रहा है। उस रोड में बहुत ज्यादा धूल उड़ती है क्योंकि वहां पर इंडियन ऑयल का टर्मिनल भी स्थापित है। वहां से हर रोज 400 ट्रक गुजरते हैं। इतनी आवाजाही से वहां काफी मिट्टी उड़ती है और लोगों को अपने घरों के बाहर कपड़े सुखाना मुश्किल हो गये हैं। आपने जो पैरा संख्याः 66 में सड़कों के बारे में जिक्र किया है, मैं उसकी स्थिति आपके ध्यान में ला रहा हूं। इसके आगे पेज नं0-27 के पैरा संख्याः 71 में जल शक्ति विभाग की गतिविधियों के बारे में जिक्र किया गया है। मुकेश भाई के क्षेत्र में इनका विभाग क्या कर रहा है उसका मुझे पता नहीं

12.03.2025/1245/RKS/डीसी-2

लेकिन मेरे क्षेत्र में अगर किसी ने प्राइवेट नलका भी लगाना हो तो उसे यह कहा जाता है कि हमारे पास पाइपें नहीं हैं। माननीय उप-मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि पूर्व मंत्री ने पाइपों का बहुत ज्यादा ढेर लगा दिया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है? जब आपके पास पेयजल और सिंचाई योजनाओं के लिए पाइपें उपलब्ध नहीं हैं तो फिर आप इन योजनाओं को आगे कैसे कार्यान्वित करेंगे? पहले गगरेट में फ्लड प्रोटेक्शन का एक्सिअन बैठता था लेकिन अब उसका चार्ज जल शक्ति विभाग के एक्सिअन को दे दिया गया है। जल शक्ति विभाग का एक्सिअन कहता है कि मेरे पास फ्लड प्रोटेक्शन में कुछ भी नहीं है। पिछली साल इस हैड में पूरे जिला के लिए 95 लाख रुपये राशि स्वीकृत हुए थे लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इस राशि से पूरे जिले में कैसे काम होगा? हमारे जिला में स्वां नदी के साथ-साथ 74 और ट्रिब्यूटरिज खड्डे हैं। जब दो साल पहले बाढ़ आई थी तो इन खड्डों के किनारे टूट गए थे। आज वहां पर पुलियां बनाने की आवश्यकता है। हमने इसके लिए अनेकों बार प्रस्ताव भेजे लेकिन हमें यह जवाब मिलता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर उप-मुख्य मंत्री के विभाग में ही पैसे की कमी है तो फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि अन्य विभागों की क्या स्थिति होगी। आपने जो राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पढ़ाया उसके पेज नं0-29 में यह दर्शाया गया है कि हमने राजस्व विभाग में बहुत अच्छा सुधार किया है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में लोग पिछले दो

सालों से निशानदेही करवाना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक उन लोगों की निशानदेही नहीं हो पा रही है। मैं राजस्व मंत्री को उन लोगों के नाम भी उपलब्ध करवा दूंगा। मैंने स्वयं इस विषय पर पटवारी-कानूनगो से बात की लेकिन इसके बावजूद भी वहां निशानदेही नहीं हो रही है। ऐसा न होने से वहां के लोगों के बीच लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं और उनके केस कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ केस पुलिस स्टेशन में भी पंजीकृत हैं। राजस्व विभाग का ग्राउंड वर्क निशानदेही ही है लेकिन विभाग द्वारा यह कार्य भी सही से नहीं हो पा रहा है। हमारे क्षेत्र में बदोबस्त का कार्य चला हुआ है। यह काम उस तहसीलदार को सौंपा गया है जो 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। माननीय राजस्व मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं है लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा कि उस तहसीलदार की 30 नवम्बर, 2024 को रिटायरमेंट थी। रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा उसे एक वर्ष की एक्सटेंशन दे दी गई। मैं जानना चाहूंगा कि यह सरकार की क्या मजबूरी थी?

12.03.2025/1245/RKS/डीसी-3

उसे लालसिंगी गांव के बंदोबस्त का कार्य सौंपा गया। आप कल्पना कीजिए कि लालसिंगी गांव किसका है। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी इस बात को जानते हैं लेकिन ये कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी कोई नहीं सुनता।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

12.03.2025/1250/बी.एस./एच.के./-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

और इन्हें वहां पर आने भी नहीं देते है इसलिए वहां पर जो बिल्डिंग्ज बनी हैं उनका उद्घाटन नहीं कर सकते। लेकिन आप उप-मुख्य मंत्री हैं आप तो किसी भी विभाग में कार्य का उद्घाटन कर सकते हैं। मैंने यहां पर पांच-सात विभागों के नाम लिए हैं, बाकी अन्य विभागों में इन्होंने कितना झूठ बोला है। उनमें तो बहुत कुछ था और बहुत कुछ है।

इसी तरह से पेज नम्बर 32 क्रम संख्याः 83, 84 और 85 इसमें स्वास्थ्य विभाग का गुणगान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे सहयोगी रहे हैं, हम लोगों ने इकट्ठे ही

एम0ए0, एम0फिल0, पी0एच0डी0 में एडमिशन लिया था। यह अलग बात है कि ये पढ़ गए इन्होंने यह कर दिया और हम थोड़ा रह गए। परंतु एम0ए0, एम0फिल0 हमारी इकट्ठी है। यह आदणीय कर्नल साहब को पूरा याद है और ये बहुत अच्छे आदमी हैं। यहां पर बोला गया कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 174 प्रकार के लैब टैस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 397 मैडिसन, सर्जरी, इस्त्री रोग, बाल चिकित्सा, एनस्थीसियलोजी व रेडियोलॉजी तथा अन्य 06 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर मैडिकल स्टॉफ और आधुनिक नवीनतम एम0आर0आई0 सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। यह कमाल हो गया कृपया मुझे बता दो कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कहां यह कारनामा हुआ है? वहां में गूगल धूम ले करके उसकी पूजा तो कर लूं। कृपया, बताइए कि आदरणीय बबलू जी के क्षेत्र में कहां है, आदरणीय मुकेश जी के क्षेत्र में कहां है, और आदरणीय राकेश कालिया जी तो चले गए। आप हमारे पांच जनों के बारे में बता दीजिए? क्योंकि हमारा प्लेन एरिया है। वहां तो आपने यह काम कर ही दिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय कर्नल साहब से यह लिखवाया गया होगा? इनको तो पता ही नहीं होगा कि मेरे से इतना गलत बुलवा दिया होगा। आप फौजी और इस सदन के सबसे वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि विभाग की परपोजल है और इस कार्य को करने की इच्छा है परंतु इच्छा तो आसमान से तारे तोड़ने की भी होती है लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि हमने आसमान से तारे तोड़ दिए हैं। मेरे आर0एच0 में आपका रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ऊना में इसे कहां लगा दिया? वहां पर एम0आर0आई0 नहीं है, वहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। मेरा कहना है कि यहां पर झूठ बोला गया है।

12.03.2025/1250/बी.एस./एच.के./-2

उसके साथ-साथ हमारे पेज नंबर 35 क्रम संख्याः 90 इसमें पर्यावरण के बारे में बोला गया है। हमने धर्मपुर में जा करके देखा पर्यावरण, वहां पर्यावरण की क्या हालत हुई है? वहां पर लकड़ी के खुले मैदानों पर ट्रकों-के-ट्रक काट करके लगाए हुए हैं। जब हम थोड़ा नजदीक ऊतरे तो हमने देखा कि जे0सी0बी0 से गड्ढे खोद कर उनके अंदर लकड़ी दबाई हुई है। जब हमने लोगों से पूछा कि ये गड्ढे किस लिए खोदे हुए हैं? तो कहने लगे कि

जब बीजेपी और अखबारों के अंदर मीडिया ने इसे उठाया तो लकड़ी को इन गड्ढों में छुपा दिया गया। मैं, आदरणीय सुख राम चौधरी जी और आदरणीय बलबीर वर्मा जी तीनों वहां पर गए। वहां पर एक नदी चलती है, शायद बयास नदी वहां जाती है। उसकी जहां-जहां पहाड़ियां हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां पर ट्रकों-के-ट्रक ढांक से गिरा दिए गए हैं, ताकि लोगों को यह लकड़ी दिखाई न दे सके और आप यहां पर पर्यावरण की बात कर रहे हैं? जंगल काट दिए गए है। जिला ऊना में 25 ट्रक लकड़ी के पकड़े गए, 2-4-5 तो पकड़े ही जाते हैं। परंतु जिस दिन 25 ट्रक पकड़े गए उस दिन अध्यक्ष महोदय अखबार के अंदर आया, मैं मैडम कमलेश जी को ब्लेम नहीं करता। मेरे पास इसकी कटिंग पड़ी है, मैं आपको दे दूंगा, इसे मैंने संभाल करके रखा है। उसमें आया कि वे सारे-के-सारे ट्रक देहरा से आए थे और सबके कागजात ठीक पाए गए। उसके बाद 25 ट्रक छोड़ दिए गए। अगर छोड़ना ही था तो फिर उन्हें पकड़ा क्यों गया; और इसकी न्यूज क्यों लगी? हमारे वनगढ़ के अंदर जंगल काटे गए, वहां पर पूरे का पूरा वनगढ़ का जंगल काट दिया गया है। देहरा डिवीजन के अंदर, आपके कुटलैहड़ चुनाव क्षेत्र के अंदर, गगरेट के अंदर ट्रकों के ट्रक पकड़े जाते हैं और पंजाब, होशियारपुर की फैक्ट्री वाले का बयान आता है कि मेरे पास तो रोज 200-200 जीपें आती हैं। इसके अलावा टाटा, 407 ट्रक भी पकड़े गए। अब इतने जंगल काटे जा रहे हैं और हम लोग राज्यपाल महोदय से ऐसा बुलवा रहे हैं कि हम लोग पर्यावरण मामले में बहुत संजीदा दृष्टि से कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगला विषय पेज न0 41 के ऊपर खनन का विषय आता है। खनन के बारे में इनका कहना है कि हमने बहुत खनन रोग दिया है। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि, आपको भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी। जब उप-मुख्य मंत्री जी ही नहीं जा सकते तो आपको भी कौन अनुमति देगा? आप एक बार वहां पर पहले गए थे, आपने कहा कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

12.03.2025/1255/डीटी/AS-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती... जारी

वह कर देंगे लेकिन मुझे भी प्रशासन व उनकी ओर से फोन आया कि आज मीटिंग है और मैं वहां जाना भी चाहता था लेकिन मैं कहीं बिजी था। अगर आप स्वयं जाकर देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी के समय वहां पर स्वां नदी और 74 ट्रिब्यूटरिज खड्डों का चैनलाइजेशन लगभग 1200 करोड़ रुपये से किया गया है उसको पंजाब की जे.सी.बी., पोकलेन ने तबाह कर दिया है। परसों रात भी स्लोघन में पोकलेन पकड़ी गई थी, उनके नंबर उखाड़ दिए गए थे, जो इंजन के ऊपर नंबर होता है वह भी घिस दिया था। मुझे रात को 11:30 बजे लोगों का फोन आया कि हम इन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं और आप पुलिस वालों को बोल दो ताकि वे उन्हें कहीं रात को ही न छोड़ दें। एक लड़का तो भाग गया है और वहां से 10-12 टिप्पर भी भाग गए इसलिए हम इस जे.सी.बी. को खुद चला करके लेकर जा रहे हैं। आप संतोषगढ़ जाकर देखो वहां क्या स्थिति है। किस तरह से वहां पर खनन हो रहा है और इस खनन को कौन कर रहे हैं इस बात को सारे लोग जानते हैं। उप-मुख्य मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं। यह भी बयान देते हैं की खनन रुकना चाहिए। ये कहते हैं कि हम खनन माफिया और चिट्टे वालों को नहीं मानेंगे लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो सारी बातें खनन के बारे में की जा रही है यह इन लोगों ने माननीय गवर्नर महोदय से झूठ बुलाई है। अगर खनन नीति ठीक ढंग से लागू हो तो मैं यह मान सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश को खनन से ही 5 या 7 सौ करोड़ पर आ सकते हैं। आपने बताया कि 124 करोड़ के लगभग खनन से आता है लेकिन हम इसे सही से लागू करें तो लगभग 5-7 सौ करोड़ रुपये आएंगे। हम मानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से खनन होना चाहिए इसमें कौन इनकार करता है लेकिन जमीन के अंदर से पानी निकाल दिया और वहां पर कुआं टाइप बन गए हैं। अब इसको कौन रोकें? पिछले कल ही एक चंबा से यह घटना आ रही थी की कोई कशमले की जड़े उखाड़ करके ले जा रहा था। जब उस व्यक्ति को रोका गया तो गार्ड को गाड़ी के पीछे बंद करके घसीटा गया। वह बड़ी मुश्किल से छूटा तब उसने जा करके FIR दर्ज की। हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं लेकिन जब हम कशमले की जड़े ही उखाड़ देंगे तो फिर क्या होगा? यह पौधा पहाड़ में झाड़ीनुमा होता है। इन जड़ों की मेडिशनल वैल्यू है। अगर इन पौधों को उखाड़ दें तो पूरे पहाड़ स्खलित हो जाते हैं। जो पहाड़ भू-स्खलित हुए हैं उसमें इन चीजों का कहीं न कहीं रोल

था। हम लोग उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से पेज नंबर 42 सीरियल नंबर 105 पर एक शाबाशी अपने आप को ही दी गई है

12.03.2025/1255/डीटी/AS-2

कि हमने अलग-अलग नगर परिषद बनाए। ऊना, बद्दी और माननीय मुख्य मंत्री के एरिया हमीरपुर में भी बनाए गए। मुझे यह समझ नहीं आता कि इसमें निर्णय कौन लेता है? अधिकारी यहां पर बैठे नहीं है। श्री विक्रमादित्य जी यहां बैठे हैं। अब यह निर्णय लिया कि एक साल पहले पुरानी नगर परिषदें भंग कर दी गई और कहा गया कि अब इनका कोई अधिकार नहीं है। वहां पर कमिश्नर लगा दिए गए। आज जो लोग डवलपमेंट के काम करवाने और डैथ सर्टिफिकेट के काम से जाते हैं तो नगर परिषद वाले कहते हैं कि ये संस्था भंग हो गई है और कमिश्नर कहते हैं कि हमें इसके लिए पावर ही नहीं है। आपको एक साल पहले नगर परिषदें भंग करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपने जो इसमें 14-14 पंचायतें इंवोल्व की आपने उन पंचायतों का अधिकार भी ले लिया। वहां पर न कोई प्रधान, उप- प्रधान, न बी.डी.सी. और न जिला परिषद के पदाधिकारी हैं। आप वहां पर कमिनर लगा सकते थे। आप यह कह सकते थे कि 31 अक्तूबर तक अपने फंड क्लॉज करो और डवलपमेंट के काम भी करो। 31 अक्तूबर के बाद कॉड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कमिश्नर अपने वोटर लिस्ट का कार्य करता है। वह और रिजर्वेशन तय करता है। आपने सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तबाह कर दिया है। फिर आप लोग बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली पार्टी के लोग हैं। मैं इन चीजों में डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो यह इंगित कर रहा हूं कि गवर्नर महोदय से इसकी शाबाशी ली गई बल्कि उल्टा उन गांवों में आज कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं गांव के लोग हमारे साथ लड़ रहे हैं, प्रधानों के साथ लड़ रहे हैं, प्रधान हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई साहब हमारी संस्था को भंग कर दिया गया है और हमारे पास कोई पावर नहीं है। मेरे क्षेत्र की 14 पंचायतें हैं जिसमें 8 मेरी और 6 कुटलैहड़ चुनाव क्षेत्र की हैं। कानून व्यवस्था के बारे में 51 नंबर पेज के सीरियल नंबर 127 पर बोला गया है। माननीय मुख्यमं त्री जी यहां बैठे हैं और इनकी कांस्टीट्यूएंसी के अंदर ही लैंड ऑर्डर के बारे में बोला गया है। पेज नं0 127 में यह दर्शाया गया है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसमें लिखा है कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही है। इससे बड़ा

झूठा कोई हो ही नहीं सकता है जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया। आज ही ऊना जिला के अंदर गोंदपुर बुला एरिया जो मुझे लगता है कि मुकेश जी के एरिया में पड़ता है वहां पिछले कल 5,20000 रुपये आदमी की आंखों में मिर्ची डाल करके ले गए। यह अखबार के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ है।

श्री एन.जी.द्वारा जारी

12.03.2025/1300/वाई.के.-एन.जी./1

श्री सतपाल सिंह सत्ती.....जारी

मैंने चम्बा के मामले के बारे में अभी बताया है कि किस प्रकार से टैक्सी के पीछे बेचारे गार्ड को घसीटा गया है। आपने इस अभिभाषण में जिन विशेषताओं के संदर्भ में लिखा है वह बिलकुल गलत है। आपकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो आपने इसमें नहीं लिखी हैं और आपको जरूर लिखनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय, यह तो आप ही बताएंगे कि क्या इस चर्चा के बाद इस अभिभाषण में कुछ जोड़ा जा सकता है या नहीं? अगर बाद में भी कुछ जुड़ सकता होगा तो सरकार को इसमें अपनी कुछ विशेषताओं को अवश्य जोड़ना चाहिए। मैं दो मिनट में इनकी उन विशेषताओं के बारे में बता दूंगा। सरकार ने ट्रेजरी को बंद कर दिया जोकि इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इस अभिभाषण में इसके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? (पंजाबी भाषा में कहा गया) 'न लेंदा भुले, न देंदा भुले, न तेनु मिलने, न मेनु आणे, गल मुक गई, ट्रेजरी बंद'। कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा है। कर्मचारियों को 10 हज़ार रुपये से ज्यादा का जी0पी0एफ0 नहीं मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले शादियों का दौर था और कुछ कर्मचारियों ने हमें कहा कि हमने अपने बच्चों की शादी करनी है लेकिन हम अपने जी0पी0एफ0 से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप तो इस सरकार के बनने पर बहुत डांस कर रहे थे, क्या अब आपकी तसल्ली हो गई? (पंजाबी भाषा में कहा गया) 'असी तां सिधि-सिधि गल करने वाले बंदे हैं। साढ़े कोल ज्यादा लम्बा चौड़ा हिसाब

नहीं है।' मैंने उनसे कहा कि अभी तो तीन साल और हैं इसलिए अभी तो और भी नज़ारे देखने को मिलेंगे। (पंजाबी भाषा में कहा गया) 'ओ मेनु कैंदा कि जाउगी नी बिच, मैंने कहा कि देखदे आं थोड़ा सा जोर लाके कि अक्तूबर-नवम्बर तक कुछ बनदा की नहीं'। उसने मुझे कहा कि बहुत बुरी हालत है क्योंकि हमारा अपना पैसा ही हमें नहीं मिल रहा है इसलिए इस सरकार को जल्दी से वापिस भेजो। ...(व्यवधान) मैं यह सब सच बता रहा हूं क्योंकि शादियों के दौर में मुझे दो लोगों का फोन आया था। ...(व्यवधान)

12.03.2025/1300/वाई.के.-एन.जी./2

माननीय श्री संजय अवस्थी जी, आपके पास तो बिजनस करने के कारण पैसा होगा लेकिन लोगों के पास नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सोलन में रह कर कुछ आड़त आदि का कार्य करते रहे हैं।...(व्यवधान) आपके मित्र, माननीय श्री गोविन्द राम शर्मा जी आज यहां पर विशिष्ठ अतिथि दीर्घा में बैठे हुए हैं और आपने इनके विधान सभा क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। आप उस विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं तो अच्छी बात है। आपके (माननीय सदस्य, श्री संजय अवस्थी जी की ओर देखते हुए) पास पैसा हो सकता है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। यह सरकार की विशेषता थी और इस अभिभाषण में इसे लिखना चाहिए था। ...(घण्टी)... अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार लगभग 1400 संस्थान बंद करना भी सरकार की बहुत बड़ी विशेषता व उपलब्धि थी जिसे इस अभिभाषण में लिखना चाहिए था। सरकार को राज्यपाल महोदय से बुलवाना चाहिए था कि हम वह गबरू जवान हैं जिन्होंने लगभग 1400 संस्थानों को एकमुश्त बंद कर दिया है। जनता भाड़ में जाए। आपको इसमें यह सब भी लिखना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी बोलते थे कि मुझे एक भी बच्चे के लिए स्कूल खोलना पड़ेगा तो मैं जरूर खोलूंगा। लेकिन आज कांग्रेस सरकार बोलती है कि हमने लगभग 1400

संस्थानों को बंद कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ठीक थे या आज आपकी सरकार ठीक कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हिमकेयर का पैसा नहीं दिया जा रहा है। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। अपंग, वृद्ध, विधवा आदि लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल रही है। अभी माननीय उप-मुख्य मंत्री, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा है कि 360 करोड़ रुपये डाल दिए गए हैं। यह पैसा तो तब डाला गया है क्योंकि सत्र चला हुआ है और यदि सत्र न चला होता तो यह पैसा अगले तीन माह तक भी नहीं डलना था।आपको शायद मालूम नहीं होगा कि प्रदेश में अनेक वृद्ध महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए पेंशन का इंतजार करती हैं। इस अभिभाषण में सरकार को लिखना चाहिए था कि हम वे लोग हैं जिन्होंने गरीब लोगों की पेंशन रोकी हुई है।

12.03.2025/1300/वाई.के.-एन.जी./3

Speaker : Conclude please.

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ऐच्छिक निधि और विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना का पैसा भी अभी आया है। यदि हम लोग नहीं बोलते तो यह पैसा भी नहीं आना था। प्रधान लोग तो हमारे पास कागज लेकर आ जाते हैं कि यह हमें क्यों दिया गया है, क्योंकि इस सैंक्शन का पैसा तो आ नहीं रहा है। मैंने डी0सी0 से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि चिट्ठी तो आई थी लेकिन पैसा नहीं आया। मैंने उन्हें कहा कि यदि आप पहले ही यह बात बता देते तो हम इन्हें चिट्ठी लिखकर ही नहीं देते और इसके कारण हमारी भी जलालत हो गई। लोगों को लग रहा है कि हम उन्हें झूठे लैटर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि आपके पास भी इस प्रकार का फोन आया होगा लेकिन आप उसके बारे में यहां पर नहीं बता सकते क्योंकि आप बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम तो ये सब बता सकते हैं क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। अभी बीच में माननीय

श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने बोला भी था कि हमारे विधायक दल में यह विषय आया था कि इसे जल्दी जारी करो। इसका मतलब यह हुआ कि यह विषय सरकार के ध्यान में आया था लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय श्री जय राम ठाकुर जी अपनी सरकार के समय में 'सहारा योजना' के नाम से एक बहुत अच्छी योजना लेकर आए थे। इस योजना के तहत बैड पर पड़े हुए लोग, कैंसर व किडनी आदि रोगों से ग्रसित लोग या जो लोग न ठीक हो पा रहे हैं और न ही चल-फिर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने 3000 रुपये की पेंशन का प्रावधान किया था। आज ऐसे लगभग 35 हज़ार लोगों को सहारा योजना की पेंशन नहीं मिल रही है। आप कल्पना करो कि उन लोगों का गुजारा कैसे हो रहा होगा? यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे इस अभिभाषण में लिखना चाहिए था।

Speaker : Conclude please.

12.03.2025/1300/वाई.के.-एन.जी./4

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सरकार ने रजिस्ट्री व गिफ्ड डीड करने के लिए 1000 गुणा पैसा बढ़ा दिया है जिसे इस अभिभाषण में लिखना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक प्रश्न लगाया था और जिसका उत्तर आया कि सरकार के पास शगुन योजना के अंतर्गत 1436 केस लम्बित पड़े हुए हैं और इसका पैसा देना बकाया है। इसी प्रकार मुख्य मंत्री कन्या दान योजना के तहत भी 297 केसिस लम्बित पड़े हैं और उसका पैसा भी सरकार ने नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो कन्याओं को भी पैसा नहीं दे रही है। कन्याओं के लिए तो कोई भी आदमी बड़े-से-बड़ा काम कर देता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी से आग्रह करता हूं कि ये बेटियां भी आपकी बेटियों की तरह ही हैं। मुझे उम्मीद है कि देहरा विधान सभा क्षेत्र की माननीय सदस्या, श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी को कहेंगी

कि प्रदेश की कन्याओं का पैसा तो मत रोकिए। (माननीय सदस्या, श्रीमती कमलेश ठाकुर जी की ओर देखते हुए) आज ही बोल देना जी, कल सुबह इनका पैसा जारी करवा देना।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

12.03.2025/1305/YK-PB/-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

इसके लिए सभी 1700 बेटियां आपकी तारीफ करेंगी। इसी तरह से हमने देखा है कि 30,000 करोड़ रुपये का लोन इन्होंने पिछले दो वर्षों में लिया है और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, लेकिन यह धनराशि आखिर कहां गई? इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है। आपको यह भी उस अभिभाषण में लिखना चाहिए था। आप इन चीजों से क्यों डर रहे हैं? इसी आधार पर तो हम चुनाव लड़ेंगे और जगह-जगह इसके पोस्टर लगांएगे। हम सरकार को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। आगामी चुनाव में 60 और 8 के बीच में लड़ाई होगी और जो परिस्थितियां वर्ष 1990 में बनी थीं, वही फिर से देखने को मिलेगी। श्री मुकेश जी को इस पुराने घटनाक्रम की जानकारी है क्योंकि उस समय ये पत्रकार थे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट कहना है कि जो भी बातें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा कही गई हैं, वे सत्य नहीं हैं, भले ही इनको सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा हो। हम इस बात का समर्थन नहीं कर सकते और इस यह दस्तावेज़ आने वाले समय में इन्हें भारी पड़ेगा।

इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि किसी भी विषय को बिना जांचे-परखे स्वीकार न करें क्योंकि विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है और उसे उचित तरीके से निभाया जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्य अच्छे भी हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों से यह सब देखा नहीं जा रहा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप भी इनसे संवाद करें और उचित मार्गदर्शन दें ताकि शासन व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ सके। इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री, कुछ कहना चाहते हैं।

12.03.2025/1305/YK-PB/-2

कृषि मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दे रहे हैं। लेकिन इस सदन में विपक्ष में बैठे सभी सत्यवादी लोग हैं और पक्ष की ओर से जो भी इस अभिभाषण का समर्थन कर रहे हैं, वे सभी झूठे हैं। यदि आपकी *** अच्छी होती तो आप इस तरफ होते। जनता ने आपको जवाब तो दे दिया है। ...(व्यवधान) पहले मुझे बोलने दीजिए। मेरी बात सुनो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमने जो घोषणा पत्र जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है, वह कोई एक दिन में लागू होने वाला दस्तावेज नहीं है। हमारी सरकार को पांच वर्ष का मेन्डेट मिला है और उसी के अनुरूप योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार ने ओवरड्राफ्टिंग के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया और बड़े पैमाने पर धनराशि का दुरुपयोग किया। इसको सुधारने में समय लगेगा। हमारा घोषणा पत्र पांच वर्षों के लिए है और इसमें किए गए वायदों को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

यदि हमने अपने वादे पूरे किए तो जनता हमें अगले चुनाव में फिर से समर्थन देगी। पिछली बार भी आपने बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर भी जनता ने हमारी सरकार को दोबारा बहुतमत देकर हमें सत्ता में पहुंचाया। हमारी पहली सरकारी कर्मचारियों के साथ किए गए अन्याय को दूर करने का था। यह हमारा संकल्प था। हमने इसे अपनी प्राथमिकता मानते हुए पहले कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने का निर्णय लिया। आज हमारे सरकारी कर्मचारी पुरानी पैंशन का लाभ उठा रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। जब हमने इस निर्णय को लागू किया, तब विपक्ष के लोगों ने कहा कि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा लेकिन इससे आपको क्या तकलीफ है। यदि बोझ पड़ा है तो वह हमारी सरकार के ऊपर पड़ा है और उसको हम देखेंगे। ...(व्यवधान) आपने जो

आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगाए हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। विपक्ष के सदस्य कोविड के समय में नोटंकी करते थे। पिछले विधान सभा सत्र के दौरान धर्मशाला में ये दूध के मटके लेकर आए थे। श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

12.03.2025/1310/a.p./a.g./01

कृषि मंत्री द्वारा जारी .....

अध्यक्ष महोदय, हमने कहा था कि हमारी सरकार दो रूपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगे और हमने यह कहा कि हम कच्चा नहीं बल्कि जैविक खाद लेगे जिसको हमने तीन रूपये खरीदा है। आज 1 करोड़ 40 लाख की लागत से हमने जैविक खाद को खरीदा है। हमने जो ब्लॉक वाइज़ लोग आइडेंटिफाई किये है जिनमें कुछ लोग कहते है कि वह देने को तैयार है और कुछ ने इंकार किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1 करोड 40 की जैविक खाद हमने खरीदी है। कृषि प्रारूप जो डिफॉर्म हो गये थें उनको हमने दोबारा प्रयोग कर रहें हैं और कुछ को हम बागवानों को बेच भी रहे हैं और हम खुले बाज़ार में भी 5 व 10 रुपये का बैग हम बेचेगें और आपके सामने रिजल्ट आएंगे।

दूसरी आपने बात कही,मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने 15 रुपये दूध के बढ़ाए है, चाहे व गाय का हो या फिर भैस का जिसको हमने 55 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाया। अब हम इसको एक दिन में तो 100 रुपये प्रति लीटर तक कर नहीं सकते। अभी हमार ड़गवार में 250 करोड़ रूपये का प्लांट लग रहा है जिसको हम तेजी से तैयार करने जा रहे हैं। आज लोगों के हमे टेलीफ़ोन आते है आप जा कर दत्तनगर के प्लांट को देखिए जिसका हमने नवीनीकरण किया है। जिस फैसले से उस क्षेत्र में दूध की कीमतें बढ़ी है और जिससे हमारे आर्थिक हालात अच्छे हुए हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमार 5 साल का मेंडेट है हम अपनी सारी गारंटियों को पूरा करेगे और हमारी सरकार द्वारा फिर से सत्ता आएंगी यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय श्री जय राम ठाकुर जी।

12.03.2025/1310/A.P/A.G/02

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी उम्र के हिसाब से हम आपका सम्मान करते हैं और मै यह भी जानता हूं कि उम्र अपना असर छोड़ देती है। इन्हें नहीं मालूम पड़ रहा था कि वह क्या बोल रहे थें। सबसे पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री द्वारा जो *** शब्द का किया प्रयोग किया गया उसको कार्यवाही से निकाला जाएं । यह एक अपमानजनक शब्द है उचित नहीं है इसको कार्यवाही में रखने लायक नहीं है और इसकी आपसे उम्मीद भी नहीं थीं।

दूसरी बात अधयक्ष महोदय, इसमें हमारे माननीय सदस्य श्री सत्तपाल सत्ती जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने यह कहा कि आपकी सरकार ने झूठ बोला है, हम आपकी बात को मानने को तैयार है कि आपकी सरकार 5 साल के लिए बनी है और आप अपनी गारंटियां 5 साल में पूरा करेगें। आपने जो नहीं किया उसका भी जिक्र आपने कर दिया। जो स्वास्थ्य के लिए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएं है अगर मैं आप में से ही पुछू,कितने विधायक जानते है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में कौन सा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान चिन्हित हुआ है और वहां सी0टी0 सकैन, एक्स रे, एम0आर0आइ0 लग गया है या वहां पर रेडियोलॉजिस्ट बैठ गया है बता सकता है कोई क्या? हम भी एक विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमको मालूम नहीं है नहीं है कि हमाने विधान सभा क्षेत्र में कौन सा आदर्श स्वास्थय संस्थान जहां पर एम0आर0आई0 लगा दिया है। मैं इनकी बातो से हैरान हूं और उपर से आप कर रहे है कि कर्ज़ हमारी सरकार के उपर हैं

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री जय राम ठाकुर जारी---

आपको कहां दर्द हो रहा है? दर्द क्यों नहीं होगा? हम इस हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के निवासी हैं। जनता के दर्द हमारे दिल के दर्द होने चाहिए, यह जन-प्रतिनिधि का भाव होना चाहिए। आप टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आज कर्मचारियों को सैलरी और पैंशन समय पर नहीं मिल पा रही है इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपको कहां दर्द हो रहा है? आज ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत से लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, इनको कहिए कि ज़रा शांत रहिए। आपकी बात हमने सुन ली है। ...(व्यवधान) आप बैठिए। आपको नहीं बोलना चाहिए। अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुख्य मंत्री जी नहीं हैं तो कृषि मंत्री जी उनकी अनुपस्थिति का फायदा लेना चाह रहे हैं। बाकी जगह तो इनको बोलने का अवसर मिलता नहीं है। आज इनको मौका मिला है तो ये चाहते हैं कि मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा, अपनी बात यहां पर कहूंगा।

अध्यक्ष : चौधरी साहब, कृपया बैठिए।

श्री जय राम ठाकुर : चौधरी साहब, हम आपके कहने पर नहीं बैठेंगे। आप नहीं बोल सकते कि बैठिए। हमें अध्यक्ष महोदय ने बोलने की अनुमति दी है। अध्यक्ष जी, आप इनको कहिए। ...(Interruption)

Speaker: Chaudhary Sahib, please take your seat. ...(Interruption) I will allow you. ...(Interruption) No interruption please. ...(Interruption)

श्री जय राम ठाकुर : आपका बेटा कहता है कि सरकार की हालत खराब है। इन सारी चीजों को ले कर मुझे लगता है कि आपको अब नहीं कहना चाहिए। अब आपको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। ---(व्यवधान)

Speaker: Chaudhary Sahib, please take your seat. ...(Interruption) Please, please. ...(Interruption) Please take your seat. ...(Interruption) Shourie Sahib, please take your seat. ...(Interruption) जय राम जी बोल रहे

12032025/1315/AG-AT/2

हैं, कृपया बैठिए। Please take your seat. ...(Interruption) Nothing will go on record except the statement of Shri Jai Ram Thakur. ...(Interruption) Please take your seat. Nothing will go on record except the statement of Shri Jai Ram Thakur.

श्री जय राम ठाकुर : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। जो फैक्ट्स हैं, वे फैक्ट्स हैं। हम यहां पर गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं। बेवजह की बातों को सुनने के लिए न आप और न ही हम आए हैं। लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत तो करिए। आपके हालात यह है कि डॉक्टरों को जो पी0जी0 करने के दौरान पैसा मिलता है, वह नहीं मिल पा रहा है। स्टाइफंड उनको नहीं मिल पा रहा है। यह आपकी सरकार की स्थिति है। युनिवर्सिटी में तनखाह लम्बित है। मैं बहुत सारी चीजों का ज़िक्र करुं तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारे पास दो, सवा दो साल का कार्यकाल खत्म हुआ है, आने वाले समय में जो हमारी गारंटियां हैं, कमिटमैंट्स हैं, उनको पूरा करेंगे लेकिन ये झूठ बोलना बंद कर दें कि हमने यह भी कर दिया, वह भी कर दिया, छः गारंटियां पूरी कर दीं लेकिन आपकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है, हकीकत यह है और यह पूरा प्रदेश जानता है।

Speaker: This has already come on the record. No repetition please.

श्री जय राम ठाकुर : झूठ बोलना बंद करिए और मेहरबानी करके कृषि मंत्री जी, हमें उम्मीद है कि कम से कम आप इस सदन में सबसे उम्र दराज सदस्य हैं और आप हम सभी को मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप मुख्य मंत्री को भी बोलिए कि यह गलत परम्परा डाल दी है कि यह भी कह दूं , वह भी कह दूं, इसको बंद करें । मुझे लगता है यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा । मैं समझता हूं कि विपक्ष की आवाज को नहीं रोका जा

सकता क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। जो बात ठीक है, वह हम कहेंगे और जहां गलत लगता है वह भी कहेंगे लेकिन

12032025/1315/AG-AT/3

जो हम सत्य कह रहे हैं वह आपको पीड़ा दे रही है, बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : इस से पहले कि मैं लंच ब्रेक के लिए माननीय सदन की वैठक स्थगित करुं ...(Interruption) **Please, please. Chaudhary Sahib, I have not allowed you. ...(Interruption) Please listen to me first. ...(Interruption) Please take your seat. ...(Interruption) Whatever have been said from both the sides which is undesirable and otherwise cannot form the part of the record will be removed from the records. I will peruse the record thoroughly. This is what I wanted to say.**

Now the House is adjourned for lunch break. We will reassemble at 2.20 pm.

12.03.2025/1425/AS/MD/01

(दोपहर के भोजनोपरांत माननीय सदन की बैठक 2:30 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य को डिबेट के लिए बुलाऊं, मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण संवैधानिक दस्तावेज है, जैसा कि माननीय सदन भी जानते है और दोनों ही पक्षों से मेरा आग्रह रहेगा कि चर्चा में भाग लेते हुए वे इस बात का ध्यान जरूर रखें कि माननीय राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक पद पर हैं। प्रदेश मे एग्जीक्यूटिव के हैड हैं। वह जो भी कहते हैं वह सरकार की मंशा तो होती है और मंत्री मंडल की एडवाइज पर कान्स्टिटूशनली वह कहते हैं। वह जो कहते हैं अपनी आत्मा से कहते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कि "झूठ बुलवाया गया"

ऐसे अपशब्द जो संसदीय भाषा में भी अच्छे नहीं लगते और वैसे भी अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो that causes an imputation to office also; we are causing an aspersion to the office also and such a highest office of the Constitution where we causes any aspersion or imputation, I don't think that will be allowed to be a part of the record. So, I am requesting all the Hon'ble Members that while delivering their speeches, they have to be very-very cautious and they should choose the proper words in the dignity of His Excellency, the Governor of Himachal Pradesh.

Secondly, yesterday also an issue was brought into my notice that the Address which the Hon'ble Governor has addressed to this House, through that address some papers have reported otherwise, which is not a part of the Governor Address and also not a part of the record. I have taken a cognizance of that also. Yesterday, also the Point-of-Order raised by the Hon'ble Leader of Opposition and through that Point-of-Order, he brought it into my notice and I have given a ruling to that effect also. I have taken a cognizance of that. The Hon'ble Governor has also conveyed a displeasure to the House also. As I said that I have taken a cognizance and

12.03.2025/1425/AS/MD/02

I am issuing Show Cause Notices to all those Media Papers and seeking their reply within three days failing which the House will take further action. Thank you very much. Now, I will request the next Hon'ble Member one who will initiate debate, Shri Mohan Lal Brakta

Shri Mohan Lal Brakta in Hindi by K.S.

12.03.2025/ 1430/ केएस/एएस/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2025 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जिसे माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने प्रस्तुत किया और श्री विनोद सुल्तानपुरी, सदस्य ने जिसका अनुसमर्थन किया, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस अभिभाषण पर पक्ष व विपक्ष की तरफ से काफी चर्चा हुई है। इस अभिभाषण के पक्ष में यहां पर सत्ता पक्ष के काफी लोग बोल चुके हैं। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। अध्यक्ष जी, जैसा आपने अभी कहा कि विपक्ष की तरफ से हम सुन रहे हैं कि राज्यपाल महोदय द्वारा झूठ बुलवाया गया है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण पहले केबिनैट अप्रूव करती है, फिर गवर्नर साहब खुद करते हैं, उनका सचिवालय करता है। मेरे ख्याल में अध्यक्ष महोदय, आप भी करते हैं।

अध्यक्ष : ब्राक्टा जी, अध्यक्ष, विधान सभा नहीं करते, गवर्नर सैक्रेटेरिएट करता है and I am only a witness of the Hon'ble Governor Address to the House.

Shri Mohan Lal Brakta : Sorry, Sir, I correct myself. इस अभिभाषण में सरकार की जो भी दो साल की उपलब्धियां हैं, दो साल में जो सरकार ने काम किए, उन सभी बातों का ज़िक्र है। उसमें चाहे गारंटी की बात आती है। कृषि मंत्री जी ने ठीक कहा कि गारंटियों की फिक्र हमें है, आप इसकी चिंता मत करो। अभी हमारी सरकार के तीन साल बाकी है। आप अपनी चिंता करो। विपक्ष के कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कहीं 8-60 की लड़ाई न हो परंतु ज़रूरी नहीं है, यह उल्टा भी हो सकता है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में हमारी सरकार बनी, ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जब मुख्य बने, उस वक्त सभी माननीय सदस्य जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि आप लोगों ने कितनी देनदारियां रखी थीं। पिछले देनदारियां भी थीं, लोन भी था, कर्मचारियों की देनदारियां थीं और खजाना खाली था फिर भी उन

परिस्थितियों में ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने सरकार चलाई। आप सभी जानते हैं कि उसके बाद त्रासदी आई। उस दौरान भी कितनी मुश्किलें आईं और मेरे ख्याल में आप

12.03.2025/ 1430/ केएस/एएस/2

लोगों ने केंद्र में यह बात भी नहीं की होगी कि स्पैशल असिस्टेंस दी जाए। उसके बाद आपने पिछले बजट सत्र के दौरान जो ड्रामा किया, वह सभी के सामने है। आपने सरकार गिराने की कोशिश की लेकिन उसमें आप नाकामयाब हुए। मैं तो बधाई देना चाहता हूं ओ0पी0एस0 हमने दी, 10 में से 6 गारंटियां पूरी कीं। युनिवर्सल कार्टन का जो मसला लम्बित था, वह भी हमारी सरकार ने सॉल्व करके दिखाया एम0आई0एस0 के तहत पैसा दिया। नशे पर जो अंकुश लगा उससे तो आप भी सहमत होंगे कि हमारा प्रदेश आज नशे को रोकने में काफी कामयाब हुआ है। इसके अलावा लॉ एण्ड ऑर्डर की बात आती है। पिछले सालों के मुकाबले क्राइम रेट काफी डाउन हुआ है। आप कहते हैं कि दूध की कीमत बढ़ाई। चाहे गाय का या भैंस का दूध है, जब से दूध की कीमतें बढ़ीं, मैं तो मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि दूध की कीमत बढ़ने से आज लोगों ने ज्यादा पशुधन रखना शुरू कर दिया है और अगर मैं अपने रोहडू चुनाव क्षेत्र का उदाहरण दूं, वहां पर हमारे मिल्क प्लांट की अभी तक केवल 5 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता थी और अब उसकी क्षमता 20 हजार लीटर के आसपास हो चुकी है। लोगों ने गाय रखनी शुरू कर दी है। इसके अलावा आंगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ौत्तरी की है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

12.03.2025/1435/AV/dc/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा----- जारी

इसके अतिरिक्त यहां पर सोलर फैंसिंग की बात की गई। मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा। परंतु आप तो सीधा ही बोल देते हैं कि यह सब तो झूठ पढ़वाया गया है। इसमें जो भी कहा गया है गलत है और

ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग ऐसा दर्शाते हैं कि सब कुछ विपक्ष वाले ही जानते हैं और सत्ता पक्ष वाले तो ऐसे ही सरकार चला रहे हैं। इसमें एक-आधी बात गलत भी हो सकती है, मैं यह बात मान लेता हूं मगर ये लोग तो यह कहते हैं कि पूरे-का-पूरा अभिभाषण ही झूठ है। ...(व्यवधान) आप किसी चीज के लिए धन्यवाद तो कीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अभी तक विपक्ष के जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, सभी ने यही कहा है कि ये सब झूठ पढ़वाया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा अपने दो वर्ष के कार्यकाल में कुछ नहीं किया गया। मगर मैं यहां आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको पिछली माननीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात बताना चाहता हूं। आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी नया काम शुरू नहीं किया। ...(व्यवधान) मैं उस पर भी आ रहा हूं। वहां पर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर का तीन बार दौरा हुआ। वे डोडरा-क्वार भी गए थे मगर मौसम खराब होने के कारण वहां से भाग कर आ गए। उनको लगा कि मौसम खराब हो गया और बाई रोड न जाना पड़े इसलिए वे एकदम उड़कर वापिस आ गए। कुछ देना तो क्या उन्होंने वहां पर लंच तक नहीं किया। उसके बाद दो बार वे रोहड़ू गए। हां, उन्होंने उद्घाटन जरूर किए परंतु शिलान्यास एक भी नहीं किया। उन्होंने वहां पर दो उद्घाटन किए और वे भी पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा शुरू किए गए कार्यों के किए। वहां पर सीमा कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का कार्य, रोहड़ू सिविल होस्पिटल और एक समूली पुल का उद्घाटन किया गया था। वहां पर आप लोगों ने केवल एम0एल0ए0 प्रायोरिटी के कार्यों के भूमि पूजन किए थे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दो-तीन जगह तो आपने डबल भूमि पूजन किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग खुद तो लगातार यह बोल रहे हैं कि कुछ नहीं

12.03.2025/1435/AV/dc/2

कर रहे हैं। मेरे दूरदराज के डोडरा-क्वार एरिया में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत एक सड़क स्वीकृत हुई थी। लेकिन आपकी सरकार उस पैसे को भी खर्च नहीं कर पाई और वह धनराशि वापिस हो गई। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का

धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे ही यह सरकार आई उसके बाद उस डोडरा-क्वार सड़क का काम शुरू हो गया है। हमारी वहां पर उच्च शिक्षा की 5-6 बिल्डिंग्ज थीं जिनकी स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में नींव रखी गई थीं। उनका काम चला हुआ था मगर पूर्व में श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद वे सारे कार्य बंद हो गए थे। मगर अब हमारी सरकार आने के बाद वे सारे-के-सारे कार्य दोबारा से शुरू कर दिए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आईना भी देखा करो। यह नहीं कि आप विपक्ष में हैं तो सभी बातों का विरोध ही करना है। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, आप कम-से-कम उनकी तो प्रशंसा किया कीजिए। मैं तो आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान आपका भी धन्यवाद करता था जब आपकी सरकार कोई फण्ड बढ़ाती थी। ...(व्यवधान) आप ज़रा मेरा पिछली बार का भाषण पढ़ना। मुझे तो यह लगता है कि विपक्ष वालों को यही ट्रेनिंग मिली हुई है कि आपने केवल विरोध ही करना है। ...(व्यवधान) विपक्ष का मतलब यह नहीं होता कि केवल विरोध ही करना है। मैं तो केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं, पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ तो आपने पता नहीं क्या-क्या किया होगा। इस बारे में तो उनको ही पता होगा कि उनके काम हुए या नहीं हुए। लेकिन

टी सी द्वारा जारी

12.03.2028/1440/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा ... जारी

उप-मुख्य मंत्री जी मैंने आपसे भी पावर जेनरेशन के एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। जिसकी लागत 200 करोड़ रुपये थी, लेकिन आपकी सरकार आई और उसे भी रोक दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुटाडा में एक लोक निर्माण विभाग का रैस्ट हाउस था जिसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई थी। उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा चुका था लेकिन जब आपकी सरकार आई तो उसको भी बंद कर दिया गया था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल महोदय ने 10 मार्च को जो अभिभाषण दिया है उसमें चाहे हमारी गारंटी की बात हो या शिक्षा क्षेत्र में हुए कार्यों की चर्चा हो, इन सबके लिए आपको मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए क्योंकि शिक्षा

के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है लेकिन नये शिक्षा मॉडल और उसकी नीतियों पर विचार करने के बजाय आप केवल यह कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का पिछले 2 वर्षों का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, फिर भी हमारी सरकार ने उन सभी ठप पड़े कार्यों को आगे बढ़ाया। मैं इस माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू करने में पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। इसलिए राज्यपाल महोदय ने 10 मार्च को इस माननीय सदन में जो अभिभाषण दिया, मैं उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

Speaker: Thank you, Hon'ble Member Shri Mohan Lal Brakta ji to be in time. माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी ने अपना भाषण मात्र 12 मिनट में समाप्त कर दिया। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह रहेगा कि वे समय का ध्यान रखें क्योंकि आज वक्ताओं की सूची लंबी है जिसमें 13 माननीय सदस्य विपक्ष से और 8 वक्ता पक्ष की ओर से बोलने हेतु शेष हैं। यदि प्रत्येक को 10 मिनट का भी समय देंगें तो भी काफी समय लग जाएगा इसलिए हमें समय का समायोजन करना होगा। मैं सभी को बोलने का अवसर देने का प्रयास करूंगा।

12.03.2028/1440/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य का नाम लूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय का जन्मदिन भी है। मैं तो सुबह से देख रहा हूं कि वे अपनी सीट पर आएं, लेकिन अभी वे सदन में उपस्थित नहीं है। फिर भी हमारी

शुभकामनाएं उनके साथ हैं। यदि वे आ जाएं, तो यह और भी अच्छा होगा, मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अपने विचार रखेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं माननीय राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करूं, मैं मुख्य मंत्री, उप-मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों की अवमानना करते हुए महाकुंभ में स्नान किया और आस्था की डूबकी लगाई। मैं मां गंगा से यह कामना करता हूं कि इनको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि सनातन में इनका विश्वास इसी तरह बना रहे और वे आगे बढ़ें।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल माननीय सदस्य भवानी सिंह पठानिया जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा था। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जब भी बजट पुस्तक, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, मुख्य मंत्री जी का भाषण या कोई प्रेस वार्ता या उनका कोई अन्य बयान होता है तो एक शब्द बार-बार सामने आता है कि

एन0एस0 द्वारा... जारी

12-03-2025/1445/ns-hk/1

श्री रणधीर शर्मा------ जारी

हम तो व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं। यह सरकार तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। हमें अभी तक दो वर्षों में समझ ही नहीं आया कि कौन-सी व्यवस्था का कैसा परिवर्तन हो रहा है? इतना जरूर देख रहे हैं कि आए साल विधान सभा सत्र के दिनों की संख्या कम हो रही है। सत्ता पक्ष का लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम हो रहा है। अगर यही व्यवस्था परिवर्तन है तो इनको मुबारिक हो। पिछले शीतकालीन सत्र में चार बैठकें हुईं। पिछले कलैंडर साल में 25 बैठकें हुईं। अभी जो बजट सत्र 24-25 सीटिंग का होता था आप उसकी 16 सीटिंग कर रहे हैं। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप सदन की बैठकों को क्यों कम कर रहे हैं? ऐसे व्यवस्था परिवर्तन सत्ता पक्ष को मुबारिक हों।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन की बहुत ही उच्च परम्पराएं हैं। देश में हमारे सदन को माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में बहुत ही स्वस्थ चर्चा होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि उन परम्पराओं को समाप्त मत कीजिए। आप उन परम्पराओं को जीवित रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

दूसरा, व्यवस्था परिवर्तन यह हुआ कि सरकारी कार्यक्रम होते हैं तो विपक्ष के विधायकों को निमंत्रण ही नहीं देते हैं। मंत्रीगण तो विधान सभा क्षेत्रों में जाते हैं और वे मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी गए। लेकिन हमें कभी कोई सूचना या निमंत्रण नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी मेरे क्षेत्र में जाकर आए हैं। इन्होंने वहां उद्घाटन व शिलान्यास किए और विधायक होने के नाते मुझे उसका कोई निमंत्रण नहीं दिया। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि विधायक एक व्यक्ति है? मैं बताना चाहता हूं कि विधायक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। आपने अगर उस संस्था का अपमान करना है और यदि यह आपका व्यवस्था परिवर्तन है तो यह भी आपको मुबारिक हो।

अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं और विधान सभा में भी प्रश्न लगे हुए थे। ऐसे-ऐसे अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, विजिलैंस में जांच चल रही है, चार्जशीट दायर हुई है और उनको उच्च पद देना, अगर यह भी व्यवस्था परिवर्तन का

12-03-2025/1445/ns-hk/2

हिस्सा है तो यह भी सत्ता पक्ष को मुबारिक हो। आपका एक तरफ नए आई0ए0एस0 व आई0एफ0एस0 लेने से मना करना और दूसरी तरफ रिटायर्ड ऑफिसर्ज को भारी वेतन देकर काम देना, यह कौन-सा व्यवस्था परिवर्तन है? आप जरा हमें समझाएं। आपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर मजाक बना दिया है। अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर (हैल्थ) का पद 15 दिन खाली रहा। प्रदेश के इतिहास में आज तक किसी मुखिया का पद इतने दिन खाली नहीं रहा। आपने 15 दिन बाद जिसको डायरेक्टर लगाया उसको रि-इम्पलॉयमैंट देकर लगाया। आपने रिटायर्ड व्यक्ति को रि-इम्पलॉयमैंट दी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या

कभी Head of the Department रिटायर्ड व्यक्ति लग सकता है? क्या रि-इम्पलॉयड किया गया व्यक्ति Head of the Department हो सकता है और वह भी हैल्थ डिपार्टमैंट का? आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आप व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। आपने प्रदेश के क्या हालात बना कर रख दिए हैं, उनको आप स्वयं देखें।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में कहा गया है कि हम प्रदेश का एक समान विकास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक समान विकास तो क्या ये 40 विधान सभा क्षेत्रों का विकास भी नहीं कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस के विधायक हैं। मैं इस बात को प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं। मैंने पिछले सत्र में भी पूछा था और मुख्य मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया था। आजकल विधान सभा क्षेत्रों में विकास के लिए अगर फंडज कहीं से आता है तो नाबार्ड से आता है। हम विधायक अपनी प्राथमिकताएं देते हैं और विभाग डी0पी0आर्ज0 बना कर नाबार्ड में भेजता है। वहां से डी0पी0आर्ज0 सैंक्शन होती हैं। पहले यह परम्परा थी कि जो डी0पी0आर0 पहले गई उसको नाबार्ड से पहले सैंक्शन मिलती थी। आपकी सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन करके आई है वह Repriortize करने के लिए पत्र लिखती है। अध्यक्ष महोदय, यह पत्र (पत्र दिखाते हुए) 10 जून का है।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

12.03.2025/1450/RKS/hk-1

श्री रणधीर शर्मा... जारी

जिसमें एडवाइजर प्लानिंग ने सी0जी0एम0, नाबार्ड को लिखा है कि 'I am directed to say that State Government has re-priortized the Detailed Project Reports (DPRs) of 28 Legislative Assemblies Constituencies of Himachal Pradesh. सिर्फ 28 विधान सभा क्षेत्रों की डी0पी0आर्ज0 को ही स्वीकृति दी जानी है और इसके लिए एडवाइजर प्लानिंग की चिट्ठी सी0जी0एम0, नाबार्ड को भेजी गई है। पत्र में नीचे यह भी उल्लेख किया गया है कि 'This issue with the prior approval of Hon'ble Chief

Minister'. यह पत्र मुख्य मंत्री की अनुमति के बाद प्रेषित किया गया है। इसमें विपक्ष के 28 सदस्यों के किसी भी विधान सभा क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि लोक निर्माण मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण और रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। आपने अपनी पार्टी के 12 विधायकों को भी छोड़ दिया है। इसमें कुल्लू, फतेहपुर, नालागढ़, भोरंज, पालमपुर, ज्वालामुखी, इन्दौरा, शिमला और ठियोग विधान सभा क्षेत्रों के नाम गायब हैं। विपक्ष के 28 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों का तो पहले ही कोई उल्लेख नहीं था। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ 28 विधान सभा क्षेत्रों का ही विकास करना चाहते हैं। उप-मुख्य मंत्री जी सरकार की यह मंशा अब लिखित रूप में सामने आ गई है। इसके बारे में आपसे भी कोई परामर्श नहीं किया गया। ...(व्यवधान) जल शक्ति विभाग की ओर से हमारी योजनाओं की डी0पी0आर्ज0 नाबार्ड को भेजी गई थी। जल शक्ति विभाग की 101 डी0पी0आर्ज0 नाबार्ड ने वापस भेज दी हैं। आदरणीय मुकेश जी क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ? उन 101 डी0पी0आर्ज0 में से 78 डी0पी0आर्ज0 विपक्ष के विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों की हैं और बाकी 12 उनकी डी0पी0आर्ज0 हैं जिनके नाम मैंने पहले लिए। लेकिन उन 28 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों की डी0पी0आर्ज0 वापस नहीं आई। इसका मतलब यह है कि यह सरकार सिर्फ उन 28 विधायकों की ही चिंता कर रही है। फिर आप कहते हैं कि हम एक समान विकास कर रहे हैं। इस प्रकार से एक समान विकास कहां हो रहा है? मुकेश जी यह आपके विभाग की बात है। आप कहेंगे कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने इसकी अनुमति नहीं दी थी लेकिन हमारे पास इसका प्रूफ है। ...(व्यवधान) यह इस सरकार की स्थिति है। यहां पर माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने भी आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की बात की। श्री नैना देवी जी में भी एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान घोषित किया है। आप सी.टी. स्कैन और एम.आई.आर. की बात कर रहे हैं लेकिन वहां तो डॉक्टर ही नहीं हैं। वहां डॉक्टर्ज़ के 10

12.03.2025/1450/RKS/hk-2

स्वीकृत पदों में से 9 पद खाली पड़े हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जल शक्ति विभाग की गतिविधियों का 3-4 पृष्ठों में उल्लेख किया गया है। मुकेश जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 जे0ई0 की पोस्टें खाली हैं। मैंने इस विषय में धर्मशाला विधान सभा में नियम-62 के अंतर्गत चर्चा की थी। आपने कहा था कि हम जल्द ही रिक्त पदों को भर देंगे लेकिन आप जे0ई0 के पदों को भरने की बजाय वर्क इंस्पेक्टर भर रहे हैं। क्या आप जे0ई0 के पदों

को समाप्त कर देंगे? आपने जे0ई0 की जगह वर्क इंस्पेक्टर के पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया है। इस तरह इस विभाग का काम कैसे चलेगा? आप जल शक्ति विभाग की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगर हम इस विषय में बात करें तो किससे करें? आपके सब-डिवीजनों में जे0ई0 उपलब्ध नहीं हैं। जे0ई0 की कमी होने के बावजूद आपने 45 जे0ई0 को प्रमोट करके एस0डी0ओ0 बना दिया है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

12.03.2025/1455/बी.एस./वाई के /-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

मैं इस बात का विरोध नहीं करता, धन्यवाद करता हूं। वे डिजर्व करते थे, इसलिए आपने उन्हें एस0डी0ओज0 बनाया। लेकिन 45 दिनों तक आप उनकी पोस्टिंग ही नहीं कर पाए। वे परमोट हो करके एस0ई0 के कार्यालय में बैठे रहे, लेकिन उन्हें स्टेशन तक नहीं दिया गया। यह कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? आप बोलेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने अप्रूवल नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं कि जल शक्ति मंत्री जी की शक्तियां कहां हैं? ऐसी दयनीय हालत इस सरकार की है। जब बोलेंगे, तो कहते हैं बोलते हैं। मैं एक बात की और बधाई देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस सरकारों की सभी परंपराओं को जीवित रखा है। वर्ष 2012-17 के बीच कांग्रेस की सरकार के समय स्कूटरों पर सेब ढोए गए थे और इस सरकार के समय स्कूटरों पर पानी ढो कर लोगों को पिलाया गया। वह परंपरा आपने और आपके विभाग ने जीवित रखी है, इसलिए विशेष रूप से आपको बधाई। आपने उनके विरुद्ध कार्रवाई केवल कागजों में की परंतु हकीकत में जांच करके केवल बचाने के प्रयास हो रहे हैं। आपने केवल मछलियां पकड़ी हैं, परंतु मगरमच्छों को आपने भी हाथ नहीं लगाया है।

उप-मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, आप मगरमच्छों के नाम तो बताइए।

श्री रणधीर शर्मा : उप-मुख्य मंत्री जी, शिकारी आप हैं, मगरमच्छों के नाम मैं बताऊं? जब आप कोई भी कार्रवाई नहीं करते तो हालत क्या होती है? मेरे पास मामले तो बहुत हैं परंतु मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, इसलिए उनके विभागों के बारे में नहीं बोलूंगा। आपके विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। परवाणू में एन0जी0टी0 के कहने पर सिवरेज का कार्य होना था। सरकार ने इसके लिए बजट दिया, टेंडर लगे। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे कि अधिकारियों कि हालत देखिए, टेंडर में ऊपर तो लिख दिया 'Name or work:- Providing Sewerage System to Parwanoo Town (Providing Electrical installation in Division office Building), Name of work:- Providing Sewerage System to Parwanoo Town (Structure stability work below plinth beam Divisional Store at Parwanoo) and Name of work:- Providing Sewerage System

to Parwanoo Town (Providing electrical installation in Division office Building)'. आपके ये सात टेंडर जो सिवरेज सिस्टम के लिए लगने थे, उन्हें सिवरेज सिस्टम के नाम पर अधिकारियों ने अपने कार्यालयों को सजाने-संवाने में लगा दिया। यह आपके विभाग का हाल है और यह सब आपके नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं करते। आप मछलियां पकड़ते हैं परंतु मगरमच्छों को हाथ नहीं लगाते, इसलिए यह हालत हो रही है। लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर नहीं है। पहले लोक निर्माण विभाग में सिस्टम था कि पांच लाख से ऊपर के टेंडर ऑन लाइन होते थे। इसका नियम भी तोड़ा जाता था। मैंने पहले भी विधान सभा में बोला था, हमारे स्कूल के एक ग्राउंड को 15 लाख रुपये आया और उसे पांच-पांच लाख रुपये के तीन हिस्सों में कर दिया गया। अब ऑन लाइन के एक लाख रुपये से ऊपर के टैंडर हो रहे हैं। उसके बावजूद आपका लोक निर्माण विभाग क्या किया कि 9,91,000 रुपये के एक काम का ऑल लाइन टेंडर नहीं किया। परंतु 90-90 हजार के 10 टेंडर कर दिए। ताकि कांग्रेस के कार्यकताओं को फायदा हो सके। आप नियम और कानून क्यों बना रहे हैं जब आपने उन पर चलना ही नहीं है? यह कोई अखबार की कटिंग

नहीं है। यह आपके वहां के एक्सियन ने स्वीकार किया है। अब 90 हजार में तीन किलोमीटर की सड़क के लिए क्या काम होगा? ...(घंटी)... अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं शुरू ही हुआ हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 14 मिनट का समय हो चुका है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुबह लोक निर्माण विभाग का एक प्रश्न था। हमारी नवगांव-बैरी सड़क के लिए केन्द्र से पैसा आया, आदरणीय अवस्थी जी हमारे पड़ोसी हैं। हमनें इनके क्षेत्र का एरिया भी इसमें सम्मिलित किया है और पड़ोसी का धर्म निभाया है, ये निभाएं या न निभाएं। परंतु उस सड़क का कार्य जल्दी शुरू करवाएं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

12.03.2025/1500/DT/YK-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

उसका काम नहीं हो रहा, यह मैं माननीय लोक निर्माण मत्री जी से कहना चाहता हूं। यहां पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की चर्चा हुई। हम आंकड़े देखकर जितना मर्जी एक दूसरे पर दोषारोपण करें, सच्चाई तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कबूल की है; खजाना खाली है। हम भी देख रहें है कि पिछले दो महीने से ट्रेजरी से पैसा नहीं आ रहा। उसमें चाहे हम विधायक क्षेत्र विकास निधि की बात करें चाहे ऐच्छिक निधि का पैसा नहीं आ रहा, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही। लोगों की बुढ़ापा हो चाहे विधवा पैंशन हों दोनों ही नहीं मिल रहीं। प्रदेशे की आर्थिक स्थिति ऐसी है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। परंतु हमारा यह कहना है जब प्रदेश के ऐसे हालात है तो फिजूलखर्ची भी छोड़ो न। मुख्य मंत्री जी का कार्यालय 19 करोड़ रुपये से सुसज्जित होगा। अन्य मंत्रियों के कार्यालयों के लिए करोड़ों रुपये खर्च होंग। अधिकारियों के विदेशी दौरे हो रहे हैं जबकि कृषी मंत्री जी ने फाइल टर्न-डाउन कर दी थी और कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्य मंत्री जी अधिकारियों को खुश कर रहें हैं कि नहीं आप विदेशी दौरे पर जाकर आओ। अधिकारियों के विदेशी दौरों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उसकी रिपोर्ट तो लो? हमारी सरकार अपने समय में रोती नहीं थी, हम किसी की पैंशन बंद नहीं करते थे बल्कि हम पैंशन लगाते थे।

लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्राफी जीती, भारतीय टीम बधाई की पात्र है। आप बधाई दीजिए। लेकिन यह कहना कि आप हिमाचल आओ आपका रहने-खाने का सारा खर्च हिमाचल वहन करेगा, इसका मतलब तो यही है कि पल्ले नहीं ढेला और कर दूं मेला-मेला। सरकार के पास पैंशन देने को पैसा नहीं है। आप क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी बुलाओ हम कहां मना कर रहे हैं पर उससे पहले आप बुढ़ापा पैंशन दे दो, आप विधवा पैंशन दे दो, आप अपंग को पैंशन दे दो। हम 10000/- रुपये की राशि किसी गरीब को अपनी ऐच्छिक निधि से देते हैं, वह हमें दे दो। उसके बाद आप जैसा दिल हो वैसा करो। इसलिए मेरा आग्रह है कि यह जो आर्थिक स्थिति है इसमें प्रदेश के हालात कहां पहुंचे गये हैं? हालात या पहुंच गये हैं कि मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है। हमे इसकी दिक्कत नहीं है। हम विपक्ष में हैं और इसके विरूद्ध हम बोलेंगे। आपने उपायुक्तों को पत्र लिखा कि

12.03.2025/1500/DT/YK-2

इन योजनाओं को पैसा दे दीजिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई, तो आप बोलते हैं कि वह झूठ बोल रहे हैं और उप-मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि न ऐसा हुआ और न ऐसा होगा। आपने यह भी कहा कि श्री जय राम ठाकुर जी के समय मंदिरों से 2.50 करोड़ रुपये निकले। आपकी सरकार ने तो माता नैना देवी मंदिर ट्रस्ट से 16 करोड़ रुपये निकाल लिये। ...(व्यवधान) मैं इसके बारे में बता दूं, मैं बताना नहीं चाह रहा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक चिकित्सालय भवन बन रहा था, सरकार के पास बजट नहीं था लेकिन मंदिर ट्रस्ट से 10 करोड़ रुपये दिलवाया गया, क्या यह बात सच है या नहीं है? ...(व्यवधान) सर, रेजोल्यूशन तो आपके कहने पर आपके ही नेता दिलवाते हैं। मेर पास चिट्ठियां है। ये डिप्टी सेक्रेटरी एल0ए0सी0 की चिट्ठियां हैं। आपने नैना देवी से 1 करोड़ रुपये सुख आश्रय योजना के लिए लिया। ...(व्यवधान) यह सरकार ने दिया। डिप्टी सेक्रेटरी (एल0ए0सी0) कौन है? यह लैंगुएज एंड कल्चर विभाग का डिप्टी सैक्रेटरी है। ...(व्यवधान) हां, आप गौ सदन के लिए दीजिए। आपकी हालत खराब है, आप दीजिए। आपकी हालत यह है कि आप स्कूलों में जादुगर का शो करवाकर उसका पैसा ले रहे हैं। मेरे पास सरकारी लैटर है।

...(व्यवधान) मैं सुझाव देता हूं कि आप सचिवालय के बाहर दान-पात्र रख दो। हम भी उसमें बाबा के नाम पैसे डाल देंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गए हैं। आप बजट में बोल लेना।

श्री रणधीर शर्मा : सर, यहां केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा आता है। यह प्रश्न सुबह भी लगा था।

श्री एन.जी. द्वारा जारी...

12.03.2025/1505/ए.जी.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा.....जारी

मेरे पास चिट्ठी बाद में आई है। केन्द्र की योजनाओं का पैसा सैलरी देने में खर्च हो रहा है। ...(व्यवधान) हां, अब आई अक्ल, ...(व्यवधान) बिलकुल संघीय ढ़ांचा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग को समग्र शिक्षा का पैसा आया है, यह चिट्ठी मुझे बाद में मिली नहीं तो सुबह ही हंगामा हो जाता, समग्र शिक्षा के पैसे का उपयोग विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों व कर्मचरियों की जनवरी-फरवरी की सैलरी देने के लिए किया। मेरे पास इसका एक पत्र है और आपको भी यह स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज सरकार की ये हालत हो चुकी है कि केन्द्र सरकार से समग्र शिक्षा का जो पैसा आया है उस पैसे को शिक्षकों व कर्मचारियों की सैलरी में दिया जा रहा है। इसके अलावा भी एक चिट्ठी निकाली गई है कि डाइट, स्कूल्ज़ या बी0आर0सी0 में जो पैसा बचा हुआ है उसे भी वापिस ट्रेज़री में भेज दो ताकि सरकार उसे भी खर्च कर सके। ...(व्यवधान) कहीं तो रुक जाइए। ...(घण्टी)...

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रेलवे के प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं और प्रदेश सरकार ने उसकी वाहवाही लेने की कोशिश की है। सच्चाई यह है कि प्रदेश सरकार ने उन रेलवे प्रोजैक्ट्स में भूमि अधिग्रहित करके केन्द्र सरकार को देनी है। उस पर जो निर्माण कार्य होगा उसका 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देगी और शेष 25 प्रतिशत पैसा प्रदेश सरकार को देना होगा। वर्तमान सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में न तो भूमि अधिग्रहण का पैसा दिया और न ही निर्माण कार्यों में अपना 25 प्रतिशत शेयर दिया है। केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार को एक चिट्ठी आई है जिसके अनुसार अभी तक प्रदेश सरकार के शेयर का लगभग 1800 करोड़ रुपये लम्बित पड़ा है। अक्तूबर में चिट्ठी आई थी तब 1626 करोड़ रुपये लम्बित पड़े थे।

12.03.2025/1505/ए.जी.-एन.जी./2

जिसमें से 1441 करोड़ रुपये भानुपल्ली-बरमाणा रेल प्रोजैक्ट और 185 करोड़ रुपये बद्दी-चण्डीगढ़ रेल प्रोजैक्ट की देनदारी लम्बित थी।...(व्यवधान) (माननीय सदस्य, श्री संजय अवस्थी की ओर देखते हुए) हमारे समय में लगभग 800 करोड़ रुपये गए हैं। आप फैक्ट्स देख लीजिए। ...(व्यवधान) भूमि अधिग्रहण का भी गया है। ...(व्यवधान)

Speaker: No interruption please, Shri Sanjay Rattan ji. Please conclude now.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के समय की लगभग 1800 करोड़ रुपये की देनदारियां लम्बित पड़ी हुई है।

Speaker : Conclude please.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस सबके बावजूद यह सरकार क्या कर रही है कि रेलवे प्रोजैक्ट्स का जो पैसा बैंकों में भूमि अधिग्रहण करने के लिए आया था और सरकार सभी बैंकों को चिट्ठी निकाल रही है, पंजाब नैशनल बैंक, कॉप्रेटिव बैंक, कैनरा बैंक आदि

को लिख रही है कि रेलवे प्रोजैक्ट्स का जो पैसा बचा हुआ है उसको स्टेट ट्रेजरी में ट्रांसफर करो। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी चिट्ठियां हैं। ये चिट्ठियां साबित करती हैं कि चाहे सर्व शिक्षा अभियान का पैसा हो या चाहे रेलवे का पैसा हो, ये सरकार उन पैसों से कर्मचरियों की सैलरी देकर अपनी सरकार चलाना चाहती है। प्रदेश सरकार का अपना खजाना पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है और इसे सत्ता में बैठे हुए लोगों को स्वीकार करना होगा।

Speaker : Conclude please.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं गारंटियों की बात करना चाहता हूं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की बात कही थी। सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये तो क्या देने थे बल्कि सरकार ने महिलाओं से फॉर्म्ज भरवाने के लिए

12.03.2025/1505/ए.जी.-एन.जी./3

उनके 5-5 हज़ार रुपये खर्च करवा दिए हैं। कभी वे पंचायत में जाती हैं, कभी पटवारी के पास जाती हैं तो कभी तहसीलदार के पास जाती हैं लेकिन उन्हें अभी तक एक ढ़ेला भी नहीं मिला है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने तो उन पर उल्टा 5-5 हज़ार रुपये का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। सरकार दुग्ध की बात कर रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने दुग्ध का समर्थन मूल्य 45 व 55 रुपये किया है लेकिन हमारे क्षेत्र में कामधेनू वाले तो यही रेट पिछले चार साल से दे रहे हैं। पंजाब में तो 70 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा दुग्ध बिकता है। आपने 100 रुपये प्रति लीटर का वायदा किया था और आप उसे पूरा कीजिए तब हम भी आपको मान जाएंगे। सरकार ने गोबर की बात भी की थी। मैं यहां पर कहना नहीं चाहता हूं लेकिन पिछले कल माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी ने बहुत गलत बात कही थी कि हम आपका गोबर भी खरीद लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि (हंसते हुए कहा गया) हमारा रहने दो, अपना ही ले लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। फिर कहते हैं कि 'जंगल में मोर नाचा किसने देखा'। अरे, आपके मोर का नंगा नाच तो सारी दुनिया ने देखा है। वह

चाहे समोसे पर सी0आई0डी0 की जांच हो, वह चाहे जंगली मुर्गे की बात हो, वह चाहे टॉयलेट टैक्स हो, वह चाहे भगवान भरोसे सरकार हो, सारी दुनिया ने आपके नंगे मोर का नाच देखा है।

Speaker : Conclude please.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार ने रेलवे की बात की है लेकिन अच्छा होता यदि इस अभिभाषण में एम्स की चर्चा भी करते। यह केन्द्र सरकार की बहुत बड़ी देन है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

12.03.2025/1510/AG-PB/-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

और अभी AIIMS को चले हुए पांच वर्ष भी नहीं हुए हैं फिर भी आज किडनी ट्रांसप्लांट और knee transplant भी हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले श्री जगत प्रकाश नड्डा जी AIIMS आए और उन्होंने 31 करोड़ रुपये की लागत से PET Scan और PET CT इत्यादि सारी सुविधाएं दे दी। जो सुविधाएं श्री नड्डा जी ने AIIMS में दी हैं वह आज तक हिमाचल के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अभी तक नहीं है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। वह वहां पर एटेंडैंटस के रहने की सुविधा के लिए 500 बैड के विश्राम सदन का शिलान्यास करके गए हैं। Virology Research and Diagnostic Lab का शिलान्यास करके गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान न करे कि आपको बिमारी के समय AIIMS जाना पड़े। आप एक बार AIIMS घूम कर आएं तो आपको पता चलेगा कि वहां किस स्तर की स्वास्थय सुविधाएं हैं। यदि आने से पहले आप मुझे बताएंगें तो मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप वहां की सुविधाएं, संचालन एवं साफ-सफाई देखेंगे तो अपने उन कांग्रेसी साथियों को अकल जरूर दे देना जो कल 20 लोगों को

लेकर गेट पर धरना दे रहे थे। जो उस...(व्यवधान) ओपीडी तो लाखों में है...(व्यवधान)। प्रदेश में 750 बैड चल रहे हैं। ...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Member, please conclude.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी आएं और देखें कि हमें एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिला है। मैं बिलासपुर ही नहीं हिमाचल की समस्त जनता की तरफ से श्री जगत प्रकाश नड्डा जी तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज पंजाब के मरीज़ भी AIIMS आ रहे हैं जिन्हें पी0जी0आई0 नज़दीक पड़ता है परंतु इसके बावजूद भी कांग्रेस के छुटपईया नेता जिस तरह के निराधार और तथ्यहीन बयान दे रहे हैं उस की मैं कड़ी निन्दा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि यह अभिभाषण सत्य से परे है। धन्यवाद प्रस्ताव लाना सरकार का जिम्मा था और यह लाए हैं परंतु मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद।

12.03.2025/1510/AG-PB/-2

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी , आप कुछ कहना चाहते हैं।

उप-मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कुछ बातें रखी हैं। सबसे पहले तो आपने मामहिम राज्यपाल को लेकर जो रूलिंग दी है हम उससे सहमत हैं। यह सरकार महामहिम राज्यपाल का पूरा सम्मान करती है। हमेशा से कन्वेंशन रहा है कि सरकार कोई भी हो महामहिम राज्यपाल आते हैं और मौके की सरकार की बात करते हैं। ठीक है विपक्ष सरकार की तथा सरकार की नीतियों की आलोचना करें परंतु महामहिम राज्यपाल को लेकर जो आपने रूलिंग दी है हम उसका पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा कि विपक्ष के एम0एल0एज़0 को बुलाया नहीं जाता। यह कोई नई बात नहीं है। इस सदन में मुझे भी 22-

23 वर्ष हो गए हैं, पिछले पूरे पांच वर्ष श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार रही और उस वक्त मैं विपक्ष का नेता था, मुझे याद नहीं कि कभी इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र का दौरा किया हो और मुझे इसकी इत्तलाह भी दी गई हो। यह कोई नई रिवायत नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि हमने शुरू की है। ...(व्यवधान) व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं है। जैसी परम्पराएं डाल के जाओगे वैसी निभानी भी पड़ती हैं। आपने (विपक्ष की ओर देखते हुए) कभी विपक्ष के सदस्यों को नहीं बुलाया लेकिन हम फिर भी आपको बुलाएंगे। आप फिर भी नहीं आएंगे। हम आपको पत्र भी लिखेंगे, आपको फोन भी करेंगे, सब कुछ करने के बावजूद भी आप नहीं आएंगे। लेकिन यह मुझे मालूम है कि आप मसला जरूर उठाएंगे। दूसरी बात...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री रणधीर जी हमने आपकी बात बड़े प्यार से सुनी, आप मेरे विधान सभा क्षेत्र के दामाद हैं। आप नाबार्ड की बात कर रहे हैं.

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1515/A.P/A.S/01

उप-मुख्य मंत्री द्वारा जारी .....

अध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य की नाबार्ड के अतंर्गत जो डी.पी.आर्ज. बनकर आई वह हमने नहीं रोकी। हमने सारी डी0पी0आर्ज0 नाबार्ड को भेज दी हैं। नाबार्ड से जो हमें पैसा मिलता है वह एक प्रकार का लोन है, राज्य सरकार लोन लेती है और फैसला करती है कि नाबार्ड का लोन किस लिए लेना है। लेकिन नाबार्ड ने हमारी 101 डी.पी.आर्ज. लौटाई और उन्होंने कहा कि हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है। हम आपको इतना ही लोन दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने इतना ही पैसा स्वीकृत किया है और जो लिमिट बताई गई है उसके तहत 21 डी0पी0आर्ज0 ली जा सकती है और शेष वापिस लौटा दी गई हैं।

दूसरा, उन्होंनें बताया कि कुछ ड0पी0आर्ज0 इसलिए लौटाई गई है क्योंकि यह 175 करोड़ रुपये की लिमिट को पार कर गई। मैं, श्री जय राम जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने, अपने सभी सदस्यों की 175 करोड़ की लिमिट अपनी सरकार के समय में ही पूरी कर दी थीं। ....(व्यवधान) हमारी लिमिट तो बहुत कम है। लेकिन सुंदरनगर में तो 195 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि आप तो उस लिमिट को over

and above ले गए । इसलिए यह है कि हम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। इसके इलावा मंदिरों के पैसे की बात आप बार-बार कर रहे हैं, आपको सूट भी करता है क्योंकि आप देश के बहुत बड़े सनातनी लोग हैं। इसलिए आप मीडिया में इस बात को बार-बार उठा रहें है, दिल्ली में चलवा रहें है कि हिमाचल सरकार भगवान भरोसे चल रही है। पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी आपको बता रहे थे कि 500 करोड़ रुपये की राशि मंदिरों से प्रदेश सरकार ले रही है, मैं श्री जय राम ठाकुर जी को बता दूं कि 500 करोड़ रुपये तो मंदिरों के पास पैसा भी नहीं है। यह जो सभी मंदिरों का पैसा है इस पर हाई कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि मंदिरों के पैसों से गाड़ी नहीं खरीद सकतें। मंदिरों के नाम पर जो विज्ञापन सरकारों के छपते थें, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप डी0सी0 ऑफिस में जो आदमी रखते थे उन्हें भी आप नहीं रख सकते। उप-मुख्य मंत्री ने श्री जय राम ठाकुर जी की इशारा करते हुए कहा कि मैं जब पहली केबिनेट में मुख्यमंत्री बनकर आया तो मैंने सबसे पहले कहा कि गौशालाओं

12.03.2025/1515/a.p/a.s/02

के लिए मंदिरों से पैसा दिया जाए। आप चाहते तो गौशलाओं के लिए कोई नीति भी बना सकते थें। इसका मतलब यह है कि जिस समय आप मुख्य मंत्री बने तो आपकी नजर उसी समय मंदिरों पर थी। आपने कहा कि मंदिरों से 15 प्रतिशत पैसा गौशालाओं को देना है । मैं श्री जय राम ठाकुर जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप अनाथ बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं, आप में कोई संवेदनशीलता है? आपको ऐतराज़ है कि अनाथ बच्चों को यह पैसा नहीं जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि गौऊओं को देना चाहिए था। हम भी गौऊओं के पक्षधर है। अब आप गौऊओं की हालत को तो देखो, ज्वालामुखी वाले गौशाला का हाल इस प्रकार है कि 900 गाय मर गई.....(व्यवधान)हमारे समय में नहीं मरी, लेकिन जो हालात है आज कुटलैहड में जो गौशाला बनाई थी उसका आप हाल देखें .....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह लगातार सरकार की नीतियों पे बात कर रहे हैं और मंदिरों के इश्यू पर लगातार बोल रहे हैं। श्री जय राम ठाकुर जी जब आप भी मुख्यमंत्री थे तो आप भी सी0 एम0 रिलीफ फण्ड़ से पैसा लेते थे। अब भी आता है सी0एम0 रिलीफ फण्ड में पैसा, आपने

16-17 करोड़ रूपये कोविड के समय लिए, आपने राम मंदिर के लिए पैसा भेजा, आपने जाखु मंदिर से पैसा लिया। ....(व्यवधान)

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

12.03.20205/ 1520 /AT/ ऐ0एस0 /.1

उप मुख्य मंत्री जारी ....

अपने कोविड में पैसा लिया अपने 16 ,17 करोड़ रुपये कोविड़ में लिया आपने राम मंदिर के लिए आपने पैसा मंदिरों से भेजा आपने झाखू मंदिर से पैसा लिया है जब हमने एक बार सपष्ट कर दिया कि मंदिरों का पैसा सरकार की किसी भी बजटिड स्कीम के लिए हम नहीं लेंगे। अभी तक नहीं लिया और हमने स्पष्ट भी कर दिया कि नहीं लेंगे। रणधीर जी, आप भी तो वहां पर अपने समय में लिफ्ट लगा रहे थे। और भी कितना काम आप वहां पर मंदिर के पैसे सही ही करवा रहे थे। मंदिर के एरिया के 10-12-15 किलोमीटर के दायरे में जो भी पंचायतें हैं, उनको पैसा देने का प्रावधान है। वहां पर चाहे सड़कें बनाएं, अस्पताल बनाएं या गरीब लड़कियों को पैसे दें या अनाथ बच्चों को पैसे दें। यह तो उसमें प्रावधान है। मंदिरों का पैसा इसके लिए यूज़ किया जाता है। हमारी कोई मंशा नहीं है, जो ठाकुर साहब बार-बार यह कह रहे हैं कि 500 करोड रुपए यह ले जाएंगे। आपने तो सरकार चलाई है, 500 करोड़ रुपये से क्या बनेगा सरकार का? एक हफ्ते का क्या तीन दिन का भी खर्चा नहीं है। इसलिए मंदिरों के पैसे के ऊपर न सरकार की नजर है और यहां तक रणधीर जी कह रहे हैं कि वहां अस्पताल बन रहा है ..व्यवधान आपका अस्पताल बन रहा है आप उसका काम रूकवाना चाहते है? आप मुझे लिख कर दे दो कि 10 करोड़ रुपया वापिस ले लो, हम वपिस ले लेते हैं। ... व्यवधान वह तो आपके ट्रस्ट ने लिखकर दिया है। बिक्रम जी, जब हमने कोई पैसा लिया ही नहीं, बताओ न। जब कोई नोटिफिकेशन आपने देखी, आपने कहा हमने स्पष्ट कर दिया कि भाई मंदिरों का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है अगर आपको नजर आए कि कहीं मंदिरों का पैसा हमने लिया है, आप हमारे ध्यान में ला देना लेकिन मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, मंदिरों में वही स्कीमें चल रही है

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

12.03.20205/ 1520 /AT/ ऐ0एस0 /.2

उप -मुख्य मंत्री : और दूसरा आप 11,12 हजार करोड़ रूपये का कर्ज छोड़ कर गये है आप ही 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड कर गये है इस प्रदेश में इतनी बडी देन दारीयां 80, 85 करोड़ रूपये छोड़कर गये है आपके सामने अभी केंद्रीय बजट आया बिहार को तीन एयरपोर्ट दे दिया उन्होंने क्यों कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं क्यों नहीं मंडी को दे रहे हैं आपकी

सरकार है आप चिंता कर रहे हैं आप कह रहे हैं यहां धन्यवाद लाओ । बिहार को तीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दे दिए बाकी राज्यों में रेलवे जो है सारी पटियां कैन्द्र सरकार बना कर दे रही है और हमसे कह रही है कि पैसा दो हमसे कह रहे हैं कि बिलासपुर का भी पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि आप बद्दी रोटी वाले का भी पैसा दो तो जहां पर केंद्र को कम से कम एयरपोर्ट और रेलवे में तो हमारी मदद करनी चाहिए तो यह जो मसाले हमारे पर सामने हैं देखो हिमाचल हम सब का है और कुछ चीज हमारे संजय इश्यूज हैं ठीक है आप हमारी आलोचना करो कि आपने यह कर दिया आपने कहा कि पेंशनर्स को पैसा नहीं मिला ,हमने दे दिया आपने कहा कि यह पैसा एम0एले0 नहीं निकला हमने पता कर लिया पैसा निकल गया है ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा में कोई खोट है सरकार ईमानदारी से हर वर्ग विशेष की सेवा करना चाहती है और कर रही है अपने रिसोर्स जनरेट करके भी कर रही है और यह भी लास्ट बाद में अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं क्या जय राम जी के टाइम में केंद्रीय योजनाओं का पैसा आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था क्या उसे पैसे से आप लोगों ने तनखयें नहीं दी, क्यों नहीं दी, ऐसे नहीं पैसा सारा ट्रेजरी में आता है अब स्पर्श स्कीम आ रही है वह आना ही नहीं है अब वह चल जाएगा अलग-अलग उनके पास ही टिका रहेगा जब यूसी जाएगी कि यह इतना खर्च हो गया वह आपके केंद्र सरकार ने नीति बदल दी सारे राज्यों के लिए लेकिन इनके समय में भी सारा पैसा ट्रेजरी में आता था वह तब भी तनखायें दी जाती थी इसमें कोई अभी बदलाव नहीं आया है इसलिए आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है पैसा जो है ट्रेजरी से निकाल लिया हमने खर्च लिया ऐसा कुछ नहीं है यह ट्रेजरी में पैसा पड़ा नहीं रहता हू मैं आपको बताना चाहता हूं जव जय राम जी ने 1000 करोड़ मंडी के ऐयर पोट के लिए तो वह पैसा पड़ा हुआ होता ।

ट्रजरी में पैसा पड़ा नहीं होता । जव जिसको पैसे की जरूरत होती है तव उसको पैसा दिया जाता है ऐसे कोई कमिटड पैसा आता नहीं है तो अध्यक्ष महोदय सब के हितों के ख्याल हो रहा है इस सदन को कहना चाहता हूं ।

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1525/md/dc/1

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय एक तो इन्होंने जो DPR की बात कही है जो वापिस आई है पहली बात तो श्री नैना देवी जी का चेक कर लें हमारा 175 करोड़ से भी अभी 12 करोड़ अभी बचा हुआ है। PWD की चार सड़के चाहें वो कटिरढ़-पंगवान, चाहे भोली संपर्क सड़क है चाहे बाड़नू सड़क है। ये चार DPR पिछले 3 सालों नाबार्ड में पड़ी है वो स्वीकृत नहीं हो रही क्योंकि रिएप्रोपिएशन के लिए आपका यह लैटर जा रहा है। जहां तक जल-शक्ति विभाग की है अब जब 12 करोड़ है तो क्यों वापिस आ रहा है। आप जो ये जबाब दे रहे हैं इस जबाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। यह जानबूझकर राजनैतिक आधार पर हो रहा है यह मैं कहना चाहता हूं। दूसरा जहां तक मंदिरों की बात है हम नहीं कह रहे हमने कहा आप मान लो हम ले रहे हैं लेना भी है और मना भी करना यह गलत बात है। आप ले रहे हैं और सुख आश्रय योजना को आपने लिया है 1 करोड़ नैना देवी से। आप स्वेच्छा और इच्छा नहीं होती आप उधर कह रहे हैं कि सवैछा नहीं होती अपने लिए आपकी सवैछा हो गई ऐसा नहीं होता। जो है आप मानो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मानो ना लिया है और जहां आप कह रहे है केन्द्रीय योजनाओं का तो अगर केन्द्रीय योजनाओं का पैसा ट्रेजरी में जाता तो यह चिठ्ठी क्यों निकलती यह समग्र शिक्षा की चिठ्ठी क्यों जाती डिप्यूटी डाइरेक्टर को कि आपके पास जो समग्र ऐजुकेशन का पैसा है वो ट्रेजरी में डालो आप सदन को गुमराह कर रहे हैं कि केन्द्र का पैसा ट्रेजरी में आता है अब रेलवे का पैसा बैंक में आता है बैकों को चिठ्ठी गई है सरकार की तो ये गुमराह कि ट्रेजरी में ट्रांसफर करो इसलिए यह कहना कि केंन्द्र का पैसा ट्रेजरी में आता है सरासर गुमराह करने वाला है। आप हमें गुमराह मत कीजिए। आप स्वीकार कीजिए कि आप मंदिरों से भी पैसा ले रहे हैं और आप केंद्रीय

योजनाओं का पैसा भी खर्च कर रहे हैं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : तो क्या हुआ, आपका नाम रिकॉर्ड पर है। आप (श्री जय राम ठाकुर) पोपुलर हो रहे हैं। ...(व्यवधान) अच्छा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप बोलिए। लेकिन अपनी बात शॉर्ट में कीजिए।

12.03.2025/1525/md/dc/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, बात बिल्कुल सीधी से है कि जब सरकार कोई गलत फैसला लेगी तो उस पर हम अवश्य टिप्पणी करेंगे और विरोध भी करेंगे। आप लोग भी अब सनातनी हो गए हैं क्योंकि आप भी अभी महाकुम्भ में स्नान करके आए हैं। इस तरह से आपने एक सबूत तो प्रस्तुत किया है कि आप सनातनी है। लेकिन सनातन के प्रति वह भाव दिल तक होना चाहिए। सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन की गई है वह विड्रो तो हुई ही नहीं है। हमारा प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके विभाग द्वारा नोटिफिकेशन की गई है कि सुख आश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना के लिए पैसा जमा कीजिए। वह नोटिफिकेशन वैसे ही स्टैंड कर रही है और आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे। कायदे से तो यह होना चाहिए कि नोटिफिकेशन विड्रो होनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि हमने यह फैसला वापिस ले लिया और आने वाले समय में हम मंदिर का पैसा नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपने भी लिया। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने वह पैसा सरकार चलाने के लिए नहीं लिया। अगर गऊ मां की सेवा करने के लिए हमने यह कहा कि मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत गऊ सदन पर 15 प्रतिशत तक खर्च कर सकते हैं। हमने इतनी ही बात कही है और इसमें क्या बुराई है? हमारी संवदेना उन बच्चों के प्रति हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं। आप इसमें क्या कम्पेरिजन करना चाहा रहे हैं। हम

उनकी सेवा करने के लिए कहां मना कर रह हैं? मगर जो सुख आश्रय योजना है, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी उसका मेज़र कम्पोनैंट मदर टैरेसा योजना से चल रहा है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

12.03.2025/ 1530/ केएस/एएस/1

श्री जय राम ठाकुर जारी--

माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, जो सुखाश्रय योजना है उसका मेजर कम्पोनेंट जो केंद्र सरकार की मदर टेरेसा योजना है, उससे चल रहा है। सिर्फ अपना नाम छाप कर आपने इस योजना को चला दिया। जब कोई योजना आपने शुरू की तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए बजट प्रोविजन्ज़ होते हैं। जो बजटिड स्कीम है, उसके तहत जो बजट प्रोविजन्ज़ किए हैं, उसके लिए मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेना उचित नहीं है, हम यह कह रहे हैं क्योंकि वह बजट में ऑलरेडी है। उससे आप पैसा खर्च कर लें। जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं, पैसा डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, सैलरी में देने की बात कर रहे हैं, यह हकीकत है कि आपको सैंट्रल स्पैशल असिस्टेंस का पैसा मिला। आपको अभी तक 2800 करोड़ रुपये मिल चुके हैं और ये फैक्ट्स हैं कि उसमें से लगभग 300 करोड़ रुपये उप-मुख्य मंत्री जी, आपके ही डिपार्टमैंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को दिए गए। आपने उस पैसे को आई0डी0बी0 में आगे दे दिया और उसके बाद किश्तों में वह पैसा वहां से निकलकर सैलरी और पैंशन में दे दिया। जहां गलत हो रहा है, उसको हमें कहना पड़ेगा और आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम इस बात को समझ सकते हैं कि हालात ऐसे हैं, जिसके मुताबिक आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सैलरी नहीं होगी, पैंशन नहीं होगी तो आपको लगता है कि विपक्ष वाले शोर डालेंगे। हम तो डालेंगे लेकिन सच्चाई स्वीकार करो और जैसे तेलंगाना के मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि गलतफहमी दूर हो गई, आप भी कह दीजिए कि हमारी भी गलतफहमी दूर हो गई तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद नये सिरे से आगे सोचेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है।

सरकार का लगभग ढाई साल का कार्यकाल बचा है। आपने जो गारंटियां दी हैं, उनको पूरा करने की बात आप कर सकते हैं, आपके पास वक्त है लेकिन जिस तरह से गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि हमने यह भी किया, हमने वह भी किया तो हम भी इसी जमीन पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। जो हुआ ही नहीं है, उसका ज़िक्र करेंगे तो विरोध तो होगा ही। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा सिर्फ यही कहना है कि गलत तथ्य प्रस्तुत करने की इस रिवायत को बंद करिए। ये जो अधिकारी आप लोगों को कुछ आंकड़े दे कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका थोड़ा वक्त

12.03.2025/ 1530/ केएस/एएस/2

निकल जाएगा लेकिन आगे प्रदेश का और हम सभी लोगों का वक्त बहुत खराब होगा, इस प्रदेश का भविष्य तबाह होगा, बर्बाद होगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : मेरा दोनों पक्षों से निवेदन है कि जब डिबेट हो रही है और एक के बाद एक माननीय सदस्य एक पक्ष से, एक प्रतिपक्ष से बोलता है तो इंटरवेंशन वहां रिक्वायर्ड है जहां कोई नया फैक्ट्स है, जिसको रिवर्ट करने की ज़रूरत है। जो डिस्कशन के प्वाइंट्स पहले ही आ चुके हैं, बार-बार उसके ऊपर रिवर्टल मेरे ख्याल में इस माननीय सदन के समय को व्यर्थ में spend करने की बात है इसलिए please if you want the time to be utilized properly then allow the other Hon'ble Members also to speak. अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी भाग लेंगे।

12.03.2025/ 1530/ केएस/एएस/3

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2025 को जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण यहां पर प्रस्तुत किया था, उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी लाए हैं और उसका अनुमोदन माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी ने किया है, आपने मुझे उसके ऊपर बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हमारी 10 गारंटियां थीं, उनमें से हमने 6 पूरी कर ली हैं। चाहे ओ0पी0एस0 की बात करें या 1500 रुपये देने की बात करें, कई जिलों में वह योजना भी शुरू की जा चुकी है। स्टार्टअप योजना के तहत उसके लिए भी मुख्य मंत्री महोदय ने कई करोड़ रुपये लगभग 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोविड के समय जो हमारी शिक्षा की दुर्दशा हुई थी, जो हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्रमें 21वें स्थान पर पहुंच गया था, मैं शिक्षा मंत्री जी की सराहना करना चाहता हूं कि अभी जो एसीईआर के माध्यम से केंद्र सरकार ने एक सर्वे किया है उसके तहत हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है उसके जिलए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

12.03.2025/1535/AV/एचके/1

श्री राकेश कालिया------ जारी

आपने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं जिनसे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आपने पूरे प्रदेश में 68 आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही है और इनके खुलने से प्रदेश की शिक्षा में एक गुणात्मक सुधार होगा। आपने प्रदेश के कुछ स्कूल्ज कंसोलिडेट भी किए हैं। कई स्कूल्ज में जहां पर दो-दो, चार-चार बच्चे रह गए थे उन स्कूल्ज को क्लब करने के उपरांत हमारे प्राथमिक पाठशालाओं की स्ट्रैंथ बढ़ी है। आपने पहली कक्षा से अंग्रेजी अनिवार्य कर दी है जिसके कारण बच्चों का अंग्रेजी के प्रति रूझान बढ़ा है। पहले हमारे सरकारी स्कूल्ज के बच्चों को दसवीं कक्षा के बाद सांइस और कॉमर्स पढ़ने में दिक्कत आती थी। मगर अब आपने प्रथम कक्षा से अंग्रेजी शुरू कर दी है जिससे हमारे सरकारी स्कूल्ज के बच्चों को बाद में सांइस और कॉमर्स के सब्जैक्ट्स पढ़ने में आसानी रहेगी क्योंकि यहां पर दसवीं के बाद सांइस अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़नी पढ़ती है। हालांकि उत्तर प्रदेश इत्यादि में बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी में भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई

देता हूं क्योंकि आपने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु प्रयास किए हैं जोकि एक सराहनीय कदम है।

यहां राज्यपाल महोदय का ही एक कार्यक्रम था कि ड्रग्ज़ के ऊपर रोक लगानी है। माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार ने एन0डी0पी0एस0 के तहत 11 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं जोकि नशे के ऊपर एक कड़ा प्रहार माना जा रहा है। मैं उसके लिए सरकार की सराहना करता हूं। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं थी फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश का संचालन बहुत अंच्छे तरीके से किया है। उसकी सराहना जब यहां पर बाढ़ आई थी तो केंद्र ने भी की थी और केंद्र के कई बड़े-बड़े समाचार पत्रों द्वारा भी इस बारे में सराहना की गई थी। हालांकि उस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा बहुत ज्यादा वित्तीय सहायता नहीं की गई थी। उस दौरान लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने संसाधनों से 5500 करोड़ रुपये खर्च करके प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया था। मुझे लगता है कि प्रदेश में कभी ऐसा नहीं

12.03.2025/1535/AV/एचके/2

कहा गया कि हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी है क्योंकि हमारे प्रदेश के अपने संसाधन कम हैं। मैं चार बार इस विधान सभा के लिए निर्वाचित हो चुका हूं लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा गया कि हमारी स्टेट रिच है और हमारे पास एक्सैस पैसा है। हम कोई भी योजना केंद्र सरकार की सहायता के बिना अपने आप शुरू कर सकते हैं। यहां पर हमेशा यह सवाल रहा है कि केंद्र से पैसा आएगा तभी हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल इत्यादि विकास के कार्य होंगे। हमें केंद्र सरकार से एक माकूल सहायता मिलती है। हमारे विपक्ष के साथी यहां पर बार-बार कहते हैं कि यह पैसा तो केंद्र भेज रहा है। आप हमें यह बताइए कि क्या हम केंद्र में कंट्रीब्यूट नहीं करते? हमारा जी0एस0टी0 केंद्र को जाता है, हमारे लोगों का इन्कम टैक्स केंद्र में कंट्रीब्यूट होता है। हमारा जायज हिस्सा हमें अवश्य मिलना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि दोनों फसलों का एम0एस0पी0 जिसके बारे में केंद्र में बड़ा

हो-हल्ला किया जा रहा है और उसके लिए किसान कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सरकार गेहूं और मक्का के ऊपर क्रमशः 40 रुपये व 30 रुपये प्रति किलोग्राम एम0एस0पी0 दे रही है। यहां पर एक साथी कह रहे थे कि गोबर बहुत है। मगर गोबर दो रुपये तो वैसे ही नहीं मिलता। मगर हमारी सरकार ने गोबर खरीद कर पशु पालकों को प्रोत्साहन तो दिया है और तब से यह पता तो चला कि हमारे प्रदेश में गोबर की कितनी अहमियत है। हम जब भी गोबर की खाद खरीदने जाते हैं तो 4000 रुपये से कम ट्रॉली नहीं मिलती। मेरे एक साथी कह रहे थे कि यहां पर गोबर तो ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सूखे गोबर की बोरी खरीदने जाओ तो वह आपको 500 रुपये से कम नहीं मिलेगी। हमारी सरकार गोबर के रेट फिक्स करके किसानों को प्रोत्साहन दे रही है तो यह एक अच्छी बात है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक बार एक प्रदेश में बहुत ज्यादा कपास पैदा हो गया और उसको घोड़ों पर लाद कर कहीं ट्रांसफर कर रहे थे। वहां से हजारों घोड़े निकल रहे थे और एक बुढ़िया उन घोड़ों को देख रही थी कि इतनी कपास के घोड़े यहां से निकल रहे हैं तो वह उसको देखकर बेहोश हो गई।

टी सी द्वारा जारी

12.03.2028/1540/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री राकेश कालिया ... जारी

और वे घोड़ों पर लाद कर उसको ट्रांसफर कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला यह दृश्य देख रही थी और वह सोचने लगी कि इतनी कपास लेकर घोड़े यहां से जा रहे हैं तो वह उनको देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया और उससे पूछा गया कि वह बेहोश क्यों हुई? तो उसने जवाब दिया कि मैं सोच रही थी कि इतना कपास कातेगा कौन? मेरे विपक्ष के साथियों का भी यही हाल है। वे सोच रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है जबकि उन्हें लगता था कि यह सरकार चलनी ही नहीं चाहिए थी, इसे तो अब तक टूट जाना चाहिए था।

आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। श्री रणधीर शर्मा जी और श्री विपिन सिंह परमार जी जो मेरे पुराने मित्र व हमारे साथी रह चुके हैं। श्री परमार जी तो विधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे बीच में बार-बार व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं। मैंने भी इनको चर्चा के दौरान टोका था जोकि इन्होंने याद रखा हुआ था हालांकि मैंने इसके लिए इनसे क्षमा भी मांग ली थी। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप प्रदेश के हित में केंद्र सरकार के पास जाएं और और केन्द्र सरकार को बताएं कि आप हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। केंद्र को चाहिए कि वह प्रदेश के साथ न्याय करें और प्रदेश की योजनाओं पर बेवजह आपत्ति न लगाएं।

मैं हाल ही में एक समिति की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मैंने पाया कि केंद्र सरकार ने हमारी जल योजनाओं की 931 करोड़ रुपये की राशि रोक रखी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि प्रदेश के हित में मिलकर काम करें और केंद्र से हमारा हक दिलाने में सहयोग करें। आलोचना करना जरूरी है, लेकिन बेवजह की आलोचना से कुछ हासिल नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद.

12.03.2028/1540/टी0सी0वी0/एच0के0-2

सभापति : अब इस चर्चा में श्री रणवीर सिंह निक्का जी भाग लेंगे।

श्री रणवीर सिंह निक्का : सभापति महोदय, दिनांक 10 मार्च को माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया, उस पर भवानी सिंह पठानिया जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, पैरा संख्याः 3 में बताया गया कि कांग्रेस सरकार द्वारा 6 गारंटियां पूरी कर ली गई हैं। अब मैं इसके पैरा संख्या 7 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें बताया गया कि गोबर की खरीद की गारंटी पूरी कर ली गई है। सवा दो सालों के अंदर कुल 401 क्विंटल वर्मी खाद बनाई गई और उसको 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। इस अभिभाषण के पैरा संख्याः 16 में बताया गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई गारंटी के

अनुसार 100 रुपये प्रति लीटर हिसाब से दूध खरीदा जाएगा। लेकिन दो साल के अंदर गाय का दूध 31.80 रुपये से बढ़ाकर मात्र 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध का मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये किया गया है। आपकी यह गारंटी भी अधूरी है। इस तरह से कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और बताते हैं कि हमारी गारंटी पूरी हो गई है।

सभापति महोदय, यदि पैरा नंबर 59 की बात करें तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 21.93 करोड़ रुपये का जिक्र किया गया है और 1500 रुपये देने की घोषणा की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा और मेरी विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में किसी भी महिला को एक रुपया तक नहीं मिला है। यह भी आपका झूठा वायदा और झूठी गारंटी है। इस तरह से पूरे प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पैरा संख्याः 37 में कहा गया कि स्कूलों के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कई प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन स्कूलों का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें 8-8, 10-10 कमरे हैं और लगभग 8 कनाल से लेकर 15 कनाल तक की जमीन है। जब वे स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है और इन जमीनों पर लोगों का अवैध कब्जा होने का खतरा भी बढ़ रहा है। वहां पर पढ़ने वाले चाहे दो ही बच्चे होते और उनके लिए आप शिक्षक भी आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त कर सकते थे। इससे न केवल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहता बल्कि बच्चों को भी पढ़ाई का मौका मिलता।

12.03.2028/1540/टी0सी0वी0/एच0के0-3

इन स्कूलों के बंद होने की वजह से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है क्योंकि दूसरा स्कूल वहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे छोटे बच्चों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है।पैसा नंबर 86 में आपने स्वास्थ्य सुविधाओं में 16.67 करोड़ रुपये की लागत से आई0जी0एम0सी0 शिमला में सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगाने का जिक्र किया है।

एन0एस0 द्वारा .. जारी

12-03-2025/1545/ns-yk/1

श्री रणवीर सिंह (निक्का)------ जारी

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नूरपुर में सिविल अस्पताल है और वहां पर आज दिन तक अल्ट्रासाउंड करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। वहां पर मातृ-शिशु अस्पताल बन कर तैयार है लेकिन सरकार वहां के लोगों को यह सुविधा देने में असमर्थ है। यहां पर बार-बार जिक्र किया जा रहा है कि सरकार ने मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के डमटाल में राम गोपाल मंदिर है और वहां से 10 करोड़ रुपये की राशि शिफ्ट कर दी गई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस मंदिर के खाते में लगभग 28 करोड़ रुपये हैं। मेरा निवेदन है कि इन्दौरा, फतेहपुर, नूरपुर और ज्वाली विधान सभा क्षेत्रों के लिए एक मेडिकल कॉलेज या ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र से मेडिकल कॉलेज, टांडा की दूरी 80 किलोमीटर है। नूरपुर में जब भी कोई एक्सिडैंट होता है तो उपचार करवाने के लिए पठानकोट जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज, टांडा दूर होने के कारण कई व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पैरा नम्बरः 47 में खिलाड़ियों के लिए जिक्र किया गया है कि खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाले खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं और प्रदेश से बाहर जाने पर 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी नूरपुर दौरे पर गए थे। वहां पर एक खिलाड़ी खज्जियां से हैं जिसका नाम गौतम जरयाल सुपुत्र श्री रजिन्दर जरयाल है। उसको स्कूल में खेलते-खेलते चोट लग गई। उसके दादा जी मेरे पास आए और मैंने मुख्य मंत्री जी को उनका पत्र भी दिया और उनको इनसे मिलवाया भी है। उसका उपचार एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है और उसको सरकार की ओर से एक रुपये की मदद नहीं दी गई है। मेरा मानना है कि जब भी किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए।

सभापति महोदय, नूरपुर में लोक निर्माण विभाग की सड़कें पिछले सवा दो वर्षों से खराब हैं। वड़वार से लेकर लदौड़ी गांव की सड़क का बड़ा बुरा हाल है और वहां पर बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं। पक्का डाला से ले करके बरंडा सड़क की पिछले दो सालों से मरम्मत नहीं हुई है। खुशी नगर से लेकर खेरियां, मिंजग्रां, बदूही पंचायतों

12-03-2025/1545/ns-yk/2

की सड़कों की हालत दयनीय है। नूरपुर अस्पताल से सदवां सड़क की भी हालत खराब है। मैंने विधायक प्राथमिकता की बैठक में दो बार नूरपुर की प्राथमिकता रखी है। लेकिन आज दिन तक उनकी डी0पी0आर्ज0 बन कर तैयार नहीं हुई हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इनकी डी0पी0आर0 शीघ्र बनाई जाए ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, अभिभाषण में पैरा संख्या : 31 में जिक्र किया गया है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 47 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है जिसमें से वर्तमान वर्ष में 21 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। जीवंत ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत 1.35 करोड़ रुपये का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में नूरपुर, इन्दौरा, फतेहपुर का एरिया आता है और उस सीमा पर कोई भी बाउंड्री वॉल या पिल्लर नहीं लगे हैं। मेरा आग्रह है कि वहां पर निशानदेही करवा कर बाउंड्री वॉल व पिल्लर लगाए जाएं ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। फतेहपुर के तलवाड़ा में लगभग 10 स्टोन क्रशर्ज हैं। ये क्रशर्ज पंजाब की बाउंड्री के ऊपर लगे हैं और पंजाब से रात के अंधेरे में आ करके हिमाचल के मिनरल का नुकसान कर रहे हैं। इन्दौरा में भी पंजाब के साथ लगते क्षेत्र में 8 स्टोन क्रशर लगे हैं। वहां से भी रात के अंधेरे में हिमाचल का मिनरल चोरी होता है।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

श्री रणवीर सिंह (निक्का) जारी.....

अगर मैं नूरपुर क्षेत्र की बात करुं तो यह क्षेत्र पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां पर आधा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का और आधा पंजाब का है। इस क्षेत्र में कुल 10 स्टोन क्रशर स्थापित किए गए हैं। वहीं इस सीमा क्षेत्र में कुल 28 ऐसे स्टोन क्रशर्ज हैं जो रात के अंधेरे में चोरी से खनन करते हैं जिससे हमारे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में एक कमेटी गठित की जाए। इसमें इन्दौरा के विधायक, श्री मलेन्द्र राजन, फतेहपुर के विधायक, श्री भवानी सिंह पठानिया और नूरपुर से मुझे शामिल किया जाए। मेरा यह अनुरोध है कि इन तीन विधायकों की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए ताकि हम सरकार को रिपोर्ट पेश कर सकें और यह बताएं कि इन गुप्त रास्तों से रात के समय अवैध खनन हो रहा है। मेरा आग्रह है कि इसके लिए माइनिंग गार्ड तैनात किए जाएं और पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है ताकि जो 28 स्टोन क्रशर्ज़ दिन-रात चलते हैं उनकी अवैध गतिविधियां रोकी जा सकें और प्रदेश के राजस्व को भी नुकसान न हो। इस अभिभाषण के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से कई बातें कहलवायीं। अब मैं कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इस योजना से हिमाचल प्रदेश के लोगों को काफी राहत मिल रही है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की किस्त भेज रही है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हर विधान सभा क्षेत्र में हजारों मकान वितरित किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश को लगभग 93,300 मकान प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई नई सड़कें बन रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मुफ्त राशन भी उपलब्ध करवाया गया है लेकिन इन सब योजनाओं का उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। आपको इस अभिभाषण में श्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना करनी चाहिए थी।

सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह बबलू इस चर्चा में भाग लेंगे।

12.03.2025/1550/RKS/वाइके-2

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। कल भी इस अभिभाषण पर चर्चा हुई थी और आज भी प्रश्न काल के बाद चर्चा जारी है। यहां यह कहा गया कि महामहिम राज्यपाल से झूठे दस्तावेज़ पढ़वाए गए जो कि मेरे विचार से बहुत ही अशोभनीय है। अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर जो बात कही मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं क्योंकि महामहिम राज्यपाल की कुर्सी की गरिमा पर विपक्ष ने प्रश्नचिन्ह लगाया है। इस पर अध्यक्ष महोदय की बात से मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बात कही थी और शायद आज भी यह चर्चा हो रही थी कि आप सनातन धर्म का विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपने सनातनी और हिंदू होने का प्रमाण-पत्र इनसे नहीं चाहिए। हम इनसे कहीं अधिक सनातनी और हिंदू हैं।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

12.03.2025/1555/बी.एस./ए जी./-1

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) जारी...

हमारे मुख्य मंत्री जी, उप-मुख्य मंत्री जी और हमारे कई नेतागण कई तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और हमेशा जाते रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता कभी भी उस पर धर्म की राजीति नहीं करते हैं। लेकिन भाजपा का एक एजेंडा रहा है कि ये धर्म पर राजनीति करते हैं और उस पर वोट मांगते हैं। मैं यह समझता हूं कि उप-मुख्य मंत्री जी की धर्मपत्नी, जिनका निधन एक वर्ष पहले हुआ वे हर साल हरौली से माता चिन्तपुरनी जी और वहां से ज्वालाजी तक पैदल यात्रा करती थीं। जिस दिन उनका निधन हुआ उससे पहले भी

उन्होंने पैदल यात्रा की थी और निधन के 10 दिन बाद भी उन्होंने महामाई के जागरण का कार्यक्रम रखा हुआ था। मैं यह समझता हूं कि भाजपा के लोगों और इनके परिवारों के लोगों ने इस प्रकार की पद यात्रा मंदिरों की नहीं की होंगी। परंतु कांग्रेस के लोग कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते। धर्म को कैसे मानना है और कैसे मानते हैं, यह हमने इनसे नहीं सीखना है। सभापति महोदय, अभी हाल ही में आपकी अध्यक्षता में विधान सभा कमेटी का टूअर प्रदेश से बाहर गया था वहां पर हम 30 धार्मिक स्थलों के दर्शन करके आए हैं, परंतु हमने उसे कभी भी शोसल मीडिया में नहीं फैलाया।

सभापति : आप तो गंगा सागर में नहा करके आए हैं।

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) : सभापति जी, हम आपकी अध्यक्षता में यह सब कर पाए हैं। भाजपा से भी हमारे दो माननीय सदस्य आदरणीय प्रकाश राणा जी और आदरणीय लोकेन्दर जी हमारे साथ थे। अध्यक्ष महोदय, जब हमें यह बोला जाता है कि आप संनातन का विरोध करते हैं, ऐसी बातें माननीय सदन के अंदर नहीं बोली जानी चाहिए। क्योंकि हमारी जो धर्म के प्रति आस्था है उसके ऊपर भी प्रश्नचिन्ह लगाने का प्रयास किया जाता है और उसमें ठेस भी पहुंचती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उप-मुख्य मंत्री जी की धर्मपत्नी का निधन हुआ उसके बाद उन्होंने पैदल यात्रा माता चिन्तपुरनी तक की और उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री जी ने भी पैदल चल कर यात्रा की है। इसलिए ऐसी बातें करना उचित नहीं है। दूसरा इनकी राजनीति तो धर्म और जातपात के ऊपर ही चलती है। माननीय सदन इतना पवित्र स्थान है यहां पर किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी ही नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जो राजा होता

है उसका कोई धर्म नहीं होता है। हमारे लोगों ने हमें चुन करके भेजा है तो हमारा धर्म हमारी प्रजा है, हमारी जनता है। हमें जब भी बात करनी है तो हमें अपनी जनता की बात करनी चाहिए न कि किसी धर्म की बात करनी चाहिए और न ही किसी के ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन लगाने चाहिए। अगर में इनके संनातन की बात करूं, जैसा ये बोलते हैं कि ये बड़े संनातनी हैं। मैं विधायक बना उसके बाद मैं अलग-अलग जिलों में गया। ऐसे ही मुझे

मण्डी की शिवरात्रि में जाने का मौका मिला। मैंने वहां के इतिहास को जाना कि वहां पर जो हमारे देवी-देवता हैं उनके नाम से अन्तर्राष्ट्रीय मेले होते हैं। मैंने भी अपने चिन्तपुरनी जी में निर्णय लिया, क्योंकि में वहीं से चुन करके आया हूं। मैं मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उसी समय वहां पर प्रशासन को जिला स्तरीय कार्यक्रम करवाने के आदेश दिए। जब हमने चिन्तपुरनी जी के महोत्सव का इंसिएटिव लिया और काम करना शुरू किया तो हम माता रानी की जोत चिन्तपुरनी जी से अंब तक ले करके आए और माता रानी की पिंडी को हमने वहां पर स्थापित किया। लोगों ने वहां पर माता जी के दर्शन किए और वहां पर तीन धार्मिक संध्याएं माता चिन्तपुरनी जी के नाम से आयोजित करवाई। परंतु उसका विरोध करने के लिए भाजपा के लोग सामने आए और इन लोगों का असली चेहरा सामने आया। हमारे पूर्व विधायक ने विरोध किया, माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी की वहां पर स्टेटमेंट आई कि यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये लोग कितना संनातन को मानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, उप-मुख्य जी का जिन्होंने पहले ही कार्यक्रम को राज्य स्तरीय करने का दर्जा दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इस फेयर को अन्तर्राष्ट्रीय फेयर तक ले करके जाएगी।

दूसरी बात सर, उस कार्यक्रम के माध्यम से पहली संध्या में उप-मुख्य मंत्री जी वहां पर मौजूद रहे। हमने करोड़ों रुपये की डिमांग उस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के लिए की। अगले दिन के कार्यक्रम में आदरणीय आर0एस0 बाली जी वहां पर आए तथा अंतिम संध्या में आदरणीय धर्माणी जी मौजूद रहे। हमने मंत्रिगण से अलग-अलग डिमांड की है। इस कायक्रम के माध्यम से जितने भी मंत्री वहां पर आएंगे हम उनसे ज्यादा से ज्यादा बजट की डिमांड करेंगे ताकि इस बजट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो सके।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

12.03.2025/1600/DT/AG-1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी...

हमारे जितने भी मंत्रीगण वहां पर आएंगे तो हमारे चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र के लिए बजट का प्रावधान होगा।

दूसरी बात जो इस माननीय सदन में हो रही है वह मंदिरों से पैसा लिए जाने के बारे में है। पिछली सरकार के कार्यकाल में कोविड महामारी के समय भी मंदिर ट्रस्टों से पैसा लिया गया। वर्तमान सरकार ने सुखाश्रय योजना के अंतर्गत अगर अनाथ बच्चों के लिए पैसा लिया गया तो इसमें बुराई क्या है? क्या उस पैसे की फंडिंग हम पाकिस्तान को कर रहे हैं? हम यह पैसा गरीब और अनाथ बच्चों के लिए ले रहे हैं। यह तो वही बात हो गई कि "आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी"। यहां पर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए की प्रदेश सरकार प्रदेश के हित के लिए काम कर रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इनके द्वारा अहम फैसले प्रदेश की जनता के लिए गये। आज जो हमारे विपक्ष के साथी प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस हालत की जिम्मेवार भी प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ही है। इन्होंने प्रदेश की संपदा को लुटाया। लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सक्खू जी व उनका पूरा मंत्री मंडल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में लगा है और मैं समझता हूं कि भविष्य में हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। पंजाबी भाषा में एक कहावत है कि हाथ की दी हुई गाठ्ठें मुंह से खोलनी पड़ती हैं, इसलिए जो गांठें पूर्व सरकार के द्वारा लगाई गई हैं उन गांठों को खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। पिछले दो वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो फैसले लिए गये हैं,उसमें से सबसे बड़ा फैसला सुखाश्रय योजना का है जिसके कारण अनाथ बच्चों के चेहरों पर आज खुशाी दिख रही है। जो समझते थे कि इस संसार में हमारा कोई सहारा नहीं है यह सरकार उनका सहारा बनी है। ऐसा हम सोशन मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं। उन बच्चों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जिन बच्चों के साथ पहले सौतेला व्यवहार होता था उन बच्चों में आज आत्मविश्वास आया है। उन्हें अब लग रहा कि आज हमें देखने वाला कोई-न-कोई है। उनके लिए सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। जिस तरह अनाथ बच्चों को विदेश के टूर करवायें जा रहे हैं, यह सरकार का एक बहुत ही

12.03.2025/1600/DT/AG-2

सराहनीय कार्य है। इसके अलावा विधवा नारी और एकल नारी के हितों के लिए जो सरकार कर रही है वह भी सराहनीय है। आज जो महिलाएं छोटी आयु में ही विधवा हो रहीं हैं उनके बच्चों को पढ़ाने का खर्चा सरकार वहन कर रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। ये ऐसे ऐतिहासिक निर्णय है जो वर्तमान सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। हमें 75000 करोड़ रुपये का कर्जा विरासत में मिला है। उसके बाद भी सरकार ने अच्छे फैसले लिए हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को ओ.पी.एस. दी। सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये देने के बारे में कहा था उसकी शुरुवात जिला लाहौल-स्पिति से कर दी गई है। वर्तमान सरकार के सवा दो साल में से छः महीने तो आपदा में निकल गये हैं। उसके बाद लोक सभा के चुनाव में कुछ समय निकल गया। इसलिए मैं समझता हूं कि अब सरकार को अच्छा काम करने के लिए समय मिला है। जो सरकार कदम उठा रही है उससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होगी। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष कभी समोसे का मुद्दा लेकर आ रहा है, कभी मुर्गे का मुद्दा लेकर आ रही है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था और हिमाचल दस्तक ने जो मुर्गा डाला था उसमें जो नीचे कमेंट पढ़े उसमें किसी ने भी इनकी फेवर में रिव्यू नहीं दिया। लोगों ने कहा कि अगर आप विपक्ष की सही भूमिका निभाते हुए जनहित के मुद्दे रखते तो हम आपकी प्रशंसा करते। मैं समझता हूं कि विपक्ष वाले मुद्दाहीन बातें करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब पूर्व में स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय चिन्तपुरनी विधान सभा में दो नये कॉलेज खोले गए थे। एक चौकी में और दूसरा चिन्तपुरनी में कॉलेज खोला गया था। चौकी में दो स्कूल के कमरों में कॉलेज खोला था क्योंकि सरकार बदल गई और यह काम पूरा नहीं हुआ था। मैंने इस बारे में शिक्षा मंत्री से बात की और शिक्षा मंत्री ने उसी समय 14 करोड़ रुपये की राशि उस कॉलेज के लिए स्वीकृत की। वहां पर तीन लैंटर का कार्य पूरा हो चुका है। शिक्षा मंत्री जी उसका भूमि पूजन करके आए थे। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। अगर मैं जल शक्ति विभाग की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पूर्व में विधायक रहे उनके पास पाइपों की फैक्ट्री होती थी। उन्होंने 2200 करोड़ रुपये की पाइपें सरकार को बेची लेकिन वह पाइपें कहां लगी उसका हमें मालूम नहीं। वहां पर कोई काम नहीं हुआ।

श्री एन.जी.द्वारा जारी...

12.03.2025/1605/ए.एस.-एन.जी./1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू.....जारी

आज जल शक्ति विभाग में एक क्रांति आई है। हमने हर घर में नल पहुंचाने का काम किया है और मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले में चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र पूरे हिमाचल प्रदेश में नम्बर एक बनने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं रोड्स के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में शहीद अमोल कालिया जी, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी शहादत दी थी, के नाम पर एक रोड बनाया जाना था। वह रोड मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत किन्नू व राड़ा-पाड़ा आदि क्षेत्रों के अलावा अनेक ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। इस रोड के लिए काफी लम्बे समय से मांग की जा रही थी। लेकिन पूर्व प्रदेश सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में इस रोड के लिए एक रुपया भी नहीं दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री व माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने इस रोड के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा मेरे क्षेत्र के जवाहर से नारी से बिल्ला से थप्पल रोड के लिए भी लगभग 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ढ़ेरा से मरकवाड़ा वाया चौकी मयार रोड के लिए भी लगभग 13 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बड़ुही से डुमखर रोड के लिए भी लगभग 6.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ रुपये के विकास कार्य चले हुए हैं।

सभापति महोदय, जब मैं विधायक बना तब मेरे क्षेत्र के सिविल अस्पताल, अम्ब में केवल तीन डॉक्टर्स हुआ करते थे लेकिन आज सात डॉक्टर्स हैं। मेरे क्षेत्र की महिलाओं को अपना चैकअप करवाने के लिए ऊना या होशियारपुर जाना पड़ता था। अब हमने अम्ब में ही गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बैठा दिया है जिससे महिलाओं को अन्य स्थानों पर

12.03.2025/1605/ए.एस.-एन.जी./2

नहीं जाना पड़ता। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को मालूम पड़ा कि हमें गायनी के साथ-साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी जरूरत है तो इन्होंने सिविल अस्पताल, अम्ब में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी उपलब्ध करवा दिया। इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, हमारा ऊना जिला कृषि के मामले में सबसे अग्रणी जिला है। हमारी सरकार ने दुग्ध के रेट्स में ऐतिहासिक वृद्धि की है। जिस कारण हमारे किसानों के चहरों पर खुशी के भाव आए हैं। मैं स्वयं किसान परिवार से संबंध रखता हूं और मेरे घर पर रोजाना लगभग 30 लीटर दुग्ध का उत्पादन होता है। दुग्ध के रेट्स में वृद्धि होने से किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की टकारला पंचायत से पूर्व बी0डी0सी0 चेयरमैन, श्री देवेन्द्र लाठी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि देसी गाय के घी को उन्होंने 2500 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा है। जब प्रदेश सरकार ने दुग्ध के दामों में वृद्धि की तब लोगों ने पशुओं को पालना शुरू किया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धंदड़ी में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है और इसके लिए पांच करोड़ रुपये देने का भी आश्वासन दिया है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने जाते-जाते आनन-फानन में हर जगह उद्घाटन व शिलान्यास करने शुरू कर दिए थे। पूर्व सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्थोथर के पुल का बिना बजट के ही शिलान्यास कर दिया था।

मैंने माननीय मुख्य मंत्री व माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से बात की है और अब हमारी सरकार उस पुल के लिए बजट का प्रावधान कर रही है।

12.03.2025/1605/ए.एस.-एन.जी./3

सभापति महोदय, हमारी सरकार मेरे क्षेत्र के लिए बहुत अहम फैसले ले रही है और उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय जी ने प्रदेश सरकार की दो साल की उपलब्धियों को अपने अभिभाषण में पढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ है कि यहां पर राज्यपाल महोदय जी आए और उन्हें जबरदस्ती करके बोला गया कि इस अभिभाषण को आप पढ़ दीजिए। यह कोई बदमाशी वाला सिस्टम नहीं है। यह एक संविधानिक दस्तावेज है जिसको कैबिनेट से अनुमति मिली है और उसके बाद वह राज्यपाल महोदय जी के पास जाता है। राज्यपाल महोदय उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं और उसके बाद यह दस्तावेज फाइनल होता है। प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति सही न होने के बाद भी सरकार ने हर वर्ग को फायदा पहुंचाया है।

Chairman : Please wind-up now.

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : सभापति महोदय, आज मनरेगा की दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

12.03.2025/1610/AS-PB/-1

श्री सुदर्शन सिंह(बबलू) जारी...

मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ पंचायतें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें पलियां पंचायत में ऐंबुलेंस रोड़,

स्तोथर पंचायत में पुल व ऐंबुलेंस रोड, धर्मशाला के महंता पंचायत में, गुरेट पंचायत में, खरयालता पंचायत में ऐंबुलेंस रोड के लिए मैं अपनी माननीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री हंस राज अकरोट जी ने एक कृषि अनुसंधान उप-केंद्र खोला था। हमारा ऊना जिला एक कृषि प्रधान जिला है, यहां पर कृषि विभाग में कर्मचारियों के कुछ पद खाली है उनको भरने का मैं सरकार से आग्रह करता हूं। हमारे जिले के लोगों को खेती-बाड़ी के लिए प्रेरित करें। हमारी बेड़ जस्वां पंचायत के अंदर अकरोट जगह पड़ती है उसके लिए भी मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बजट का प्रावधान किया जाए। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायती राज के अंतर्गत पंचायत भवन निर्माण हेतु कठोह पंचायत को 1.14 करोड़ रुपये, दुसाड़ा को 1.14 करोड़ रुपये, सांगड़ा को 1.14 करोड़ रुपये, धनदरी को 1.14 करोड़ रुपये, गेबट भेहड़ा को 1.14 करोड़ रुपये, पलियां को 1.14 करोड़ रुपये, नेहरी को 35 लाख रुपये और गंगरेट को 35 लाख रुपये दिए गए। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। खासतौर पर माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरूद्ध सिंह जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये राशियां रीलीज़ करवाई हैं। सब पंचायत भवनों के टेंडर हो गए हैं और हर एक पंचायत घर का काम चला हुआ है। सरकार ने हमारे नौजवान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो कदम उठाएं हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र से पैरालंपिक में मैडल जीतने वाले निषाद कुमार को हमारी सरकार ने 7.80 करोड़ रुपये से नवाज़ा है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय खेल मंत्री श्री यादविंदर गोमा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वह महामहिम राज्यपाल जी ने यहां 1.30 घण्टा लगाकर गिनवाईं। यदि विपक्ष को विरोध करना था तो उस समय ही विरोध करते। उस समय ये विरोध नहीं कर सकते थे इसलिए अब खामियां निकाल रहे हैं कि यह दस्तावेज गलत है और महामहिम राज्यपाल जी के

12.03.2025/1610/AS-PB/-2

पद की गरिमा पर जो सवाल उठाया जा रहा है वह भी गलत है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का इस विषय पर रूलिंग देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आज जो प्रदेश की स्थिति है वह कांग्रेस की वजह से नहीं है। प्रदेश सिर्फ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का नहीं है यह प्रदेश हिमाचल प्रदेश की जनता का है। आज अगर प्रदेश के हितों की बात की जा रही है और केन्द्र से पैसा मांगा जा रहा है तो इसके लिए विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए। प्रदेश में सरकारें आती जाती रहती हैं परंतु प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें जनता ने चुकर भेजा है। हमें अपने लोगों के हितों की बात रखनी चाहिए अगर एक जुट हो कर प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए चाहे वह केन्द्र से पैसों की सहायता की लड़ाई हो या चिट्टें के खिलाफ हो। प्रदेश को बचाने के लिए यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो हमारा प्रदेश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री भवानी सिंह पठानिया जी द्वारा इस सदन में लाया गया है उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद, जय हिन्द, जय हिमाचल, जय मां चिन्तपुरनी।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी भाग लेंगे।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1615/A.P/D.C/01

सभापति : माननीय सुखराम चौधरी जी।

श्री सुखराम चौधरी : आदरणीय सभापति महोदय जी, 10मार्च, 2025 को महामहिम राज्यपाल जी ने द्वारा दिये गये अभिभषण कि चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। प्रदेश में जब विधान सभा के चुनाव थें, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की दूर-दराज की कोई भी दिवार खाली नहीं छोड़ी, जिसपे अपनी 10 गारंटियों का जिक्र न किया हो ताकि लोगों को अवगत रहें और उसमें लिखा की सरकार बनने के तुरंत बाद पहली केबिनेट में 18-60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देगे। राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के बारे

में दिवारों में लिखा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा 10-10 करोड़ रुपये बेरोज़गारों को लोन व सब्सिडी के रूप में देगें, इसके अलाव बाकी 10 गारंटिया भी दी। आज बार-बार वे एक बात की चर्चा करते है कि हम चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी को पूरा करेगे। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं कि वह चरणबद्ध तरीका कौन-सा है? हमें भी पता चले ताकि हमारी विधान सभा क्षेत्र में भी लागू हो सके। मुख्यमंत्री जी लाहोल-स्पिति व चौपाल गए ओर वहां कि महिलाओं को 1500 रुपये दे दिये। यह कौन सा चरणबद्ध तरीका है? आज हम इस बात को हम मान सकते थें अगर मुख्यमंत्री जी यह घोषणा करते कि मैं 50, 40 व 30 साल के ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दें रहा हूं तब तो यह बात जायज़ है, यह तो आप इलाकेवाद की बात कर दी, देनी किसी को नहीं और बातें आसमान की कर रहे हो। 41 हज़ार पेंशने पूरे साल में लगी, उसमें से 20,000 पेंशने तो उन महिलाओं को लगी जिनकी उम्र एक साल पहले 60 साल पूरी हुई। आपने साल में कितनी पेंशने लगाई, सिर्फ 20,000 यह आपकी घोषणा का हाल है और आपने इसमें लिख दिया कि आपने चरणबद्ध तरीके से घोषणा पूरी कर दी। इनका चरणबद्ध तरीका दो सालों से पूरा ही नहीं हो रहा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि आप हिमाचलवासियों की आखों में धूल नहीं झोंक सकते लोग समझदार हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने घोषणाएं आपने पूरी नहीं की, आप टाल-मटोल कर रहे हैं, इधन-उधर की बाते करके आप सबको उलझा रहे हो, पीक एण्ड चूज़ की तरह अपने राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरू की होगी कुछ विधान सभा

12.03.2025/1615/a.p/d.c/02

क्षेत्रों में। इंसेंटिव अगर आप कृषि क्षेत्र को देते हो, उसे भी आप राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना में जोड़ देते हो। इसकी के साथ आपने कहा कि हमने 45 रुपये गाय व 55 रुपये प्रति लीटर का दूध कर दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो 60 रुपये लीटर ओपन बिकता है गाय का दूध, 70 रुपये लीटर भैस का दूध है और आप दें रहे हैं 45 व 55 रुपये। इसलिए ऐसा है जो आपने वास्तविक घोषणा की 80 रुपये लीटर गाय और 100 रुपये लीटर भैस

का दूध, उसका इंतजार कर रहें है हिमाचल प्रदेश के गांव के लोग कि कब यह घोषणा पूरी होगी। फिर आपने कहा दो रुपये प्रति किलो गोबर लेगे। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा हम जैविक खाद तीन रुपये प्रति किलो लेगे। आपको मैं बता दूं कि 10-15 रुपये प्रति किलों तो बाज़ार में बिक रही है। आपको कौन देगा 3 रुपये प्रति किलो खाद? इसलिए यह लोगों को झुनझूना मत दिखाओं व छोटे लालच मत दों। असलियत में जो आपसे हो सकता है वह करें, आप अंग्रेजी मीडियम की बात कर रहे हो स्कूलों में पढाने की, वहां अध्यापक तो हैं नहीं , एक-एक अध्यापक 5-5 कक्षओं को पढ़ा रहा है और फिर आप कह रहे हैं कि पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए। इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता तब आएंगी जब आप मूलभूत सुविधाएं स्कूलों को देगें। इस तरह से न तो वह हिंदी पढ़ पाएंगे और न ही अंग्रेजी, आप उनको कहीं का भी नहीं छोड़ेगे। यह सब घोषणाएं आपके गले में अटक गई है। आप बता क्यों नहीं देते कि हम यह घोषणाएं पूरी नहीं कर सकते? हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा बोल के हिमाचल प्रदेश के लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो जाएंगा। इसके इलाव मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ एक बातें यहां इस मंच पर करना चाहता हूं। मैं नई स्कीम की कोई बात नहीं करना चाहता।

ए0टी0 द्वारा जारी.....

12.03.20205/ 1620/AT/ एम0डी /.1

श्री सुख राम चौधरी :

मुझे लगता हमारे विधानसभा क्षेत्र को तो अपने लावारिस छोड़ दिया कोई काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में आप करते नहीं हो और जो काम हमने शुरू किया मैं उनकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं वह कब पूरे होंगे । हमारे क्षेत्र में पिछले दिनों बरसात आई ,रोहित ठाकुर जी हमारे कमेटी के अध्यक्ष थे हर्ष वर्धन जी हमारे मेंबर थे मीटिंग में आये डी0सी0 ऑफिस में 6, 7 पंचायतों का एक छोटा सा वरिज गिर गया था पिपली वाला में 2023 की बात में बता रहा हूं मुझे उसे समय रोहित ठाकुर जी ने भी कहा 6 महीने के अंदर तैयार करके देंगे छोटी सी तो बात है 6 महीने में तैयार कर देंगे तो हमने विश्वास किया चेयरमैन साहब बोल रहे हैं हर्षवर्धन चौहान जी बोल रहे हैं मैं इंतजार करता रहा सच बोल रहा हूं मैं बिल्कुल

सच बोल रहा हूं आप लोगों ने बोला मेरेको और चौधरी करनेल सिंह जी नहीं बोला वह भी मीटिग में थे अंदर । मेरी बात सुनी आप तीन एस्टीमेट बने थे उसमें आप लोगों ने कहा जरूर था लोगों की पूरा करें। अब 2 साल होने वाले हैं मैं पिछले बार यह मुददा धर्मशाला विधानसभा में भी उठाया ,उसे पिछली बार भी उठाया, मुझे लोक निरमान विभग के मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया 31 मार्च 2025 को काम कंप्लीट कर , उसका टेंडर लगा मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं काम शुरू हुआ ठेकेदार ने आधा ब्रिज बनाकर छोड़ दिया स्लैब नहीं डाला मैंने उससे पूछा क्यों नहीं डाल रहे हो उनहोंने कहा एक भी पैसा मुझे नहीं मिला अव वह काम बंद है 6 पंचायतों के लोगो को 7 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा अगर बरसात होगी तो उनका आना-जाना बंद हो जाएगा यह तो जरूरी काम है जो प्राकृतिक आपदा में त्रासदी उसका काम मैं बोल रहा हूं उसे काम का 64 लाख का एस्टीमेट है एक पैसा भी नहीं दिया ठेकेदार को वह अपना सामान वहां से फोल्ड करके ले गया उसने कहा मैंने बंद कर दिया काम। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं काम से कम उसे ठेकेदार को पैसे दे दो ताकि वह काम शुरू कर दे ताकि स्लिप डल जाए और लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाए यह छोटा सा काम मैंने बोला है और अभी बरसात के दिनों में 25 सितंबर और 26 सितंबर को बहुत बरसात हुई मेरे विधानसभा क्षेत्र में तीन जगह बदल फटे और दो व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई ,मैं आपको बताना चाहता हूं बद्रीपुर में प्रदूनी सड़क है 24 किलोमीटर की लंबाई है वह अभी का ब्रिज है छोटा सा

12.03.20205/ 1620/AT/ एम0डी /.2

गिर गया , हम उसको बार-बार बोलते रहे सारा रास्ता बंद हो जाएगा और आना-जाना भी बंद हो जाएगा विभाग ने क्या किया? अल्टरेट रास्ता बना दिया बरसात में वह भी बंद हो जाएगा। वहां पर पाइप बाहर निकालने पड़ेंगे पूरी बरसात के लिए रास्ता बंद हो जाएगा और लोगों को आने-जाने में दिक्कत होगी हजारों गाड़ियां उस रोड से प्रतिदिन पोंटा में नया काम नहीं है जो काम प्राकृतिक आपदा के कारण है वह काम तो करिये। लोबीक

रोग में बादल फटे 6 ग्राहट वैहगये एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो सड़क टूट गई उसको देखने आज तक कोई नहीं गया किसी व्यक्ति ने उसकी चिंता तक नहीं की डंडा काला आम है रेतूया में उसमें एक व्यक्ति की डेथ होगी उसके लिए कोई ज्यादा प्रोविजन नहीं किया गया इसलिए एक महत्वपूर्ण ब्रिज है हमारे क्षेत्र का जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है नवघाट से सिंह प्रभवानी का ब्रिज है सी0आर0एफ0 में बन रहा है डेढ़ साल से ब्रिज बनकर तैयार है डेढ़ साल हो गए उत्तराखंड सरकार ने ब्रिज बना दिया हमारी तरफ से जमीन एक्वायर नहीं हुई । मैंने तीन चार बार इस बात को विधानसभा में रखा आदरणीय मंत्री जी ने कहा हम जमीन को एक्वायर कर लेंगे और जल्दी इसको बनाकर देंगे क्या मैसेज जा रहा है वहां , मंत्री ,विधायक हमको टेलीफोन करते हैं वहां का प्रशासन हमसे बात करता है पिछले दिनों उत्तराखंड का प्रशासन कहता है कि आप जमीन क्लियर नहीं करते हम क्या जवाब दें । डेढ़ साल से वह ब्रिज चालू नहीं हो उसका किसकी कमी है ।

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1625/md/hk/1

श्री सुखराम चौधरी-----जारी

मैंने तीन-चार बार इस विधान सभा में इस बात को रखा आदरणीय मंत्री जी ने कहा जमीन की इनक्वाइरी कर लेंगें और जल्दी इसको बनाकर देगें। क्या मैसेज आ रहा उतराखंड में वहां के मंत्री, विधायक और प्रशासन हमें टेलीफोन करते हैं। पिछले दिन हुए उतराखंड के प्रशासन का आप जमीन के लिए नहीं करते हम क्या जबाब दें डेढ साल से वह ब्रिज चालू नहीं हो सका किसकी कमी है आप मात्र 501 कि0मी0 की जमीन एक्वायर नहीं कर सके डेढ साल में फिर कहते हो आप बहुत बडा-बडा काम कर रहे हो। 44 करोड़ से यह ब्रिज बना है। हम तो उतर प्रदेश सरकार का धन्यावाद करते हैं। उन्होंने ब्रिज तो हमें दिया ज्यादा लाभ हमारे लोगों को होना है पांवटा और शिलाई के विधान सभा क्षेत्र को परंतु

आपकी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आप काम नहीं करना चाहते कोई भी डेढ साल से फाइलें घूम रही हैं सैक्ट्री रेवन्यू और सैक्ट्री PWD से मैंने कई बार बात की कि इस काम को करिये ताकि लोगों का इसका फायदा हो सके परंतु इनकी मनसा ठीक नहीं है काम करने की इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी एक MDR (Major District Road) बगानी से खोदरी माजरी तक की एक हजार गाडियां हर दिन उस सड़क से गुजरती है। आज उस सड़क का यही पता नहीं चलता कि सड़क खड़ों में है या खड़ों में सड़क है इतनी बुरी हालत है मैंने कई बार कहा और लिखकर भी दिया कोई ध्यान नहीं देता और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से पूछते हैं वो पैसे का रोना रोते हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है हम आपकी सड़क नें पैच भी नहीं लगा सकते अब इतनी बुरी हालत है उस सड़क की वह सड़क सरकार को दुनियाभर का राजस्व देती है। यहां पर माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं और मैं इनसे भी एक आग्रह करना चाहता हूं। पिछली बरसात में बाता नदी की जो चेनलाइजेशन और डैमैज हुई कुंडियां गांव से वहां पर कम-से-कम तीन बीघे जमीन का पता नहीं चला कि कहां चली गई। आज दो साल होने को है हमने बार-बार विभाग को कहा कि इसको पैच को लगा दो ताकि लोगों की अगली फसल खराब ना हो जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को आदेश दीजिए ताकि उसको कवर करके

12.03.2025/1625/md/hk/2

उस पैच वर्क, डंगे लगा दें और रिपेयर कर दें। नहीं तो उससे ज्यादा नुकसान होता है पानी दूसरी तरफ को फैलता है। कम से कम एक कि0मी बाहर से जाकर फिर वह नदी में मिलता है उससे नुकसान होता है और मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी आपसे धर्मशाला में भी आग्रह किया था। ENC साहब को बोला था कि कुछ पैसा रिलीज करो पांवटा के लिए हमारे यहां 7 इंच के बोर लगे हैं हिमकेट के 160 बोर हैं उन बोरों से हम 25-30 बीघे जमीन की सिंचाई करते हैं दो-तीन किसानों की उसमें हम टयूब-वैल तैयार करके किसान को दे देते हैं उसके बाद हम उसको किसान को दे देता है और उसकी रिपेयर भी करता है और

उसको चलाने का बिल भी देता है। अपनी जमीन की सिंचाई भी करता है और सरकारी सेक्टर में हम जो टयूब-वैल लगाते हैं उससे 100 और 150 वीघे जमीन की सिंचाई होती है और उसमें 50 लाख से 60 लाख का खर्चा होता है। हमारी टयूब-वैल पर जो 25 वीघे जमीन की सिंचाई करता है उस पर 5 लाख का खर्चा होता है। सरकार की कोई देनदारी नहीं है। उसके बाद बिल और रिपेयर भी लोगों ने करवानी है। जब टयूब-वैल को चलाएंगे तो अच्छी फसल भी पैदा कर सकते हैं। सरकारी टयूब-वैल से नम्बर वाइस पानी की बारी आती है। जिस दिन शट्डा उन होता है उस किसान को पानी नहीं मिलता है। फिर उसका नम्बर अगली टर्म में आता है और तब तक चाहे उसकी फसल सूख जाए। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि उनमें कम-से-कम मोटर्ज डालने के लिए पैसे दो। अगर सरकार पैसे देने में असमर्थ है तो कम-से-कम किसानों को यह तो बोल दो कि वे अपनी ही मोटर्ज डाल लें ताकि वे ट्यूब वैल शुरू हो जाए। इस बारे में सरकार ने दो वर्ष की समयावधि में कोई निर्णय नहीं लिया। किसानों के ट्यूब वैल वैसे-के-वैस खड़े हैं। उसमें अभी तक कोई भी ट्यूब वैल चालू नहीं हो सके। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर सरकार पैसे दे सकती है तो दे वरना विभाग द्वारा किसान को यह आदेश दे दिया जाए कि बिजली का कनैक्शन लेकर अपनी मोटर्ज लगा लें और अपना ट्यूब वैल शुरू कर लें। मैं आपसे इतनी-सी बात कहना चाहता हूं। अभी 40 ट्यूब वैल के लिए आपने केवल 5 लाख रुपये की ही राशि तो देनी है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनके बारे में मैं यहां पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं।

12.03.2025/1625/md/hk/3

जल जीवन मिशन में डी0डब्ल्यू0एस0 निहालगढ़ की एक स्कीम चली है। वहां डेढ़ वर्ष से बोर भी हो गया, ओवर हैड टैंक भी बन गया तथा ट्रांसफॉर्मर लगने के बाद मोवहां टर भी डाल दी गई है। वहां केवल राईजिंग मैन बिछनी है। उसके लिए डेढ़ वर्ष का समय हो गया है। निहालगढ़ पूर्व विधायक सरदार रत्न सिंह जी का गांव है। वहां एक किलोमीटर की राईजिंग मैन बिछनी है और उसके लिए दो इंच की पाइप चाहिए। परंतु वह स्कीम डेढ़ वर्ष

से बंद पड़ी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कुछ इंतजाम करके उसको चलाइए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

12.03.2025/1630/केएस/एचके/1

श्री सुख राम जारी---

सभापति महोदय, हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में यहां पर बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की गईं। मैंने कई बार आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि सिविल हॉस्पिटल पांवटा केवल पांवटा विधान सभा क्षेत्र का ही हॉस्पिटल नहीं है। उसमें शिलाई का पूरा विधान सभा क्षेत्र, नाहन विधान सभा क्षेत्र की 12 पंचायतें, श्री रेणुकाजी विधान सभा क्षेत्र की 7 पंचायतें आती हैं और सीमा क्षेत्र उत्तराखंड तथा हरियाणा के मरीज भी वहां पर आते हैं। पांवटा के सिविल हॉस्पिटल में प्रतिदिन 800 ओ0पी0डी0 हैं । मैं तो 84 नम्बर पैरा पढ़कर बहुत ही हैरान हुआ, उसको आपने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा दिया है। 37 में से वहां पर 10 ही स्टाफ नर्सें हैं। आपने कहा कि हमने वहां पर एम0आर0आई0 की मशीन भी लगा दी। माननीय उद्योग मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, क्या शिलाई में एम0आर0आई0 की मशीन लग गई? उपाध्यक्ष महोदय, क्या संगडाह में लग गई? राजगढ़ या पांवटा में लग गई? लिखना क्यों है जब दे नहीं सकते। अभिभाषण में वही लिखो जो सत्य है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आपने जो महामहिम राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पढ़वाया उसमें आपने झूठ बुलवाया, इसमें कोई गलत बात नहीं है और आपने किया ही कुछ नहीं है। कहां लगी एम0आर0आई0? अगर पांवटा में यह मशीन लग जाती तो मैं आपको लड्डू ले कर आता। वहां पर दो साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक्सरे नहीं हो रहे हैं, स्टाफ नहीं है। 150 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 74 भरे हैं और 76 खाली हैं। वह जिला सिरमौर के कम से कम ढाई विधान सभा क्षेत्रों को फीड करता है। आपके स्वास्थ्य विभाग की यह हालत है । बाकी संस्थानों की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। पी0एच0सी0, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की

क्या बात करें जब एक स्वास्थ्य केंद्र को आप अच्छी तरह से नहीं चला सकते? न वहां पर प्रॉपर सिटी स्कैन चलता है, न रेडियोलॉजिस्ट है, न एम0आर0आई0 की मशीन लगी है, न डॉक्टर है। स्टाफ नर्सों की कमी है। 10 स्टाफ नर्सें क्या चलाएंगी जबकि वहां पर 7 डिपार्टमैंट्स हैं। एक डिपार्टमैंट को चलाने के लिए एक-एक स्टाफ नर्स चाहिए और डे-नाइट चलाने के लिए 14 चाहिए तो कैसे चलेगा आपका हैल्थ का सिस्टम? मैं कहना चाहता हूं कि हैल्थ डिपार्टमैंट की सेहत को सुधारो ताकि हिमाचल प्रदेश की हैल्थ सुधर जाए। यह इतना महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है, हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, माइनिंग एरिया है। वहां पर एक्सिडैंट्स होते रहते हैं। हर महीने कोई न कोई गाड़ी गिर जाती है। पांवटा

12.03.2025/1630/केएस/एचके/2

साहिब रैफरल हॉस्पिटल बन गया और उस हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। कई मरीजों को तो हमें एम्बुलेंस में ही रैफर करवाना पड़ता है ताकि डिले न हो जाए। वह समय पर नाहन या चण्डीगढ़ के हॉस्पिटल में पहुंच जाए। यह हालत है आपके हॉस्पिटल की और आप बड़ी-बड़ी बातें करते हो। बड़ी-बड़ी बातें करने से अच्छा है धरातल पर छोटी बातें कर लो। सिस्टम में सुधार करिए।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा बिजली बोर्ड के बारे में बोलना चाहता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में एच0टी0 और एल0टी0 की लाइनों के लिए कंडक्टर नहीं है। अगर किसी ने कोई एल0टी0 का छोटा सा कनैक्शन लेना है तो उसमें कंडक्टर नहीं है। थ्री फेज़ के कनैक्शन के लिए कंडक्टर नहीं है। कभी आपके पोल आ जाते हैं, कभी मीटर आ जाते हैं, कंडक्टर है ही नहीं। दो साल से काम बिल्कुल बंद पड़ा है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। 3701 करोड़ रुपये की आर0डी0एस0एस0 की स्कीम थी जो कि हमारी सरकार के समय में स्वीकृत हुई। आपने तो टैंडर लगाने में भी दो साल लगा दिए। आपको उसमें टैंडर अवार्ड करने में भी दो साल लग गए। प्रॉपर तरीके से खर्च नहीं कर सके वह पैसा भी आप। हमने तो अक्तूबर, 2022 में टेंडर भी लगा दिए थे, आपने कैंसल कर दिए 6 महीने के दायरे को ले कर कि 6 महीने से पहले लगे हुए सारे टेंडर हमने रद्द करने हैं। आपकी सरकार कितनी सक्रिय है, आप दो साल में वह टेंडर नहीं लगा सके, काम उसके कारण डिले हुआ । आज अभी टैंडर लगे हैं इसलिए यह सामान दीजिए। आपने तो लोगों को कह दिया

कि बिजली के मीटर भी अपने लाओ, सिंगल फेज़ के भी अपने लाओ, थ्री फेज़ के भी अपने लाओ। कल को तो आप यह कहेंगे कि पोल भी अपने आप परचेज़ करके लाओ और सर्विस वायर भी अपनी लाओ इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करिए ताकि लोगों को मैडिकल की सुविधाएं मिल सके।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

12.03.2025/1635/AV/वाईके/1

श्री सुख राम चौधरी------ जारी

मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखण्ड और हरियाणा से महंगी बिजली है। इसके अतिरिक्त आपने सैस भी बहुत ज्यादा लगा दिए। आपने मिल्क सैस और पर्यावरण सैस लगा दिया। इसके अतिरिक्त आपने उद्योग क्षेत्र में खनिज सैस भी लगा दिया है। आपने बैक डोर से सारे सैस लगाए हैं और बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है जिसके कारण प्रदेश की आम जनता परेशान है। आपने दस पैसे मिल्क सैस, दस पैसे पर्यावरण सैस और दस पैसे खनिज सैस लगाया है। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपकी इस नीति के कारण आज हिमाचल प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहे हैं। आज जिसने शैड बनाया था या फैक्ट्री लगी थी उसके लिए भी धारा 118 की परमिशन चाहिए। आज जो धारा 118 के अंतर्गत इंडस्ट्री लगी है और वह उस इंडस्ट्री को बेचता है तो उसको भी धारा 118 की परमिशन के प्रोसैस से गुजरना पड़ता है। आप इसका सरलीकरण कीजिए ताकि यहां से इंडस्ट्रीज न जाएं। अगर आप इस प्रकार के सख्त नियम बनाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री से मिलता क्या है। मैं यहां पर पांवटा का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर कम-से-कम 20,000 से 22,000 लोग काम करते हैं। पांवटा में तीन से चार हजार लोग शिलाई, सात से दस हजार लोग पांवटा और दो से तीन हजार लोग हिमाचल प्रदेश के काम करते हैं। इसके अतिरिक्त सात से आठ हजार हिमाचल प्रदेश से बाहर के लोग काम करते हैं, तो क्या इंडस्ट्री ने लोगों को रोज़गार नहीं दिया है? आप वहां खुद देख

सकते हैं कि इंडस्ट्री ने वहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। हमारी गलत नीतियों के कारण आज वहां से इंजस्ट्रीज पलायन कर रही हैं। वहां पर धारा 118 की क्या जरूरत पड़ गई जब आपने वह परमिशन एक इंडस्ट्री को पहले दे रखी है? वहां जब इंडस्ट्री शैड में लगी है तो उसके लिए धारा 118 की क्या जरूरत पड़ गई? आपने इतने सख्त नियम बना दिए और आपकी गलत नीतियों की वजह से हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्रीज अब पलायन कर रही हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग इस संदर्भ में ध्यान दीजिए।

12.03.2025/1635/AV/वाईके/2

आप स्पोर्ट्स के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। यहां पर अभी मंत्री जी नहीं बैठे हैं। माननीय सदस्य श्री अजय सोंलकी के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला माज़रा में 5 करोड़ रुपये की लागत से एस्ट्रो ट्रफ लगा है। वहां उसको लगे हुए डेढ़ वर्ष का समय हो गया परंतु वहां पर एक ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा। वहां उसमें पानी देने में दिक्कत होती है और एस्ट्रो ट्रफ उखड़नी शुरू हो गई है। उसके बारे में इतनी बार कहा गया लेकिन आप लोग एक ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा सके। फिर आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। आपको केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको एस्ट्रो ट्रफ लगाकर दी। परंतु आप डेढ़ वर्ष की समयावधि के अंदर वहां पर एक ट्रांसफॉर्मर तक नहीं लग सके। वहां पर मोटरें नहीं चल रहीं, वहां जो कनैक्शन दिया गया है। यहां पर माननीय उप-मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कम-से-कम एक ट्रांसफॉर्मर तो लगा दीजिए ताकि प्रदेश की छवि खराब न हो। वहां पर नावघाट से सिंहपुरा-भगाणी का पुल बनना है, उससे प्रदेश सरकार की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। वह पुल 44 करोड़ रुपये की लागत से बनना है। डेढ़ वर्ष का समय बीत गया लेकिन अभी तक हम उसके लिए जमीन एक्वायर नहीं कर पाए। मैं यहां आपकी वर्किंग की बात बता रहा हूं क्योंकि कहीं पर फ्लड आता है तो वहां कोई देखने नहीं जाता। वहां पर लोग इंतजार करते रह जाते हैं कि कोई मंत्री या सरकार का नुमाइंदा आएगा और हमारे लिए काम करेगा जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं।

अब मैं अंतिम बात कह कर अपनी चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं। मेरा उद्योग मंत्री जी से आग्रह है। आपने भी कई बार कहा कि जिला सिरमौर में कोई-न-कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए क्योंकि आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। परंतु आज हालत क्या है? गोंदपुरा का 132 के0वी0 का सब-स्टेशन ओवरलोडिड है। हमने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान वहां 16 एम0वी0ए0 का ट्रांसफॉर्मर लगाया था परंतु आज हम एक भी इंडस्ट्री को लोड नहीं दे सकते। वहां न 33 के0वी0 पर लोड उपलब्ध है और न 11के0वी0 व 132 के0 वी0 पर है। गोंदपुरा में 117 करोड़ रुपये का एक एच0पी0टी0सी0एल0 का सब-स्टेशन सैंक्शन हुआ है। अगर वह लग जाएगा तो साथ में एक 132 के0वी0 का सब-स्टेशन भी तो चाहिए क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि

12.03.2025/1635/AV/वाईके/3

132 के0वी0 का एक नया सब-स्टेशन सी0सी0आई0 राजवन में बन जाए क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री की जमीन है। उस पर शिलाई, कपोटा, सतोन, सी0सी0आई0 राजवन, डी0आर0डी0ए0, पुरुवाला, नघेता इत्यादि कुल 9 सब-स्टेशन बनते हैं। पांवटा में 33 के0वी0 के 22 सब-स्टेशन हैं और गोंदपुरा से जो 132 के0वी0 का सब-स्टेशन चलता है तो उसका लोड कम हो जाएगा। वहां पर एक नया सब-स्टेशन बन जाएगा

टी सी द्वारा जारी

12.03.2028/1640/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री सुख राम चौधरी ... जारी

जिससे हमें बहुत राहत मिलेगी। गोंदपुर इसके लिए जमीन उपलब्ध है। उसके लिए निविदाएं मांगी गई है जब वह लग जाएगा तो इससे कम-से-कम अढ़ाई विधान सभा क्षेत्रों को फायदा होगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इसमें हस्तक्षेप करें ताकि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति मिल सके

और भविष्य में नए उद्योग स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। साथ ही, इससे वोल्टेज स्थिरता में भी सुधार होगा।

मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सदन में भवानी सिंह पठानिया जी बोल रहे थे, तो मैं उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को 2200 करोड़ रुपये देना व्यर्थ है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो 2200 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड को दे रही है, वह वास्तव में जनता के कल्याण के लिए दी जा रही सब्सिडी का हिस्सा है। यह राशि बिजली बोर्ड को नहीं दी जा रही, बल्कि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए उपयोग हो रही है।

पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने उद्योगों के लिए बिजली के रेट में राहत दी थी, जिससे कुल भार बढ़ गया। अब वह 2200 करोड़ रुपये की राशि बिजली बोर्ड को दी जा रही है, लेकिन यह कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। इसलिए इस माननीय सदन में सभी को अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।

राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसमें कई कमियां हैं। जो घोषणाएं की गई थी वे सारी घोषणाएं अधूरी हैं। इन्होंने जो छह घोषणाएं की थी वे सभी अधूरी हैं और संस्थानों की हालत खराब है, सड़कों की स्थिति दयनीय है, बिजली आपूर्ति अस्थिर है तथा सिंचाई योजनाओं का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। उद्योगों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। इन सब कारणों से मैं इस प्रस्ताव और अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

12.03.2028/1640/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी भाग लेंगे।

श्री संजय अवस्थी : सभापति महोदय धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया द्वारा प्रस्तुत किया गया और श्री विनोद सुल्तानपुरी जी द्वारा अनुसमर्थित किया गया, उस पर चर्चा चल रही है। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राज्य सरकार की उपलब्धियों को लगभग 49 पन्नों पर महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा अपने अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया नेता विपक्ष और उनके साथियों ने दी, मैं उनको गम्भीरता से सुन रहा था। उन्होंने राज्यपाल महोदय के पद की गरिमा और मर्यादा की सीमाओं को भी लांघा दिया। इस तरह से हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा एक गलत परंपरा की शुरुआत ने की गई है। इस तरह की बातें तभी होती है जब कोई मानसिक दबाव में होता है। आज हमारे विपक्ष के साथियों पर भी कोई-न-कोई दबाव अवश्य है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस समय क्या बोलना है और किसके बारे में क्या टिप्पणी करनी है? मैं इसकी निन्दा करता हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण में प्रदेश सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 10 गारंटी योजनाओं में से 6 पूरी हो चुकी हैं या उन्हें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

12-03-2025/1645/ns-ag/1

श्री संजय अवस्थी------ जारी

मुझ से पूर्व वक्ताओं ने भी यह स्पष्ट तौर पर कहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव पूर्व गारंटियों को लेकर अपना दस्तावेज जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है और जनादेश मिलने उपरांत सरकार बनने के बाद उसको पांच वर्षों तक पूरा कर सकती है। विपक्ष ने तो पहले ही दिन से इस तरह का वातावरण बनाना शुरू कर दिया था। आपने प्रदेश की जनता के

समक्ष इस तरह की झूठी व भ्रमित बयान बाजी करके आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। इससे कहीं-न-कहीं ऐसा लगता है कि आप एक सुनियोजित षड्यंत्र इस स्थापित सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और आर्थिक व्हर्लपूल के अंदर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं तथा देश व प्रदेश की जनता को ऐसी पिक्चर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश आज आर्थिक रूप से डूबा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों का सबसे बड़ा कारण आप लोग (विपक्ष) हैं। पांच वर्षों तक आपकी सरकार रही और आपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्या प्रयास किए? आप व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकारना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन प्रदेश में सरकार बनी और माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने मुख्य मंत्री की शपथ ली, उसी दिन से उन्होंने अपना नज़रिया देश व प्रदेश का दिखा दिया था। उन्होंने मानवता का संदेश दिया और वे शपथ के बाद सचिवालय न जा करके सबसे पहले बाल आश्रम गए। आपको उससे ही आभास हो जाना चाहिए था कि किस तरह के मुख्य मंत्री आज प्रदेश को मिले हैं। आज पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसकी तरफ प्रदेश सरकार व मुख्य मंत्री जी की नज़र है। यदि आप विपक्ष वाला चश्मा उतार कर देखते तो आपको यह सब कुछ दिखाई देता। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए और यदि आप उस भावना से देखते कि प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री के नेतृत्व में जो योजनाएं लाई हैं, जन-हित की योजनाएं लाई हैं, रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस करके जो योजनाएं लाई हैं व ला रहे हैं तब आपको सच्चाई पता लगती। आप उस सच्चाई का बयान सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को देते और उसमें सत्तासीन सरकार का सहयोग करते तो मैं समझता कि आप हिमाचल प्रदेश के सच्चे हितैषी हैं। आपने अपना चेहरा उसी दिन दिखा दिया था जब प्रदेश में आपदा आई और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के उद्देश्य से एक विशेष सत्र बुलाया गया। आपने उस दिन प्रदेश की जनता को धोखा दिया और

12-03-2025/1645/ns-ag/2

यह आपका सच्चा चेहरा है। आज आप किस मुंह से आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। आज आप बजट की मांग करते हैं। आप पी0डी0एन0ए0 की लगभग 9600 करोड़ रुपये की राशि को लेकर आएं जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को देनी है। आप उसकी बात कीजिए।

केंद्र सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर कटौती लगाई है, आप उसकी मांग कीजिए। आप यहां पर बताएं कि आपने इन पैसों को लाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं? आपने सिर्फ विरोधाभास की स्थिति ही पैदा करनी है। आपको लगता है कि विपक्ष द्वारा सिर्फ विरोध होना चाहिए और करना चाहिए, आपने इसी भावना से आज यहां पर बातें की हैं।

सभापति महोदय, अगर हम प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो हमारी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए इस क्षेत्र की मजबूती के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। जिनमें से 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा चुके हैं। कैंसर मरीजों को इलाज सहित 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त में दी जा रही हैं। एक तरफ पूर्व भाजपा सरकार थी जिसमें दवाइयों का घोटाला हुआ था।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

12.03.2025/1650/RKS/Aजी-1

श्री संजय अवस्थी.... जारी

आपकी सरकार के समय सैनिटाइजर घोटाला हुआ। हमारी सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में एक भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह व्यवस्था परिवर्तन है। आई0जी0एम0सी0, शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ के हजारों पद भरे जा रहे हैं। अस्पतालों में आधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद भी की जा रही है। आई0जी0एम0सी0, शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। श्री रणधीर शर्मा जी एम्स की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पैट स्कैन मशीन के उद्घाटन के लिए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कोठीपुरा आए थे। लेकिन यह माननीय मुख्य मंत्री जी का दृष्टिकोण था कि हमने इससे

पहले ही प्रदेशवासियों के लिए पैट स्कैन की उपलब्धता कर दी है। मेडिकल कॉलेज, नेरचौक में भी MRI मशीन स्थापित की जा रही है। ...(व्यवधान) अगर आप विपक्ष का काला चश्मा उतारकर देखेंगे तो यह प्रक्रिया अंतिम चरण पर है और प्रदेशवासियों को इसकी सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया कि 10 में से 6 गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इन योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है और पांच साल में हम 10 की 10 गारंटियों को धरातल पर लेकर आएंगे। यह हमारी प्रदेश की जनता से की गई प्रतिबद्धता है। नेता प्रतिपक्ष इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। जब कर्मचारी वर्ग अपनी लंबित मांगों के लिए आंदोलन कर रहा था तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं। आपने अपने समय में उन्हें वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया। आपके कर्मचारी विरोधी रवैये के कारण ही आप विपक्ष में बैठे हैं। आपके द्वारा दिए गए घावों पर हमने मरहम लगाया और सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ओ.पी.एस. लागू की। यह हमारी प्रतिबद्धता थी। इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि यदि आपको राजनीति में आना है और नारे लगाने हैं तो आप सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ें। आज प्रदेश की जनता ने न केवल आम चुनाव में बल्कि जो उप-चुनाव हुए हैं उसमें भी आपको आइना दिखा दिया है। यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। आप मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। हम वर्ष 2027 में पुनः सत्ता में आएंगे और वर्ष 2032 में जो हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और

12.03.2025/1650/RKS/Aजी-2

आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का संकल्प लिया है उसे हम पूरा करेंगे। आप वहीं बैठे रहेंगे और हम यहीं से आपसे बात करते रहेंगे। आप इस बात का इंतजार कीजिए। मैं उन 6 गारंटियों को दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे बाद अभी और भी वक्ता अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जो 68 विधान सभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं वह अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि डॉ0 वाई0 एस0 परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को देश-विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

12.03.2025/1655/बी.एस./ए.एस./-1

श्री संजय अवस्थी जारी...

यह उन बच्चों के लिए है जो धन की कमी की वजह से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। उनके भविष्य को सुधारने के लिए उनके उज्ज्वल भविष्य को बनाने के दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में फैसला लिया है। एक आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में युवाओं के भविष्य को दाव पर लगाया था। आपके समय में पेपर बेचे गए और हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। यह व्यवस्था परिवर्तन आज हमने किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। आपके समय में पेपर बेचे गए तभी सिलेक्शन बोर्ड को भंग करना पड़ा और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य मंत्री जी का यह ऐतिहासिक फैसला था। आपको इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश की जनता सब जानती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इंतजार करें और ये मुंगेरी लाल के सपनों को लेना छोड़ दें। प्रदेश के विकास में जो हमारी योजनाएं हैं, प्रदेश के विकास में जो प्रदेश सरकार के फैसले हैं, उसमें आप अपनी साकारात्मक भूमिका निभाएं, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

आज रेवेन्यू जनरेशन पर प्रदेश सरकार का फोकस है और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था को हमे अपलिफ्ट करना है। यही एक संकल्प हमारा है उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके तहत हमारी प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उठाने का प्रयास है और इसी के तहत गाय और भैंस के दूध के मूल्य को बढ़ाया गया। यह तो शुरूआत है, आगे-आगे देखिए होता है क्या? आप इंतजार करिए और आप इस बात की प्रशंसा करना सीखिए।

आपकी सरकार के समय में जो कीट नाशक दवाइंया थीं और जो खाद पर मिलने वाली सब्सिडी थी उसे बंद कर दिया गया था। परंतु प्रदेश सरकार ने उसे पुनः बहाल किया है, यही हमारा व्यवस्था परिवर्तन है। आज मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय जी

ने अपने अभिभाषण में नशे को रोकने की भी बात कही है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि यह जो नशे की तस्करी की बात है, आज युवाओं में जिस तरह से नशे का एक प्रचलन बढ़ रहा है और हमारे युवा जो नशे की ओर अकर्षित हो रहे हैं इसे रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। यह समाज में एक ऐसी कुरीती है कि इसके खिलाफ

12.03.2025/1655/बी.एस./ए.एस./-2

हम सब को इकट्ठे होना है। इस पर हमें राजनीति नहीं करनी है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो नशा समाज में हमारे युवाओं को जकड़ रहा है, यह आज ही पैदा नहीं हुआ है। पूर्व में जो सरकारें थीं, उस समय भी ऐसे केसिज आते रहे हैं लेकिन आपकी सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई गंभीर उपाय नहीं किए और कोई कदम नहीं उठाए। यदि बतौर मुख्य मंत्री हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस संदर्भ में आवश्यक एवं कड़े कदम उठाए होते तो आज हिमाचल प्रदेश नशे के दलदल में नहीं फंसा होता। आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने पी0आई0टी0, एन0डी0पी0एस0 एक्ट को प्रदेश में सख्ती से लागू नहीं किया। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पी0आई0टी0, एन0डी0पी0एस0 एक्ट में नशे के सेवन एवं तस्करी की रोकधाम के लिए कड़े प्रावधान हैं जिन्हें हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सख्ती से लागू किया गया है। इसके सुपरिणाम हमारे सामने होंगे। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। राज्य सरकार ने मादक पदार्थ के मुद्दे को एक संतुलित और व्यापक रणनीति के साथ संबोधित करने का संकल्प लिया है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट बैठ जाइए।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

12.03.2025/1700/DT/AS-1

सभापति : माननीय राज्य पाल के अभिभाषण पर अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष से 12 सदस्य ने बोलना है। अगर माननीय सदन की सहमति हो तो इस सदन की बैठक 2 घंटे के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(सदन की बैठक 2 घंटे के लिए बढ़ाई गई)

श्री संजय अवस्थी : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का हमारा सामुहिक प्रयास होना चाहिए। जो व्यक्ति नशे की लत का शिकार होते हैं वह स्वभाव से अपराधी नहीं होते बल्कि एक गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं, इसलिए हमारा जो दृष्टिकोण है वह दण्डात्मक उपायों से आगे बढ़कर एक मजबूत पुनर्वास ढांचा होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार नशे के शिकार लोगों को अपराधी के रूप में नहीं बल्कि चिकित्सा व मनोवैज्ञनिक सहायता वाले लोगों को रूप में पहचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए पुर्नवास केंद्रों की स्थापना, मौजूदा बुनियादे ढांचे में वृद्धि और चिकित्सा के आधुनिक तौर-तरीकों की शुरुआत पीड़ित लोगों को समाज की मुख्य धारा में फिर शामिल होने का मौका देने में महत्वपूर्ण होगी। मैं यह कहना चाहूंगा। श्री रणधीर शर्मा जी इस समय सदन में नहीं हैं। उन्होंने यहां पर कुछ बातें कही और उन बातों से भ्रमित करने का प्रयास किया। रणधीर शर्मा जी ने 500 करोड़ रुपये की राशि की बात कही और माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने भी इस बारे में बयान दिया था तो मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा कि यह एक आधाहीन और भ्रमित करने वाला बयान है। ऐसे बयान के द्वारा सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। वास्तविकता यह है कि वह 500 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार की राशि नहीं थी। यह राशि चार-पांच बैंकों में पड़ी थी और यह प्रदेश सरकार की राशि थी। यह राशि भूमि अधिग्रहण के लिए दी गई थी। यह एक अनस्पेंट राशि थी। उन्होंने इस राशि की बात तो कही पर इनको यह भी पता होना चाहिए कि यह राशि कब से वहां पड़ी हुई थी। यह राशि इन्हीं के समय से वहां पड़ी हुई थी। लेकिन ये सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि उनको अपने संसाधनों का ही पता नहीं था कि कौन सा संसाधन कहां पड़ा है। क्योंकि ये लोन पर ऐश कर रहे थे। ये लोन ले रहे थे और इनको लोन मिल रहा था क्योंकि इनके समय लोन लिमिट में कटौती नहीं हुई। कटौती का सामना वर्तमान

सरकार को करना पड़ा। जब साधनों का अभाव होता है तब व्यक्ति इधर-उधर देखता है कि मेरे पास और क्या है जो एसेट्स के रूप में पड़ा है। जब मुख्य मंत्री जी के ध्यान में

यह बात आई कि इस पैसे का लाभ केवल बैंक ले रहे हैं, इस पैसे का लाभ मात्र कुछ व्यक्ति ले रहे हैं, उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हों और उसमें हमारी कुछ साथी भी शामिल हों जो इसका लाभ ले रहे थे। ...(व्यवधान) मैं यह बताना चाहूंगा ...(व्यवधान) आप सुनिए ...(व्यवधान) Let me complete ...(व्यवधान) आप यह पता करें, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन उसमें से म्यूचल फंड कंपनी में पैसा लगा हुआ था और कुछ लोगों को पर्सनल बेनेफिट दिए जा रहे थे वे कौन लोग हैं? ...(व्यवधान) विनोद जी मैं अकेले आप को बता दूंगा, आप चिंता मत करो। ...(व्यवधान) इसकी जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान) वह आप के लोग थे, वह पैसा आपके समय से पड़ा था ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि श्री त्रिलोक जम्वाल जी को पिंच हुआ है। श्री त्रिलोक जी आप बैठ जाइए। मैं बताता हूं। ...(व्यवधान) आप ऊंचा बोल कर दूसरे की आवाज नहीं दबा सकते। आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते , उसमें पर्दा नहीं डाल सकते। आपको सुनना होगा। हमने आपको सुना, आपकी झूठी बातें सुनी। हमने आपके द्वारा लगाये गये झूठे आरोप सुने। लेकिन आज आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी। सच्चाई कड़वी होती है। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी जब आपकी बारी आएगी तो आप इस क्लेरीफाइ कर देना। Let him complete.

श्री संजय अवस्थी : सभापति महोदय यदि हमारे विपक्ष के साथी इतने उत्सुक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसकी जांच

श्री एन.जी. द्वारा जारी

12.03.2025/1705/डी.सी.-एन.जी./1

श्री संजय अवस्थी.....जारी

करवाई जाए और दूध-का-दूध तथा पानी-का-पानी किया जाए। इसके अलावा इनके समय में कितने कॉप्रेटिव बैंक, किस-किस कम्पनी और किन-किन म्यूच्अल फण्ड्स में पैसा लगा था तथा किसके कहने पर लगा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान) आप इंतजार कीजिए।...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल जी, इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।...(व्यवधान) कम्पलीट करने के बाद बोल लीजिएगा।...(व्यवधान)

श्री बिक्रम सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य यहां पर कह रहे हैं कि कुछ लोग उसमें सम्मिलित थे तो मेरा आग्रह है कि उनके नाम भी बताएं और अपनी सरकार से जांच करवाएं।...(व्यवधान)

श्री संजय अवस्थी : माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जी, मैंने जांच की मांग कर ली है।...(व्यवधान) मैंने इस सदन में जांच की मांग की है।...(व्यवधान) आप इंतजार कीजिए।...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य जांच की मांग कर रहे हैं। (विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर देखते हुए कहा) ...(व्यवधान) इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, अब वाइंडअप कीजिए।...(व्यवधान)

श्री संजय अवस्थी : सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष जांच की मांग करता हूं।...(व्यवधान) सभापति महोदय, किसी को भी यह तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि आज जो परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही हैं वह वास्तविक्ता

12.03.2025/1705/डी.सी.-एन.जी./2

नहीं है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं कि सच्ची तसवीर सबके सामने आनी चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति : एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य को अपनी बात कम्पलीट करने दीजिए उसके बाद आप बोल लीजिएगा। (विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर देखते हुए कहा) ...(व्यवधान)

श्री संजय अवस्थी : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार के समय में प्रदेश के असेस्ट्स को कोड़ियों के भाव बेचा गया था। पूर्व सरकार के समय में अपने चहेतों को एक रुपये की लीज़ मनी पर करोड़ों रुपये की जमीनें दी गई थी। यह सब ऑन रिकॉर्ड है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान) आप (विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर देखते हुए कहा) दूध के धुले हुए नहीं है। आपकी सरकार के समय में भी कईं घोटाले हुए हैं। आपकी सरकार पर भी कईं आरोप लगे थे। आपकी सरकार में भी आपका विरोध हुआ था।...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Member, please, windup. ...(interruption)

श्री संजय अवस्थी : माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी, आप मेरी बात को सुन लीजिए। यदि आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप उसका खंडन कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों से केवल इतना आग्रह है कि पी0डी0एन0ए0 की ग्रांट जोकि लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपये है, को केन्द्र सरकार से लाने का काम करें। इसके अलावा राजस्व घाटा अनुदान पर जो कटौती लगी है उसे हटवाने का काम करें। मैं विपक्ष के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप ओ0पी0एस0 पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। आप लोग ओ0पी0एस0 के पक्ष में हैं या नहीं?

12.03.2025/1705/डी.सी.-एन.जी./3

जब भी विपक्ष के माननीय सदस्य या माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं और माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी, आप यदि अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप ओ0पी0एस0 पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें ताकि आप लोगों का सच्चा चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ सके।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी भाग लेंगे। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी, इन्होंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है और कोई स्पेसिफिक बात नहीं की है। इन्होंने इंक्वायरी की बात की है और ओ0पी0एस0 के लिए बोला है।...(व्यवधान) ठीक है, माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी, आप बोलिए।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, मुझे लग रहा है कि माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस ऊंची आवाज में आप सरकार की तरफदारी कर रहे हैं उससे यह लग रहा है कि माननीय सदस्य किसी जनसभा में बोल रहे हैं। माननीय सदस्य इस सदन में दूसरी बार जीत कर आए हैं। यहां पर माननीय सदस्य जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं तो मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि प्रदेश में आपकी सरकार है और यदि किसी ने घोटाला किया है, सचिवालय में किया, बैंक में किया या म्यूच्अल फण्ड्स में किया तो आप उसकी इंक्वायरी करवाएं। ...(व्यवधान) आपने मांग किससे की है? आप इस सरकार का हिस्सा हैं। माननीय सदस्य मुझे लगता है कि आपके एण्ड पर इस प्रकार से सनसनी पैदा करना ठीक नहीं है। अब यहां पर.

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

12.03.2025/1710/DC-PB/-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

वर्तमान मुख्य मंत्री जी के बारे में टिप्पणियां हो रही हैं। उस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री और विधान सभा अध्यक्ष के बारे में टिप्पणियां हो रही हैं। ये निराधार है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपके पास तथ्य हैं तो उन पेपर्ज को आप यहां पर ले करें और जो माननीय अवस्थी जी ने कहा है उन तमाम शब्दों को इस प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाए

। माननीय सदस्य इस अभिभाषण का समर्थन करे या विरोध करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है परंतु आप तथ्यों और ठीक तरीकों पर बात चीत करें। हम इनसे यह अपेक्षा करते हैं। यह कह रहे हैं कि श्री जय राम जी तो कर्मचारी विरोधी थे जिन कर्मचारियों को आप उकसाते थे...(व्यवधान) उनमें से एक विभाग के कर्मचारी नेता ने मुख्य मंत्री जी का नारा लगा रहा था कि 'सुक्खू सुनदा नहीं, साडियां गलां पूरियां करदा नीं' और (***) ...(व्यवधान) आप पूरी बात सुनिए। यह इस सदन की और निर्वाचित सदस्यों की मर्यादाओं का हनन है।...(व्यवधान। संजय अवस्थी जी की ओर बोलते हुए।) आपने शुरूआत की थी। वह कर्मचारी कौन था? आप उसको नवाज़ा करते थे। पलकों और सिर पर उठाया-बिठाया करते थे। आज वही कर्मचारी आपके विरोध में खड़े हैं। इसलिए माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी मैं उज्जवल परंपराओं को बनाते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि (***) ओ0पी0एस लागू करो और माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर के नारा लगा रहे थे। हमें भी दुःख हो रहा था। हिमाचल प्रदेश में यह जो परंपराएं आपने स्थापित की हैं। ये मुख्य मंत्री हमारे भी हैं और इस सदन के नेता है आपका बहुमत है परंतु ऐसे कोई उपहास उड़ाए यह हमें स्वीकार नहीं है। आदरणीय जय राम जी की हुकुमत थी तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हित की हमेशा रक्षा की गई है और सुरक्षा की है यह मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने कहा कि उस सरकार में भ्रष्टाचार हो गए। आप तथ्य प्रस्तुत कीजिए किसने भ्रष्टाचार किया? और कौन सा आरोपी है। उनके खिलाफ कहां पर एफ0आई0आर0 लॉज हुई और कहां पर पी0एल0आई0 हुई, कृपया आप बताइए तो सही।

सभापति : माननीय सदस्य, इस पर पिछले सत्र में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

12.03.2025/1710/DC-PB/-2

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आदरणीय संजय अवस्थी जी ने, जिसे कहते हैं कि जनसभा में भाषण देते हैं। इन सभी शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए। कृपया आप इन्हें पढ़े और देखे यदि ये शब्द

अनुकूल नहीं है उनकी कार्यवाही में क्या आवश्यकता है? आप सरकार का समर्थन करना चाहते हैं आप करें।

सभापति : माननीय सदस्य ऐसा कोई भी व्यक्तिगत आरोप नही लगाया गया है परंतु मैं इसे देख लूंगा।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय उप-मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

उप-मुख्य मंत्री : माननीय सभापति महोदय, सदन चल रहा है कई टैम्पर हाई हो जाता है जिसकी वजह से पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों में नोक-झोंक हो जाती है। लेकिन माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने कहा(***)को सदन की कार्यवाही से एक्पंज किया जाए।

सभापति : इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।...(व्यवधान)

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, जिस कर्मचारी नेता ने मुख्य मंत्री जी का उपहास उड़ाया है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति : अब राजस्व मंत्री जी प्रदेश में चल रही कानूनगो और पटवारी संघ की हड़ताल के बारे वक्तव्य देना चाहते हैं।

राजस्व मंत्री : माननिय सभापति महोदय मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जो प्रदेश में पटवारी तथा कानूनगो संघ ने एक आंदोलन किया था। आज हमारी संघ से बैठक हुई है और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है और वह कल से अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद।

सभापति : अब इस चर्चा माननीय सदस्य श्री इन्द्र लखनपाल जी भाग लेंगे।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

12.03.2025/1715/HK/AP-1

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री इंद्र दत्त लखनपाल जी इस चर्चा में भाग लेगें।

श्री इंद्र दत्त लखनपालः आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा इस सदन में लाई है उस सदंर्भ में आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पक्ष और विपक्ष से बड़े लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। जहां पक्ष के लोगों की एक मजबूरी बन जाती है कि इस दस्तावेज़ का समर्थन करना है, वहां हमारा जनता की समस्यों को इस सदन में रखना प्रथम कर्तव्य होता है। यह दस्तावेजद़ जो माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, मैंने भी इस दस्तावेज़ को पढ़ा। अगर हम इस दस्तावेज़ को माने तो यह लगता है कि हमारा प्रदेश स्विट्जरलैंड बन गया। लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं तो परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। यहां पर जितनी मर्जी तारीफ कर लें क्योंकि हमें मालूम है कि सत्ता पक्ष की मजबूरी है, उन्हें काम भी करवाने हैं। अगर वह बीच में ऐसी-वैसी बात बोल देंगे तो उनका नम्बर लग जायेगा। यहां पर हर विषय को लेकर बहुत लंबी-लंबी चर्चाएं हुई हैं, हमारे साथियों ने अपना-अपना पक्ष रखा है। मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। पिछले ढाई वर्षों से हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ या आप उसे प्रतिशोध की भावना कह लीजिए कि मैं उधर से इधर आ गया। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के काम को रोक कर रख दिया। ऑफिसर्ज़ बदल दिये। मेरे घर का कोई ऑफिसर तो था नहीं। सबसे पहले बी.एम.ओ. को उठा दिया, उसके बाद बी.डी.ओ. को उठा दिया। फिर 8 महिनों तक बी.डी.ओ. ही नहीं आया। अब एक महीने पहले बी.डी.ओ. आया। तीन महीने से जल शक्ति विभाग में अधिशाषी अभियंता नहीं है। छः महीने से बी.एम.ओ. नहीं है। यहां पर अभी पक्ष के माननीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग के बारे में बड़ी चर्चा कर रहे थे कि स्वास्थ्य संस्थाएं बहुत सुदृढ़ हो गई हैं। मेरे सिविल अस्पताल में माननीय मुख्य मंत्री ने मुछसे कहा था कि मैं आपको 9 स्पैशलिस्ट दूंगा, वहां सिविल अस्पताल में केवल मात्र 4 डॉक्टर्ज़ हैं। वहां पर जिस प्रकार का ढांचा होना चाहिए था, जो कर्मचारी होने चाहिए थे, वह नहीं है। सिविल अस्पताल की बिल्डिंग बननी थी वह नहीं बनी। हमारे आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने पी.एच.सी. भौटा को स्तरोनित किया था। पी.एच.सी. से सी.एच.सी. बनाया। वह पी.एच.सी. 24X7 चलती है। लेकिन दूर्भाग्य इस बात का है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने

उसको डी-नोटिफाई किया और उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तीन बार अधिसूचनाएं जारी हुई हैं कि इस पी.एच.सी. में पांच बजे के बाद किसी मरीज को अटेंड नहीं किया जाएगा। यह स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम है। जो भौटा की पी.एच.सी. है। वह नेशनल हाइवे के साथ है, आए दिन वहां पर दुर्घटना होती है और सबसे पहला स्टेशन भौटा पड़ता है। रात के समय में कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई महिला या बुजुर्ग बीमार हो जाए, तो उनको कहां ले जा सकते हैं। उस पी.एच.सी .को सरकार ने डी-नोटिफाई कर दिया। अभी उप-चुनाव में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक जनसभा में अपने संबोधन में कहा कि मैं इस पी.एच.सी. को 50 बिस्तरों का सी.एच.सी. बना दूंगा। अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। हमारा भौटा का बस स्टैंड और बड़सर का बस स्टैंड जिसके बारे में मैंने माननीय उप-मुख्य मंत्री जी आपसे भी चर्चा की लेकिन आज दिन तक न भौटा और न बड़सर बस अड्डे का कार्य शुरू हुआ। एकमात्र हमारे मिनी सचिवालय का कार्य शुरू किया था। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने और आदरणीय मुख्य मंत्री श्री सुक्खविन्दर सिंह सुक्खू जी ने भी अपना सहयोग दिया। आज वह बस मिनी सचिचालय बनकर पिछले 4 महीनों से तैयार हो गया है। लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है और वह जनता को समर्पित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजड़ी के अन्दर अग्नि शमन केन्द्र लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

12.03.20205/1720/AT/ HK /.1

श्री इन्द्रदत लखनपाल जारी :

लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो रहा ,जनता को समर्पित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा अग्निशमन केंद्र बिझड़ी के अंदर 8 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वह 6 महीने से तैयार पड़ा है लेकिन उसका भी कोई उद्घाटन नहीं हुआ । बिझड़ी के अंदर बहुउद्देश्यीय भवन बनना था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 करोड़ की उसकी डी0पी0आर0 बनी है बिझड़ी के अंदर कम्पयूटर हेल्थ सेंटर बना था उसकी फाइल

का कोई पता नहीं है। टेक्निकल सेंशन स्वास्थ्य विभाग ने उसमें देनी थी। पिछले ढाई साल से उसमें सेंक्शन नहीं हो रही है। यह मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं। आयुर्वेद विभाग की हालात इससे भी दयनीय है। एक मात्र हमारा 10 बैडिड हॉस्पिटल है बिझडी के अंदर और उसमें एक डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात वहां पर हमारे आदरणीय जय राम ठाकुर जी के समय में पंचकर्मा की मशीन स्थापित की थी और आज भी उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है इसके बारे में भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की थी और वे उसको देखकर भी आए थे। हमारे तीन आयुर्वैदिक हेल्थ सेंटर है जिनमें आज दिन तक ना डॉक्टर है ना फार्मासिस्ट है एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुली थी कूल्हेड़ा के अंदर जो कि जयराम ठाकुर द्वारा खोली गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको भी डीनोटिफाई कर दिया और जब मैंने इन बातों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से चर्चा की तो उन्होंने कहा आयुर्वेद विभाग मैंने बंद ही कर देना है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं इतना बड़ा आयुर्वेद विभाग, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण लोग आयुर्वेद संस्थानों में जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि मैं इनको बंद ही कर दूंगा। आप क्यों सारे संस्थानों को बंद करने लगे हैं? किसी ने सोच समझकर आयुर्वेद विभाग बनाकर रखा है। आयुर्वेद विभाग में कोई डॉक्टर की नई भर्तियां नहीं हो रही हैं।

बिझड़ी और भोटा के अंदर हमारे दो चौकियां हैं जो कि लंबे समय से स्थाई तौर पर चल रही हैं। आदरणीय जय राम जी ने उनको परमानेंट कर दिया था और आते ही मुख्यमंत्री महोदय ने उनको भी डीनोटिफाई कर दिया तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक

12.03.20205/1720/AT/ HK /.2

होगी? जो बिझड़ी का क्षेत्र है माननीय सभापति महोदय, उसमें 26 पंचायत आती हैं और 30 ,35 किलोमीटर का उसमें एरिया हैं। अगर उन चौकियों को ठीक ढंग से परमानेंट कर देते, वहां स्टाफ बढ़ता जो रोज वहां पर नशे का जो व्यापार हो रहा है और डोमेस्टिक बैलेंस के जो केसिज़ आ रहे हैं, उनमें कुछ रोक लगती । एक घंटा लगता है अगर कहीं पर वारदात हो जाए । और चार आदमी फील्ड में रहते हैं और एक आदमी

मुंशी होता है कैसे आप न्याय दिलाएंगे लोगों को ?गाड़ी उनके पास नहीं है की तुरंत कार्रवाई करके कहीं पहुंच जाए और फिर यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं । उसके बाद मैं अब जिला हमीरपुर के सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज में आता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहां के जो प्रिंसिपल महोदय हैं जो शुरू से निशाने पर हैं उनको बार-बार एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है ? ऐसा क्या है उनके अंदर जो चरित्रहीन व्यक्ति है उसको आपने मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाकर रखा है । जिसके ऊपर तरह-तरह के केसिज चले हुए हैं चंबा के अंदर उसके ऊपर केस चला है, टांडा हॉस्पिटल में उसके ऊपर कैसे चला है बावजूद उसके सरकार ने पता नहीं क्यों वहां पर उसको रखा हुआ है? 250 पोस्टें है मेडिकल कॉलेज में और वहां पर 100 के आसपास पोस्टें भरी हुई हैं और कोई प्रोफेसर नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर से काम चल रहा है और जो प्रोफेसर थे भी सर्जिकल विभाग में एच0ओ0डी0 थे भले ही आउट सोरस से थे पर बढ़िया काम कर रहे थे छुट्टियों के दौरान दिसंबर में उसको नीकाल कर बाहर कर दीया , और एक जूनीयर को एच0ओ0डी0 बना दिया हर पैहलू में आप फैल हो रहे है डी0एन0वी0 ने आपको वलैक लिस्ट कर दिया है

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी .....

12.03.2025/1725/md/yk/1

श्री इन्द्रदत्त लखनपाल... जारी

जो 36 डॉक्टर हमीरपुर से गए और उसके कारण मरीजों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। माननीय अवस्थी जी ने कहा कि हर विधान सभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई संस्थान नहीं खुला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब पड़ी हैं, डॉक्टर और रेडियोग्राफर उपलब्ध नहीं हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान महिलाओं को जमीन पर सुलाया जाता है क्योंकि वहां पर्याप्त बेड नहीं हैं।

इसके अलावा, मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों में भी अनियमितताएं हो रही हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए धन से बनने वाले कॉलेजों में ठेकेदारों द्वारा सब-कंट्रक्ट्रों को भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे काम रुका पड़ा है। एंबुलेंस सेवाएं भी चरमराई हुई हैं, कई जगह ड्राइवरों के पद खाली पड़े हैं। रात के समय मरीजों को खुद निजी स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ती है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज केवल एक रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है.

तीन-तीन महीने तक मरीजों को सीटी स्कैन के लिए इंतजार करना पड़ता है, मशीनें खराब पड़ी रहती हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हर मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन लगाए जाएंगे, लेकिन अब तक किसी भी मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा नहीं दी जा रही है। एम0आर0आई0 मशीन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार कैसे दावा कर रही है कि प्रदेश की जनता खुशहाल है और बड़ा काम हुआ है?

सरकार ने 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना चलाई, जिसमें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को 10-10 करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसका कोई लाभ नहीं मिला। बिजली विभाग की हालत भी खराब है। मेरे बड़सर डिवीजन में न तो खंभे हैं, न तारें, न कंडक्टर और न ही ट्रांसफार्मर है। ढाई साल से अधिकारी सिर्फ 15 दिनों में समाधान का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है.

12.03.2025/1725/एम0डी0/वाई0के0-2

मैं मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी पेयजल की एक महत्वकांक्षी योजना 131 करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई थी, लेकिन उसे गति नहीं मिल रही। पिछले वर्ष गर्मियों में निजी स्तर पर 15 लाख रुपये इकट्ठा कर टैंकरों से जल आपूर्ति करनी पड़ी। सरकार को चाहिए कि जिलाधीशों को कहा जाए कि गर्मी के मौसम से पहले ही ड्राई इलाकों में टैंकरों की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में की एक्सियन की पोस्ट भरने की भी कृपा करें क्योंकि एस0डी0ओ0 और स्टोर का जेई भी हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमारे डिवीजन में दो सालों से आधे व पौने, डेढ़ और दो इंच की पाइपें नहीं है। जब इसके बारे में अधिकारियों से बात कीजाती है तो कहते हैं कि 15 दिनों में आ जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में भी समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार ने हर विधान सभा क्षेत्र

में एक राजीव गांधीडे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात कही थी। भोरंज और विधान सभा क्षेत्र में जगह चिन्हित भी की गई थी, लेकिन बड़सर में अब तक काम शुरू नहीं हुआ। जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थीं, तो इसमें देरी क्यों हो रही है? क्या इसमें भेदभाव किया जा रहा है?

आई0जी0एम0सी0 शिमला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी बुनियादी जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. लैब में जरूरी किट नहीं हैं। आज अखबार में खबर छपी है कि वहां पर न तो थायराइड, एच0बी0ए1सी0 और विटामिन बी12 के टैस्ट हो पा रहे हैं। पिछले कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमारी इमरजेंसी तो इतनी बड़ी बन गई कि वहां

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

12.03.2025/1730/केएस/वाईके/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी---

बैड पर एक-एक मरीज सो रहा है। कल ही मैं आई0जी0एम0सी0 जा कर वहां के हालात देखकर आया हूं। दो-दो, तीन-तीन मरीज आज भी वहां पर एक बैड पर हैं। कोई चुपके से जा कर देख लेना, पता लग जाएगा। जहां तक युनिट्स की बात है, वह चाहे सर्जिकल का है या मैडिसिन का है, हर बैड पर दो-दो मरीज पड़े हैं। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के तीन मरीज थे जिनको देखने के लिए मैं वहां गया था। वहां पर डबलिंग है। जो मरीज चलकर शौचालय तक भी नहीं जा सकते, उनको भी दूसरे मरीज के साथ एक ही बैड पर रखा जा रहा है और वे दूसरे मरीजों को भी परेशान कर रहे हैं। फिर आप वाहवाही लूटे जा रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा नाम कर लिया। यहां पर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हैल्थ डिपार्टमैंट को रिव्यू करिए। बहुत बुरी हालत है। कहा तो यहां तक भी जा रहा था कि 9 महीने में हम रोबोटिक सर्जरी शुरू कर देंगे लेकिन पता ही नहीं है कि वह कहां गई? जो जनरल सर्जरी होनी है उसमें ही नम्बर नहीं आ रहा है। मैं हमीरपुर की बात करुंगा, हमारे बड़सर विधान सभा क्षेत्र से जो लोग आई0जी0एम0सी0 में आते हैं उनको छः-छः महीने का टाइम दे कर भेज देते हैं। जो गम्भीर मरीज है उसको आप बिना सर्जरी के घर भेज देंगे तो वह तो मर जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा

है, यह देखने वाली बात है। आपको स्वास्थ्य सुविधाएं चाक-चौबंद करनी पड़ेंगी क्योंकि उनको कोई गम्भीरता से ले ही नहीं रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप कभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आकर देखें कि वहां पर क्या हालत है? हमारे जिला का जो मैडिकल कॉलेज है, अभी तक वहां पर हार्ट स्पैशलिस्ट ही नहीं है। हमारे बड़सर विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक सिटी हार्ट हॉस्पिटल है और आए दिन वहां चार से पांच लोगों को स्टंट पड़ते हैं। भारी-भरकम पैसा लोगों को खर्च करना पड़ता है। जो हिमकेयर योजना चली थी, उसको आपने उस हॉस्पिटल से बंद कर दिया। कम से कम वहां पर उसको तो लागू कर दो। जो वहां पर गरीब लोग आते हैं उनको साढ़े तीन-तीन लाख रुपये का बिल बनाकर भेज देते हैं। वे परेशान हो जाते हैं। कई तो वहीं पर मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि आप कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं?

12.03.2025/1730/केएस/वाईके/2

केवल मात्र यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। धरातल में देखिए कि हालत क्या है? आपने एक गारंटी में यह भी कहा था कि आप मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शुरू करेंगे। ढाई साल हो गए, हमारे वहां तो इस तरह की कोई सेवा शुरू नहीं हुई। मैं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करुंगा जिन्होंने अपनी सांसद निधि से एम्बुलेंस चला रखी है जो पूरे गांव में जा कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करती है। जो कहना है, उसको करके दिखाइए। झूठी वाहवाही लेने से कोई फायदा नहीं है। महिलाओं को आपने 1500 रुपये के रूप में पहले ठगा। 10-10 बार उनसे फॉर्म भरवा लिए। ...(व्यवधान) मैंने भी भरवाए और उस समय हमने भी सोचा कि शायद 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिल जाएंगे लेकिन अब जूते पड़ रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी महिला को 1500 रुपये नहीं मिले। अब उसके नियम बदल दिए। यह उन महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके घर से कोई पैंशन नहीं लेता। यह कैसी सरकार है?

आपने सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालकर बाहर कर दिया। लगभग 30-35 हजार आउटसोर्स कर्मचारी आपने बाहर निकाल दिए। मंत्री जी, सी0एच0ओ0 महिलाएं बेचारी आपसे कई बार मिलीं कि हमारा कुछ भला करो लेकिन उसकी एवज में आपने नई भर्ती

कर दी, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। आपने आंगनवाड़ी, आशावर्कर, ये जो हमारे छोटे-छोटे संस्थान हैं, उनमें 200, 300 और 500 बढ़ाकर बहुत बड़ा नाम कमा लिया। अगर हजार, पन्द्रह सौ, दो हजार या पांच हजार रुपये दिए होते, तब भी मानते कि आपने कुछ दिया। आप मल्टी टास्क वर्कर और पार्ट टाइम वर्कर भर रहे हैं। पूरा दिन उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। सुबह 9.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक पार्ट टाइम वर्कर काम करते हैं। उनकी आप वहां पर चमड़ी उधेड़ते हैं और पैसे 5500 रुपये देते हैं। वे इस तरह से अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करेंगे? वे तो भ्रष्टाचार ही करेंगे। 5-5 महीने उनको पैसे नहीं मिलते। उप-मुख्य मंत्री जी , जितनी भी आपकी स्कीमें आउटसोर्स हुई हैं, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी और आपने आश्वस्त किया था कि यह जो मशीनरी की आउटसोर्स प्रथा है इसको हम बंद करेंगे। विभाग इनको चलाएगा लेकिन कोई भी नहीं चला रहा है। सारी मशीनरी का बेड़ा गर्क हो गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

12.03.2025/1735/AV/एजी/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल------ जारी

मैंने पिछले हफ्ते अपने विधान क्षेत्र की सभी वॉटर सप्लाई स्कीम्ज का दौरा किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी बहुत बुरी हालत है। वहां पर फिल्टर्ज और मोटर्ज की बहुत बुरी हालत है। इससे भी बुरी हालत मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगी 10 से 12 सिंचाई स्कीम्ज की हैं जोकि लगभग बंद पड़ी हैं। वे काफी समय से बंद पड़ी हैं और मैं इस मुद्दे को कई बार उठा चुका हूं कि आप उनकी मोटर्ज को उठाकर या तो वहां की पेयजल योजनाओं में लगा दें या वहां बोर करके उन स्कीमों को चलाया जाए।

यहां पर अभी माननीय कृषि मंत्री जी नहीं बैठे हैं। वे कह रहे थे कि हमने कृषि के क्षेत्र में प्रदेश के बहुत सारे युवाओं को स्वरोज़गार प्रदान किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहां से रोज़गार दे दिया जब आपकी पानी की स्कीम्ज व सिंचाई की स्कीम्ज ही नहीं चल रही हैं। वहां सारा एरिया ड्राई है,फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि आप कृषि क्षेत्र में

स्वरोज़गार प्रदान कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आज कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे वोकेशनल टीचर्ज के बारे में भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर टीचर्ज और एस0एम0सी0 टीचर्ज के बारे में भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही है। यह सरकार चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुकी है। प्रदेश में बहुत बुरे तरीके से आर्थिक संकट फैला हुआ है। आप चाहे जो मर्जी कह लें या जितने मर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर लें लेकिन हालात बहुत खराब है और इस बात को दबी जुबान से हमारे सत्ता पक्ष के लोग भी मानते हैं। प्रदेश में विकास के सारे काम रुक गए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की लोक निर्माण विभाग से संबंधित 6 सड़कों की डी0पी0आर0 विभाग के पास पड़ी है मगर उसके लिए नाबार्ड से पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि नाबार्ड की लिमिट खत्म हो गई। अब आप उस लिमिट को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वह बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे विधायकों की पैंडिंग पड़ी हुई डी0पी0आरज0 के लिए पैसा मिले। प्रदेश में विकास के सारे काम रुके हुए हैं। आज ठेकेदार काम करने से मना कर रहे हैं। मैं इस अभिभाषण में पढ़ रहा था कि एक लाख

12.03.2025/1735/AV/एजी/2

रुपये से ऊपर के सभी टेंडर ऑनलाइन होंगे और आप उसके लिए बड़ी वाहवाही ले रहे हैं। प्रदेश में बड़े-बड़े सभी ठेकेदार 50-50 टेंडर भर रहे हैं। प्रदेश में छोटे ठेकेदार जो यह सोच रहा थे कि सरकार आई है तो हम भी थोड़ी-बहुत ठेकेदारी करके अपना जीवन-यापन करेंगे, उनको तो आपने खत्म कर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन है? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं है बल्कि यह एक अनर्थ व्यवस्था है जोकि आप लोगों ने शुरू की है। इसको बंद कीजिए और सभी मंत्रिमण्डल के लोग ध्यान से बैठकर सोचिए कि लोगों की भलाई के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। आप इसलिए काम मत कीजिए कि हमें विपक्ष को जवाब देना है। आप जनता को जवाब देने के लिए नीतियां व योजनाएं बनाएं।

यहां पर माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी 52 पंचायतों के ऊर केवल 17 सचिव हैं। वहां पर तकनीकी सहायक भी केवल 17 हैं और ग्राम रोज़गार सहायक 18 हैं। अब आप बताइए कि मनरेगा का काम कैसे चलेगा और आप उसके अंतर्गत टारगेट कैसे अचीव करेंगे? वहां पर कोई भर्ती नहीं हुई। आपने नई पंचायतें बनाने का काम शुरू कर दिया और आपने बड़सर के अंदर एक नई नगर पंचायत बना दी तथा उसमें पूरी बणी पंचायत को अधिसूचित कर दिया। इसके पीछे क्या कारण है? आप लोग जो प्रदेश की जनता को हर तरफ से तंग करने के काम कर रहे हैं, इनको बंद किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विपक्ष के लोगों की बातों को सकारात्मक रूप से सुनिएं और उनके ऊपर विचार-विमर्श करके काम करने के प्रयास कीजिए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस दस्तावेज का समर्थन करने में असमर्थ हूं क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा जी भाग लेंगे।

12.03.2025/1735/AV/एजी/3

श्री हरदीप सिंह बावा : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव और जिसका अनुसमर्थन माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी ने किया है, इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

यहां पर दिनांक 10 मार्च, 2025 को जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। इस दस्तावेज में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

टी सी द्वारा जारी

12.03.2028/1740/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री हरदीप सिंह बावा ... जारी

क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आम जनमानस के जीवन में प्रगति और विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने अपने भाषण में दी गई चुनावी घोषणाओं में से 6 महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूरा किया है जिनमें कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 की सौगात, महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि देने की बात, 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वराज स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, गाय बैंक के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि और गोबर खरीद योजना शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित हुई। उसके पश्चात् वर्ष 2023 में प्रदेश में प्राकृतिक त्रासदी आई जिसने प्रदेश को बड़ी चुनौती दी। वर्ष 2023 की आपदा से प्रभावित परिवारों की वेदना को समझते हुए सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज जारी किया। इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से ध्वस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये तथा आंशिक रूप से ध्वस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये की सहायता राशि सीमित संसाधानों के बावजूद जारी की गई। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रभावित परिवारों को ठहरने की व्यवस्था के साथ 3 महीने के लिए राशन और गैस सिलेंडर भी प्रदान किए गए। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी कैबिनेट और सभी मंत्रियों का धन्यवाद करता हूं।

सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार द्वारा 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया गया और बाढ़ प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद की गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत और नीति पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। सरकारी दस्तावेज में सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़, 96 लाख, 64 हजार कार्य दिवस सुनिश्चित कर 6.36 लाख परिवारों को रोजगार दिया जिनमें से 64% रोजगार महिलाओं को प्रदान किया गया। मनरेगा के तहत एक लाख 38 हजार 913 से अधिक कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिन पर 1252 करोड़ रुपये खर्च किए गए

12.03.2028/1740/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

हैं। राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 रुपये की मजदूरी अधिसूचित कर राज्य के गैर-जनजातीय क्षेत्रों में अपनी निधि से 64 रुपये अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जा रही है। वर्तमान में टॉप-अप मजदूरी के कारण इस वर्ष मनरेगा मजदूरों को 216 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

इसके अलावा, सरकार ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण हेतु दृढ़ संकल्प है। सभी 19 अधिसूचित रोजगारों में काम करने वाले अंशकालिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 01 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत अब तक प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कुल 47000 श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है जिसके लाभार्थी को न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

कृषि क्षेत्र की बात करें तो मैं माननीय मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किसानों को गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 645 किसानों से 6.55 करोड़ रुपये की लागत से कुल 2880 मीट्रिक टन गेहूं तथा 5572 किसानों से 85.64 करोड़ रुपये की लागत से कुल 36902 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। जो यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के मुद्दों व फसल के प्रति कितनी गम्भीर है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

12-03-2025/1745/ns-as/1

श्री हरदीप सिंह बावा------ जारी

व 5572 किसानों से 85.34 करोड़ रुपये की लागत से कुल 36,902 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। जो अपने आप में यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किसानों के प्रति, उनके मुद्दों व उनकी फसल के प्रति कितनी गम्भीर है। इसके अतिरिक्त 1.19 करोड़ रुपये की लागत से प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उत्पादित कुल 399 मीट्रिक टन मक्का की खरीद से कुल 1508 किसान लाभान्वित हुए हैं। यह बहुत बड़ी सोच व काम है, जो मैं समझता हूं कि किसानों के मुद्दों व फसल को देखते हुए सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मैं इण्डस्ट्रियल एरिया बी0बी0एन0 से आता हूं। हालांकि, मेरा नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र है और वहां पर वर्ष 2003 से वर्ष 2005 तक ज्यादा इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग आज भी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। आज भी बहुत सी ऐसी भूमि है जहां पर सरकार के पास लैंड बैंक्स हैं। जहां सरकार आज नीतिगत फैसले करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजैक्ट बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजैक्ट दबोटा के गांव नसराली में बन रहा है जिसका मुख्य मंत्री जी ने शिलान्यास किया है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूं। बद्दी-बरोटीवाला में बहुत ज्यादा उद्योग लगे हुए हैं। हमें इंडस्ट्री के माध्यम से डायरेक्ट व इन-डायरेक्ट इम्पलॉयमैंट मिली हुई है। मैं अगर ट्रांसपोर्ट सैक्टर की बात करूं तो आपको पूर्व सरकार व वर्तमान सरकार का फर्क बताना चाहता हूं। आज बी0बी0एन0 में लगभग 20,000 के आसपास ट्रांसपोर्ट व्हीकल्ज हैं और ये कॉमर्शियल व्हीकल्ज हैं। आज हम डायरेक्टी और इन-डायरेक्टली इण्डस्ट्रीज के साथ कार्य कर रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार इण्डस्ट्रियल फ्रैंडली थी और उन्होंने कभी भी लोगों की तरफ नहीं देखा। लेकिन वर्तमान सरकार ने हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को सुना और उसे हल करने का प्रयास किया। जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी व उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं। वर्ष 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही अर्की विधान सभा क्षेत्र जहां से श्री संजय अवस्थी जी विधायक हैं वहां पर अम्बुजा सीमेंट प्लांट अदानी ग्रुप के द्वारा खरीदा गया तथा वहां पर तीन महीनों तक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चलती रही। उसका निपटारा मुख्य मंत्री जी के द्वारा किया गया। आज वहां पर ट्रांसपोर्ट साथियों को रोजगार मिला है

12-03-2025/1745/ns-as/2

और रेट की सैटलमैंट भी हुई है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी, उप-मुख्य मंत्री व उद्योग मंत्री जी ने श्री संजय अवस्थी के साथ इंटरवीन करके रेट की सैटलमैंट करवाई और आज यह कार्य चला हुआ है।

सभापति महोदय, पूर्व भाजपा सरकार यूनियन फ्रैंडली नहीं थी बल्कि इण्डस्ट्रियल फ्रैंडली थी और यूनियन को कम इज्जत दिया करती थी। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने यूनियन को तरजीह दी है और जिन लोगों की जमीन इण्डस्ट्री में चली गई हैं उन लोगों को इन-डायरेक्ट काम इण्डस्ट्री के माध्यम से मिल रहा है। जिसके लिए सरकार एक अहम भूमिका निभाने का काम कर रही है।

यहां विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे कि एच0आर0टी0सी0 के कर्मचारियों को सैलरी व पेंशन नहीं दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार में सैलरी व पेंशन का अगर सबसे ज्यादा इश्यू रहा है तो वह एच0आर0टी0सी0 से संबंधित रहा है। सरकार का कार्यकाल दो वर्ष तीन महीने का हो गया है और मैं मुख्य मंत्री जी व उप-मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दो वर्ष तीन महीने के कार्यकाल में एच0आर0टी0सी0 की कोई हड़ताल नहीं हुई है

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

12.03.2025/1750/RKS/AS-1

श्री हरदीप सिंह बावा.. जारी

और एक बार भी पेंशन और सैलरी में कोई देरी नहीं हुई है। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार के समय भी हड़ताल हुई थी और पेंशन एवं सैलरी में देरी हुई थी। आप उस समय को भी याद रखें। पूर्व सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार थी जो आज हमें पाठ पढ़ाने का काम कर रही है। मेरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र से संबंधित चाहे वह ड्रग

माफिया की बात हो इस पर काबू पाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने जो कड़े फैसले लिए हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। ड्रग माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए जो हमारी सरकार ने कानून बनाया है उसे धरातल पर लागू करने की जरूरत है। मैं जिला शिमला, जिला सोलन और जिला बद्दी की पुलिस को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए न केवल चिट्टा तस्करों, बल्कि चूरा पोस्त और अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यहां पर अवैध खनन की बात की गई। नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सरकार के समय अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा था और वही लोग अवैध खनन करते थे जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता थे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी माइनिंग लीजें आज भी उन नेताओं और उनके रिश्तेदारों के पास हैं जो भाजपा सरकार के समय दी गई थीं। कांग्रेस सरकार के दौरान कोई माइनिंग लीज नहीं दी गई। ये वही माइनिंग लीजें हैं जिनसे आज हमारे गांव व मलैणी पंचायत, जिसके बारे में मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी चर्चा की थी को बहुत खतरा है। हमारे कुण्डलू खड्ड के पास जो मलैणी पंचायत और पपलेड़ गांव हैं उनके नीचे सरकारी भूमि को माइनिंग लीज के तौर पर भाजपा सरकार ने दिया था। अगर आज वहां खनन होता है तो मैं कह सकता हूं कि वे गांव बारिश के मौसम में जलमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरा सदन से आग्रह है कि सरकार कड़ा निर्णय लेकर ऐसी माइनिंग लीजों को रद्द करें। यह माइनिंग लीजें भाजपा के पदाधिकारियों और उनके रिश्तेदारों की हैं। मैं नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे जीताकर इस सदन में भेजा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो 10 जुलाई, 2024 को चुनाव हुआ था उसमें भाजपा के साथी वहां प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष भी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। आज ये सरकारी दस्तावेज़ को झूठा बता रहे हैं लेकिन इन्होंने चुनाव के समय मेरे बारे में इतना दुष्प्रचार किया जिसका जवाब नालागढ़ की जनता ने दिया है। मेरे ऊपर 133 झूठे केसों का इल्जाम लगाया गया। जब

12.03.2025/1750/RKS/AS-2

कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वह चुनाव आयोग को अपना एफिडेविट देता है और उसमें यह दर्शाया जाता है कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने में सजा का प्रावधान है, और कितने में ट्रायल चल रहा है। सिर्फ चुनाव जीतने के

लिए पूर्व मुख्य मंत्री और इस सभागार में बैठे भाजपा के विधायक दिन-रात एक ही प्रचार करते रहे कि हरदीप सिंह बावा के ऊपर 150 केस पंजीकृत हैं। जब मैंने एफिडेविट मंगवाया और देखा तो मेरे ऊपर सिर्फ तीन केस ही पंजीकृत थे और वे भी आपकी सरकार के समय में बने थे। वे रोड जाम के केस थे लेकिन इन्होंने इतना दुष्प्रचार किया जिसका कोई हिसाब नहीं था। मैं मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रभारी रहे श्री हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे चुनाव में ऐसी रणनीति बनाई जिससे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सच्चाई की जीत हुई है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

12.03.2025/1755/बी.एस./डी.सी./-1

श्री हरदीप सिंह बाबा जारी...

मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 का चुनाव हुआ तो भाजपा हारी, भाजपा अपने साथ कांग्रेस का सिटिंग एम0एल0ए0 ले गई। वर्ष 2022 का चुनाव हुआ, फिर से भजपा हारी। जो व्यक्ति चुनाव जीता उसे भाजपा अपने साथ ले गई। वर्ष 2024 का चुनाव हुआ उसमें फिर से भाजपा हार गई। अरे भई, अब तो समझ जाइए, अब कोई भी जाने वाला नही है, आपके पास बहुत लोग आ गए हैं। परंतु जहां तक नालाबढ़ के विकास की बात है, आप रिकार्ड निकाल करके देख लें, वर्ष 2017-22 की सरकार में पूर्व मुख्य मंत्री जी के नालागढ़ के तीन दौरे हुए हैं। एक दौरा हुआ, उस समय राज्यपाल महोदय के साथ आप आए थे और वह एक कॉमन विजिट थी, वह एक क्लीन ड्राइव थी, उसे फ्लेगऑफ करना था। उस दौरे में एस0पी0 और डी0सी0 सस्पेंड हो गए। दूसरा दौरा वर्ष 2022 में चुनाव से चार माह पूर्व हुआ जिसमें एक पूर्व विधायक की पीठ थपथपाई गई और तीसरा दौरा चुनाव से केवल एक माह पहले हुआ जब तीसरे व्यक्ति की पीठ थपथपाई गई।

इन तीन दौरों में जो लगभग 20 से जयादा संस्थान खोलने का काम भाजपा की सरकार ने किया उन्हें खोलने की जरूरत नहीं थी। इन संस्थान की केवल चुनाव जीतने के लिए

घोषणाए कर दी गईं। जो घोषणाए इनके द्वारा की गई थीं वे सारी रद्द हुई, क्योंकि उनके लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं था। पंरतु आज नीड बेस पर उन्हीं मुद्दों को मैं सरकार के समक्ष उठा रहा हूं जिसमें हमारी पंजेरा की पी0एच0सी0 को बहाल किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि नालागढ़ में जो विकास हुआ वह वर्ष 2012-17 की कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया है। उस समय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे। हमारे क्षेत्र में चाहे सिंचाई की स्कीमें लगी, चाहे पीने के पानी की स्कीमें लगी, चाहे चैक डैम लगे, चाहे आर0टी0ओ0 ऑफिस का निर्माण हुआ। पंजेरा में उप तहसील बनी, रामशहर में तहसील बनी, रामशहर को पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 किया गया। यह सारे कार्य कांग्रेस सरकार ने किए। इसके साथ-ही-साथ रामशहर को कॉलेज दिया गया। हम अपनी सरकार में रामशहर कॉलेज को चार कमरों में चला करके गए थे, इस कॉलेज के लिए हम 13 करोड़ रुपये दे करके गए,

12.03.2025/1755/बी.एस./डी.सी./-2

परंतु पूरे पांच साल में वहां एक ईंट नहीं लगी। पांच साल तक पंजेरा की तहसील पटवार सर्कल में चलती रही परंतु वहां एक ईंट नहीं लगी। रामशहर में उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया, परंतु पूरे पांच साल में बिल्डिंग नहीं बनी। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और इनका धन्यवाद करना चाहता हूं इन्होंने वर्ष 2022 में सरकार बनते ही पंजेरा उप-तहसील की बिल्डिंग का टेंडर किया और आज उस बिल्डिंग का 80 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है और रामशहर कॉलेज का भी 70-80 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी 13 दिसम्बर को जो राज्यपाल महोदय का दौरा हुआ, हमारे उप-मुख्य मंत्री जी का 14 दिसम्बर को दौरा हुआ और हमारे मुख्य मंत्री जी का दौरा 15 दिसम्बर को हुआ जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वहां पर तीन पुलों का शिलान्यास किया गया जिसमें कोटला से ब्रूणा, हमारी रेतल खड्ड पर एक और पुल लगना है और भटोली खड्ड पर जो पुल का निर्माण होना है, इन तीनों पुलों का शिलान्यास किया गया। मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्री

जी द्वारा लगभग 26 इरिगेशन की स्कीमों का उद्घाटन किया गया और छः पीने के पानी की स्कीमों का उद्घाटन किया गया। ये वह काम है जो पिछली सरकार के द्वारा भी हो सकते थे। परंतु नहीं हुए और यह कार्य आदरणीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के समय में हुए मैं इनका ह्दय से धन्यवाद करता हूं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

12.03.2025/1800/DT/DC-1

श्री हरदीप सिंह बावा जारी...

यहां पर अभी हमारे माननीय सदस्य ने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, वाटर गार्ड की पॉलिसी के बारे में बात की। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इतिहास निकाल कर देखिए और सोचिए की आशा वर्कर किस की देन है? आशा वर्कर पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है। आशा वर्कर को बाहर निकालने का काम पूर्व की भाजपा सरकार जो श्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में चल रही थी उसने किया और उनको रीइन्स्टेट करने का काम हमारी प्रदेश के मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने किया। आंगनवाड़ी वकर्ज हमेशा कांग्रेस की सरकार में लगे। वाटर गार्ड की पॉलिसी भी वर्ष 2017 में कांग्रेस की सरकार ने ही बनाई थी। पॉलिसी हमने बनाई और सरकार बनते ही उस पॉलिसी को भाजपा सरकार ने तोड़ने-मोड़ने का काम किया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ा और ये जो दस्तावेज रखा गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और सरकार को इस दस्तावेज के लिए बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नालागढ़।

12.03.2025/1800/DT/DC-2

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, इन माननीय सदन में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने 10 मार्च, 2025 को जो अभिभाषण दिया है, उस पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसमें वर्तमान सरकार ने हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय से बहुत सारी बातें जो झूठ है, इस माननीय सदन में बुलाई गई हैं और उन्हें इसे पढ़कर बहुत खेद हुआ है। साथ-ही-साथ इन्होंने 6 गारंटीज की बात कही है कि हमने 6 गारंटीज पूरी कर दी हैं। एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. में इन्होंने कहा था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियेां को ओ.पी.एस का लाभ मिलेगा। आज बिलजी बोर्ड के कर्मचारी ओ.पी.एस. के लिए तरस रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी ओ.पी.एस. के कर्मचारी तरस रहे हैं, इसके अतिरिक्त नगर पंचायत, नगर परिषद के कर्मचारी भी ओ.पी.एस. के लिए तरस रहे हैं। फोरेस्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी ओ.पी.एस. का लाभ नहीं दिया गया है। अभी हिमाचल प्रदेश में 11 विभाग ऐसे हैं जो ओ.पी.एस. के लिए तरस रहे हैं। पहला झूठ तो इन्होंने जो एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. में लाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को बोला था, वह अभी तक अधूरा है। दूसरा, महिलाओं के लिए कहा था कि 18 से 60 वर्ष की प्रदेश की प्रत्येक महिला 1500 रुपये की राशि प्रतिमाह देंगे। आप वर्ष 2011 के सेंसस के हिसाब से प्रदेश की आबदी लगभग 70 लाख है और उसमें से 35 लाख के लगभग महिलाओं की संख्या होगी। लेकिन अगर 2025 के सेंसस में प्रदेश की आबदी 1 करोड़ से ऊपर चली गई होगी और उसमें महिलाओं की संख्या भी लगभग 50 लाख पहुंच गई होगी। इन्होंने सिर्फ 30000 महिलाओं को यानी केवल 1 प्रतिशत महिलाओं को ही 1500 रुपये का लाभ दिया है और 99 प्रतिशत महिलाओं को अभी ये धनराशि देने को शेष है। इन्होंने महामहिम राज्यपाल से 30000 महिलाओं को आंकड़ा पढ़वाया है। ये भी वे महिलाएं हैं जिनको आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने किसी-न-किसी स्कीम के अंतर्गत पैंशन का लाभ दिया था। रोजगार के लिए भी कहा गया था कि पहले वर्ष 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा और 5 साल में पांच लाख

बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोराना काल में हमारी सरकार ने आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हैल्थ डिपार्टमेंट में 1800 कर्मी लगाए थे परंतु आपने उन्हें भी नौकरी से परे हटाया। जब परिवार वालों ने कोरोना मरीजों को अस्पताल छोड़ा था तो उन लोगों ने ही उन मरीजों को संभाला था। उसके बावजूद भी

12.03.2025/1800/DT/DC-3

सरकार ने उन पर कोई दया नहीं की है। अभी जो नर्सें नियुक्त की जा रही हैं वे भी उनके सर्किल में ही है और वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए कि कोरोना काल में जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जाति, धर्म, पार्टी छोड़कर मरीजों की सेवा की थी, उन्होंने यह नहीं देखा था कि यह मरीज कांग्रेस पार्टी का है या भाजपा का, जिसको कोरोना हुआ था उन सबका अस्पताल में बराबर इलाज किया था।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

12.03.2025/1805/एच.के.-एन.जी./1

श्री बलबीर सिंह वर्मा.....जारी

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से विनती है कि कोरोना काल में आऊटसोर्स पर लगे जिन कर्मचारियों को निकाला दिया गया है उन्हें वापिस नियुक्ति प्रदान की जाए। मेरे चौपाल विधान सभा क्षेत्र में आऊटसोर्स के माध्यम से 20 स्टाफ नर्सें लगी थीं। उन सभी को एक मुश्त निकाल दिया गया है जिस कारण चौपाल, नेरवा व कुपवी क्षेत्र में आज केवल एक स्टाफ नर्स है। मेरे क्षेत्र में कुल 72 स्टाफ नर्सिस के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अन्याय हुआ है।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार ने गाय व भैंस के दूध के बहुत ज्यादा दाम बढ़ाए हैं। मेरे चौपाल विधान सभा क्षेत्र में तो किसी से भी एक लीटर दूध नहीं लिया गया है। इसके अलावा जिस दाम पर सरकार दूध लेना चाहती है तो उस

दाम पर कोई दूध देने वाला ही नहीं है। प्रदेश सरकार ने जो 10 गारंटियां दी थीं उसमें आपने अपने मुखारबिंद से कहा है और हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने कहा है कि दूध को 100 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप दूध के दाम को 100 रुपये प्रति लीटर कीजिए तभी लोग दूध बेचना शुरू करेंगे। जिस रेट पर सरकार दूध खरीदने की बात कर रही है उससे ज्यादा रेट तो लोकल में ही मिल जाता है।

सभापति महोदय, इसके अलावा सरकार ने गोबर खरीदने के लिए भी गारंटी दी थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में तो सरकार ने किसी से एक किलो गोबर भी नहीं लिया है। सरकार हर बार कहती है कि गोबर खरीदना शुरू कर रहे हैं जिस कारण लोगों ने गोबर के ढ़ेर लगा दिए हैं।

12.03.2025/1805/एच.के.-एन.जी./2

अब हम गोबर को ट्रकों में भर कर सचिवालय भेज देंगे क्योंकि लोगों ने काफी ढ़ेर लगा दिए हैं और मेरे क्षेत्र में अब जगह नहीं बची है। मेरा सवाल है कि प्रदेश सरकार गोबर की खरीद कब शुरू करने वाली है?

सभापति महोदय, मैं नशे के संदर्भ में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में नशा बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। आज नशा उस गांव में भी पहुंच गया है जहां पर जाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मैं बहुत हैरान हूं कि हमारे दूर-दराज के क्षेत्रों में भी युवा नशे के गिरफ्त में चले गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब इंग्लैंड ने चीन को अपने अधीन करना था तब उन्होंने वहां पर कई सालों तक नशा भेजा था। उन्होंने युवाओं को नशे में डाल कर वहां पर कब्जा किया था। हमारी स्थिति भी यह है कि हमारा युवा भी नशे की गिरफ्त में जा रहा है। यदि प्रदेश सरकार इसमें सख्त कार्रवाई नहीं करेगी या कोई सख्त कानून नहीं बनाएगी तो स्थिति बहुत ज्यादा गम्भीर हो जाएगी। नशे का प्रचलन 3-4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उससे पहले हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा नशा नहीं था। मेरे विधान सभा क्षेत्र के दूर-दराज क्षेत्र, जहां पर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहां

पर भी चिट्टा पहुंच गया है। मेरा आग्रह है कि इसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। यदि समय रहते इसके लिए सख्त कानून बनाया जाएगा तभी हमारे प्रदेश का युवा नशे से बच पाएगा और हमारा प्रदेश समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में 32-33 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वे स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं जिनके लिए स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने बोला था कि वहां पर 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और वहां पर स्कूल जरूरी है। यह बात ठीक है कि हमारी व आपकी सरकार ने वहां पर टाइम से स्टाफ उपलब्ध नहीं करवाया जिस कारण वहां से बच्चों ने पलायन कर लिया और वह स्कूल बंद करना पड़ा। मेरा यह कहना है कि यदि वहां पर स्टाफ होता तो वे स्कूल कभी भी बंद न होते। मेरी सरकार से विनती है कि जिस स्कूल में जाने के लिए 7-8 या 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है तो उस स्कूल

12.03.2025/1805/एच.के.-एन.जी./3

में स्टाफ उपलब्ध करवाएं और वहां पर बच्चों को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे क्षेत्र के नेरवा, चौपाल, कुपवी और देहा क्षेत्र के लोगों ने अन्य क्षेत्रों में कमरे लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। यदि उनके क्षेत्र के स्कूल में स्टाफ होगा तो वे वापिस अपने घरों की ओर आ जाएंगे।

सभापति महोदय, आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने कुपवी में कॉलेज दिया था। हिमाचल प्रदेश में सबसे दूर-दराज का क्षेत्र कुपवी है। कुपवी क्षेत्र की सभी 15 पंचायतें बैकवर्ड हैं। देश के 500 आकांक्षी ब्लॉक्स में कुपवी ब्लॉक भी शामिल है। कुपवी में पिछले 10 साल में ही विकास की गति बढ़ी है। वहां पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला.

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

श्री बलबीर वर्मा... जारी

वहां पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, पी0एच0सी0 और अस्पताल भी श्री जय राम ठाकुर जी ने दिए थे। मेरी आपसी विनती है कि आप कुपवी के कॉलेज को बंद न करें। आपने पूरे प्रदेश के लिए एक पैमाना लगाया है कि जहां बच्चे कम होंगे उन संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। बच्चों की संख्या तो तब बढ़ेगी जब आप वहां पर पूरा स्टॉफ भेजेंगे। उन कॉलेजों में न एसिस्टेंट प्रोफैसर हैं और न ही एसोसिएट प्रोफैसर हैं। अगर आप वहां अध्यापक भेजते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर 10 दिन के भीतर सैंकड़ों की संख्या में छात्र हो जाएंगे। मैं आपके सामने पूरे कुपवी क्षेत्र की तस्वीर रख रहा हूं। कुपवी में बेटियां बहुत कम पढ़ती थी। जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बेटियां कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती थी। अगर आप पूरा स्टाफ भेज देते हैं तो कुपवी की बेटियां और बेटे वहां पढ़ने जाएंगे अन्यथा वे बच्चे किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए सीधे चले जाएंगे। श्री हर्षवर्धन चौहान जी सही तरीके से बता सकते हैं कि कुपवी कितनी दूरदराज का क्षेत्र है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी उपस्थित नहीं है लेकिन मेरी आप दोनों से विनती है कि आप कुपवी के कॉलेज, जो ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया है उसके बारे में अलग से क्राइटेरिया बनाएं। वह संस्थान बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टाफ देते हैं तो जो आपने पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या पैमाना बनाया है उससे ज्यादा बच्चे वहां पर होंगे। उस दूरदराज क्षेत्र के लोगों की आवाज को श्री जय राम ठाकुर जी ने सुना है। मेरी आपसे विनती है कि आप भी उन लोगों की आवाज को सुनें और वहां पर पूरा स्टाफ भेजा जाए अन्यथा उन लोगों के साथ व वहां की 15 पंचायतों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ...(व्यवधान) जब किसी क्षेत्र में कोई मंत्री जाता है तो वह विकास करने के लिए वहां जाता है। लेकिन मेरे क्षेत्र में कोई मंत्री जाता है तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं वह किस हैड का फंड वापिस ले जाएगा। मेरे कुपवी कॉलेज के लिए स्वीकृत 5 करोड़ रुपये और चौपाल कॉलेज का 2 करोड़ रुपये वापिस ले लिया गया। आपने स्कूलों के लिए स्वीकृत पैसा भी वापिस ले लिया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ननार है उसमें सिर्फ पेंट का कार्य रह गया था।

उसके लिए श्री जय राम ठाकुर जी ने 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे लेकिन आप दो वर्षों में उस स्कूल के पेंट का कार्य नहीं कर सके। उस स्कूल का भवन पूरी

12.03.2025/1810/पीबी/AS-2

तरह तैयार है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, देहा है। उस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूं। जब मैंने यह बात श्री जय राम ठाकुर जी को बताई तो इन्होंने एक मुश्त उस स्कूल के लिए 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। उस भवन का कार्य डेढ़ वर्ष पहले पूर्ण हो गया है लेकिन आप उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बाहर घूम रहे हैं और इसका कारण यह है कि वह मेरे घर के पास का स्कूल है। यहां पर आप यह बात करते हैं कि बड़ी पारदर्शिता के साथ 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का काम होना चाहिए। आप इसके लिए एक रूपरेखा बनाएं क्योंकि हमारा संस्थान दिन-प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। हम आपस में लड़ रहे हैं लेकिन हमें साढ़ चार वर्षों तक तो इस संस्थान को मजबूत बनाना चाहिए। आपको सभी विधायकों के कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। अभी शिक्षा मंत्री जी सदन में उपस्थित हुए हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, देहा का उद्घाटन जल्द रखें। अभी मेरे क्षेत्र के 6 स्कूलों का कार्य होना शेष है। मेरी विनती है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं उसमें उद्घाटन पट्टिका में मेरा नाम भी जरूर अंकित किया जाए। मेर विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 132 सड़कें बनी हैं। जब तक इस संसार में मानव रहेंगे चौपाल की जनता भारतीय जनता पार्टी और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को कभी नहीं भूलेगी।

श्री ए.पी. द्वारा जारी

12.03.2025/1815/A.P/Y.K/01

श्री बलवीर सिंह द्वारा जारी .....

हम यहां हर बात के लिए लड़ रहें है यह ठीक नहीं है, हर सरकार अपनी राजनिति 6 माह के लिए सबके लिए फ्री रखें और जो साढ़े चार साल बचते हैं जिसमें हम इस संस्थान को

मजबूत करे और विधायको का भी ध्यान रखे। माननीय शिक्षा मंत्री जी आएं है मेरी उनसे यह विनती है जो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाल दया है उसका उद्घाटन जल्द-से-जल्द किया जाएं। अगर आप मेरी विनती स्वीकार करे, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं वहां मेरा नाम भी जरूर लगाएं, क्योंकि बड़े मुश्किल से बनाया है। माननीय सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 132 सड़के बनी। जब तक इस संसार में मानव रहेगे, मेरे चौपाल के लोग भारतीय जनता पार्टी और स्वर्गीय अटल विहारी जी को कभी नहीं भूल सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी भी विधान सभा क्षेत्र में इतनी सड़के नहीं बनी, जितनी हमारे चौपाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी हैं। ...(व्यवधान)

सर, मैं सारी बाते आपके सामने रख रहा हूं। मेरे चौपाल में 130 के करीब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से फेज़ -1 में सड़के बनी, कुपवी कि बात करू तो आपकी सरकार 60 साल तक रहीं, कुपवी में सन् 70 में सड़क पहूंची थीं । लेकिन सन् 70 से लेकर 2012 तक किसी ने एक फुट भी मैटलिंग नहीं की थीं और आज में खुशी से कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला बैक्वर्ड ब्लोक पहला होगा जिसमें 15 की 15 पंचायतों कि सड़को में मैटलिंग है। इसमें 200 करोड़ सिर्फ टारिंग के लिए खर्च हुआ है। जिसमें नवार्ड द्वारा 70 करोड़ का लोन कुपवी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए दिया गया था, यह 70 करोड़ रुपये, 175 करोड़ के लोन के हैं जिसकी आप बात कर रहे थें। इसके कार्य अभी भी चले हुए हैं और सी0आर0एफ0 से जो हमारी मेन सड़क जुड़ी है माननीय श्री मंत्री महोदय जी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से मैने केंद्रीय सरकार के लिए भेजा था वो सिर्फ 10 कि0मी0 स्वीकृत हुए और हमारी जो सड़क है चौपाल में सैन्ज-फिडिज पुल अगर आप रिकार्ड निकालेगे तो देखेगें वहां काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं और ज्यादातर

12.03.2025/1815/A.P/Y.K/02

यूवा ही इसना शिकार बन रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री व मंत्री महोदय से बिनती है कि आप सी0आर0एफ0 में दौबार सैन्ज-फिटिज पुल को दोबार दिल्ली भेजें और मैं आदरणीय श्री जयराम जी के साथ दिल्ली जाकर उसको अप्रूव करवाउगा, इससे पैसा प्रदेश में आएगा और यह काम आपकी सरकार ही करवाएगीं। लेकिन चौपाल के दर्द के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें कोई राजनिति न की जाए, क्योंकि शिमला में जितने भी चुनाव क्षेत्र है सबकी डबल लाईन बन गई है और हमारी सिर्फ अभी 10 कि0मी0 है। हमारे यहां बिजली की बहुत दिक्कत थीं, श्री जयराम जी ने 66 के0वी0 चौपाल को दिया, जिससे अब शिमला में लाईट नहीं होती लेकिन चौपाल में लाईट होती है। एक अरब से उपर उसमे खर्च किया गया है, इससे बिजली से निजात हमें मिला है। अब हमारी मेन डिमाण्ड सिर्फ सड़क है, हमारी सड़के बननी चाहिए और मेरी आपसे विनती है कि इसको सी0आर0एफ0 में भेजे। हिमाचल प्रदेश में सी0आर0एफ0 सेंटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड़ में हिमाचल प्रदेश को 297 करोड़ रुपये इसी साल दिये गए है और माननीय अध्यक्ष यहां पर माननीय उपः मुख्यमंत्री महोदय जी है, मैं अपनी बजट बुक भी साथ लेकर आया हूं। उसमें 2024-25 में बोला था कि नेरवा और चौपाल की सीवरेज़ लाईन पूरी की जाएंगी (सीरियल नं0 127 और पेज नं0 47)। अब तक टेंडर नहीं लगा, अभी तक एक गौंती कही नहीं लगी और आपने अपनी बजट बुक में दिया है और बताया है कि चौपाल-नेरवा की सीवरेज़ लाईन को पूरा किया जाएंगा। दोनों की AA & ES का प्रावधान आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने अपनी सरकार के समय किया था। मेरी आपसे विनती है सर नेरवा खड्ड के किनारे बसा है। नेरवा में सिर्फ 1200 दुकानें हैं और 28 पंचायतों का सेंटर पवाइंट है, वहां सीवरेज़ बहुत जरूरी है और नेरवा पूरा बाज़ार खड्ड में है उसके आगे लगभग 22-23 लिफ्टे पानी की उठ रही हैं और उसकी स्थिति इतनी दायनीय है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे इस दूर-दराज क्षेत्र के लिए आप दया करें और चौपाल-नेरवा के लिए टेंडर प्रक्रिया को लगाए। मेरे चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी व श्री महेन्द्र सिंह जी ने एक अरब 51 करोड़ रुपये दिये थें।

ए0टी0 द्वारा जारी .....

12.03.20205/1820/AT/ बाई0के0 /.1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी.....

अब मैं पूरी फाइल विद वीडियो ,फोटोग्राफी बना रहा हूं उसमें कुछ काम सही नहीं हुए आपसे विनती है सर चौपाल बहुत दूर दराज का क्षेत्र है सारे गांव हमारे टॉप में उसमें हमारी 32 लिफ्ट है 32 लिफ्ट से पानी पहुंचता है पर अभी तक एक लिफ्ट से भी पानी नहीं पहुंचा सर मेरी आपसे विनती है उसमें बड़े ठेकेदारों ने काम लिए और वह ठेकेदार बाहर की है और उन्होंने काम साब्लाटिंग कर छोटी-छोटी ठेकेदारों को दीये है मेरी आपसे विनती है कि इसके लिए आप जहां 152 करोड़ का काम है और किसी एक आदमी को भी पानी ना मिले लिफ्ट तो कितना बड़ा अन्याय हो रहा है सर मेरी आपसे विनती है अगर अपने डिपार्टमेंट को कसा तो आप 10 लिफ्टों का उद्घाटन दो महीने के अंदर कर सकते हैं मेरी आपसे विनती है कि इसका संज्ञान जरूर लें आप ।

सभापती : बाइंड अप करें ।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : बिल्कुल सर बिल्कुल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में सभापति मोदिया स्वास्थ्य की दृष्टि से आदि श्री जयराम ठाकुर जी ने निर्वाह का अस्पताल बनाया 15 ,16 करोड़ से हॉस्पिटल बना पहले तो यह स्थिति थी कि जव हॉस्पिटल में जाते थे तो छतरी साथ ले जानी पड़ती थी पड़ती क्योंकि पानी ऊपर से नीचे तक पहुंचा था चोपाल , नेरवा ,कुपी तीनो अस्पताल के लिए जयराम ठाकुर जी ने पैसे दिए थे कूपी के अस्पताल का लेंटर बनकर तैयार हो रहा है निरवा का हैंडोवर कर दिया है चौपाल ,नेरवा ,कुपी से कोई भी महिला बीमार होती है अल्ट्रासाउंड के लिए हमको को 400 किलोमीटर आना जाना पड़ता है देश में कहां इतनी दूर अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है पर यह बात में हर बार विधानसभा में बोल रहा हूं पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ,हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी श्री जयराम ठाकुर जी ने अल्ट्रासाउंड भी दिया ऐकसरे की मशीनें भी थी पर अभी तक हम उसमे स्टाफ नहीं लगा सके ,मेरी आपसे विनती है कि आप हमको रेडियोलॉजिस्ट दें जरूर और इस माननीय सदन में जय राम ठाकुर जी को भी कई पीढियों तक चोपाला की जनता याद करेगी मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी चुनाव क्षेत्र में, हिंदुस्तान में 28 स्टेट और

12.03.20205/1820/AT/ बाई0के0 /.2

आठ केंद्र शासित प्रदेश है एक ही दिन में एक ही कैबिनेट में जय राम ठाकुर जी ने 91 पौस्टें एक साथ सैंकसन की थी ।

सभापती : बाइंड अप करें ।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : आप लोगों ने छोड़ दिया जिस कि वजह से आप यहां तक पहुंचे है हम इस जन्म में जरूर याद करेंगे और मेरी आपसे विनती है मैं हेल्थ की दृष्टि से बोलना चाहता हूं हमारे एक साथ इन्होंने 8 डॉक्टर चौपाल के 8 डॉक्टर नेरवा के 16 डॉक्टर की वैकेंसी एक साथ क्रिएट की थी और 20-20 स्टाफ की यह दोनों हॉस्पिटल की थी अब मेरे चुनाव क्षेत्र में 86 डॉक्टर की वैकेंसी है आज सिर्फ 9 बची है एक दिन 86 थी कारण यह था कि श्री जयराम ठाकुर जी ने उसमें क्लोज डाला था जो चौपाल में सेवा देगा उसको 2 साल के बाद एम0डी0 के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाएगा अब वह क्लोज भी खत्म कर दिया और चोपाल में अब डॉक्टर ही नहीं है मेरी आपसे विनती है की चौपाल में डॉक्टर का स्टाफ जरूर भेजें आप और जो मेरी पी0ए0सी0 बंद की है अब कूपवी जैसी क्षेत्र में जुकाम कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि लोगों के पास ना उतना धन है और न आने की सुविधा है वहां कपवी में दो पी0एस0सी0 बंद कर दी मेरा छैला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बंद कर दिया और एक किरण टेलर है जहां सड़क अभी जयराम ठाकुर जी ने दी थी नहीं तो हमें उत्तराखंड से जाना पड़ता था अब हम हिमाचल से जाते हैं वहां की पी0सी0सी0 बंद की जिनको हिमाचल के लिए भी बहुत दूर है और उत्तराखंड के लिए भी दूर है वो भी बंद हुई है कुछ बहुत जेनुएन इंस्टीट्यूशन बंद हुए उसको जरूर ओपन करे मेरी आपसे विनती है आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 92 हजार घर मिले सर एक भी किसी सदस्य ने धन्यवाद है मेरी आपसे विनती है इसमें क्वालिटी वर्क के लिए कोई पारद्रशीता बनाएं यह जो पैसा आ रहा हैइसमे कुछ नाकुछ काम हो मेरी आपसे विनती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी सस्वयं सहायता समूह के लिए

भी बहुत सा पैसा आ रहा है सर और यहां माननीय कृषि मंत्री है चलो सरकार ने महिलाओं को झूठ बोला, युवा को झूठ बोला सबको बोला आप लोगों ने तो गौ माता को भी झूठ बोला आपने कहा कि हम 700 से 1200 कर देंगे अब गौ माताएं वेट कर रही है

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी.....

12.03.2025/1825/md/as/1

श्री बलवीर सिंह शर्माः

अब प्रधानमंत्री योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 69000 घर मिले, एक भी किसा सदस्य ने धन्यावाद नहीं किया 92000-93000 घर मिले है पर नेरी आप सभी से विनती है कि जो इसमें क्वालिटि वर्क के लिए कोई पारदर्शिता बनाएं। यह जो पैसा आ रहा है वो जय राम ठाकुर जी ने 1 अरब 51 करोड़ रुपया दिया था। अब मैं पूरी फाइल बना रहा हूं सर जितनी बन रही है मैं विडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ ला रहा हूं। उसमें कुछ काम सही नहीं हुए। आपसे विनती है मेरी सर चौपाल बहुत दूर-दराज का क्षेत्र है। सारे गांव हतारे टॉप में हैं और उसमें हमारी 32 लिफटें है जिनसे पानी पहुंचता है पर अभी तक एक लिफट में भी पानी नहीं पहुंचा। उसमें बड़े ठेकेदारों ने काम लिए, बड़े ठेकेदार बाहर के आए और उन्होंने काम छोटे-छोटे ठेकेदारों को दिए मैंने हर बार बताया था। मेरी आपसे विनती है कि इसके लिए आप जहां 1 अरब 52 करोड़ का काम है और किसी एक आदमी को पानी ना मिले लिफट से इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरी आपसे विनती है अगर आपने डिपार्टमेंट को कसा सर 10 लिफटों का उद्गाटन आप 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। दो महीने के अंदर-अंदर दस लिफ्ट्स तैयार करके देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बारे में संज्ञान जरूर लें।

अभी माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी बाहर चले गए हैं। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य की दृष्टि से 15-16 करोड़ रुपये की राशि से नेरवा का अस्पताल बनाया। पहले वहां यह स्थिति थी कि अगर अस्पताल के अंदर जाना होता था तो वहां हाथ में छतरी या बरसात लेकर जाना पड़ता था क्योंकि बारिश के समय वहां पानी नीचे तक पहुंचता था। वहां चौपाल, नेरवा तथा कुपवी, उन

तीनों अस्पतालों की यही स्थिति थी और माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने मुख्य मंत्री कार्यकाल में उन तीनों अस्पतालों के लिए पैसा दिया था। कुपवी होस्पिटल के लैंटर पड़ गए हैं और वह तैयार हो रहा है। नेरवा का हैण्डओवर कर दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चौपाल, नेरवा और कुपवी में यदि कोई महिला बीमार होती है तो अल्ट्रासाउंड के लिए हमें 400 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं इतनी दूर जाना पड़ता होगा। मैं यह बात हर सत्र के

12.03.2025/1825/md/as/2

दौरान कहता हूं। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था लेकिन आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने हमें अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे की मशीनें दीं परंतु हम अभी तक वहां स्टाफ नहीं लगा पाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें रेडियोलॉजिस्ट जरूर दें। मैं यहां यह जरूर कहना चाहता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी को चौपाल की जनता कई पीढ़ियों तक याद करेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि हिन्दुस्तान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। चौपाल में हैल्थ की दृष्टि से श्री जय राम ठाकुर जी ने एक ही दिन और एक ही कैबिनेट में 91 पोस्ट्स सैंक्शन की थीं। ...(व्यवधान) मुझे पहले हैल्थ की बात करने दो। लेकिन दुःख इस बात का है कि आप लोगों ने छोड़ दिया जिनकी वजह से आप सारे पहुंचे। मैं तो इस जन्म में जरूर याद रखूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इन्होंने एक साथ 8 डॉक्टर्ज चौपाल, 8 डॉक्टर्ज नेरवा यानी 16 डॉक्टर्ज के अतिरिक्त वहां के लिए 20-20 पैरा मेडिकल स्टाफ की रिक्तियां एक साथ क्रिएट की थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में वर्तमान में डॉक्टर्ज की बहुत सारी रिक्तियां हैं जबकि एक दिन ऐसा भी था जब वहां सभी 86 डॉक्टर्ज उपलब्ध थे। लेकिन आज वहां पर 9 डॉक्टर्ज बचे हैं। उसके पीछे यह कारण था कि आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने उसमें एक क्लॉज डाली थी कि जो चौपाल में सेवाएं देगा उसको दो वर्षों के बाद एम0डी0 के लिए सुविधा मिलेगी। मगर अब वह क्लॉज खत्म कर दी गई है और चौपाल में अब डॉक्टर्ज ही नहीं है। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि आप वहां पर डॉक्टर्ज जरूर भेजें। वर्तमान सरकार ने कई पी0एच0सीज0 बंद कर दी हैं। हमारे कुपवी जैसे क्षेत्र में दो पी0एच0सीज0 बंद कर दी। वहां छैला में कम्युनिटी हैल्थ सेंटर बंद

कर दिया। वहां पर किरण--- टेलर में आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने सड़क दी थी वरना हमें उत्तराखण्ड से जाना पड़ता था। अब हम हिमाचल से जाते हैं मगर वहां की पी0एच0सी0 भी बंद की गई जिनको हिमाचल और उत्तराखण्ड दोनों ही दूर पड रहा है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

12.03.2025/1830/केएस/एजी/1

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें। आधा घंटा हो गया है। आपके बाकी सदस्य कब बोलेंगे? कृपया समाप्त करिए।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इस माननीय सदन में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण पढ़ा है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि आपने उनसे जो झूठ बुलवाया है, उसका हम सभी को भी दुख है और उनको भी दुख है कि उन्हें झूठ बोलना पड़ा है। इसलिए मैं समर्थन नहीं कर सकता। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

12.03.2025/1830/केएस/एजी/2

सभापति : अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी भाग लेंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अभी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं तो कृपया संक्षिप्त में बोलें।

श्री मलेन्द्र राजन : सभापति महोदय, दिनांक 10 मार्च, 2025 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जिसको माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया द्वारा प्रस्तुत तथा श्री विनोद सुल्तानपुरी, सदस्य द्वारा अनुसमर्थित किया गया, पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मुझसे पूर्व पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है लेकिन यह जो डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय से पढ़ाया गया है, लगता है कि हमारे विपक्ष के साथियों ने

इसको पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा है। अगर इसको इन्होंने पूर्ण रूप से पढ़ा होता तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सी ऐसी जनकल्याणकारी स्कीमें हैं जिनका सीधा लाभ आज आम आदमी को, कमज़ोर आदमी को हो रहा है। यहां पर गारंटियों की बात की जा रही है। निश्चित रूप से गारंटियों पर काम हो रहा है। गारंटियां पूरी हो रही हैं और उन पर आगे काम चल रहा है। जैसे कि मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार को पांच वर्ष का मेन्डेट मिला है। ये गारंटियां भी पांच वर्ष में सरकार द्वारा पूरी की जानी हैं। उसके बाद हमारी सरकार का जो लेखा-जोखा होगा उसको ले कर हम हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे। मैं समझता हूं कि हमारे जो विपक्ष के साथी बोल रहे हैं कि प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो ये भी तो पांच वर्ष सत्ता में रहे हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य और पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे सुख राम चौधरी जी बोल रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं हैं, बिजली के पोल नहीं हैं तो पांच वर्ष ये भी तो मंत्री रहे, इन्होंने क्या किया? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जो आम परिवार से निकलकर आज प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं, निश्चित रूप से यह बात भी हमारे विपक्ष के नेताओं को हजम नहीं हो रही है कि कैसे एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज प्रदेश के मुख्य मंत्री के पद पर बैठा है और प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहा है? कैसे आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज एक आम व्यक्ति की बात कर रहा है, आम आदमी को डायरैक्ट फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है? कैसे एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज महिलाओं के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं बना रहा है

12.03.2025/1830/केएस/एजी/2

और उनका सीधा लाभ उन बच्चों तक पहुंचा रहा है, यह बात इनको हजम नहीं हो रही है। निश्चित रूप से जब हम पांच वर्ष के बाद दोबारा चुनाव के लिए जनता के बीच जाएंगे तो इस वक्त जो हम लोग सत्ता में हैं, जनता हमारे कार्यों के लेखे-जोखे का आकलन भी करेगी और विपक्ष के साथियों का आकलन भी करेगी। अगर मैं इस प्रस्ताव की ही बात करुं तो निश्चित रूप से हमारे विपक्ष के साथी जो कुछ यहां पर बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल

रहे हैं। इनको प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हम लोग चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य, कृषि या लोक निर्माण व जलशक्ति विभाग की बात करें,

12.03.2025/1835/AV/एएस/1

श्री मलेन्द्र राजन------ जारी

या दूसरे विभागों की बात करें। प्रदेश सरकार आज माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है। सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा पर कोई भी प्रदेशवासी किसी भी प्रकार की अंगुली नहीं उठा रहा है। प्रदेश के आम जन-मानस को पता है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री, पूरा मंत्रिमण्डल व विधायकों की प्रदेशवासियों के प्रति मंशा बिल्कुल क्लीयर है। आज प्रदेश के अंदर जो भी योजनाएं बन रही हैं उनका लेखा-जोखा यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आज प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे ऊर्जावान शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। ये कदम पूर्व सरकार द्वारा भी उठाए जा सकते थे जिनका फायदा हमारे सरकारी स्कूल्ज में पढ़ रहे बच्चों को मिल सकता था। लेकिन आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो क्रान्तिकारी कदम उठाए जा रहे हैं उससे आने वाले समय में हमारे गवर्नमैंट स्कूल्ज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। ऐसा कहा भी गया है कि जब-जब किसी सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया जाता है तो निश्चित रूप से उस संदर्भ में पक्ष और विपक्ष द्वारा बातें उठाई जाती हैं। लेकिन यदि हम उसको अल्टीमेट रूप में देखें तो आने वाले समय में उसका फायदा निश्चित रूप से हमारी सरकारी पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को होगा। हमारी सरकार द्वारा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात की गई है। ये स्कूल प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अंदर बनने जा रहे हैं और इनका फायदा हमारे प्रदेशवासियों के बच्चों को मिलेगा तथा हमारे विपक्ष के साथियों को इस बात को समझना चाहिए। आज अगर हमारी सरकारी पाठशालाओं में अंग्रेजी मीडियम की क्लासिज शुरू की गई हैं तो उसका फायदा आने वाले समय में हमारे प्रदेश के बच्चों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ऑफ एक्सीलैंस की

बात की गई है। मैं समझता हूं कि उसका भी आने वाले समय में काफी लाभ मिलेगा। यहां पर बंद किए गए शिक्षण संस्थानों की बात की जाती है। मेरे हिसाब से यह ठीक बात है क्योंकि प्रदेश में बहुत सारे स्कूल्ज ऐसे हैं जहां पर टीचर्ज हैं मगर बच्चे नहीं हैं और कई स्कूल्ज ऐसे

12.03.2025/1835/AV/एएस/2

हैं जहां बच्चे तो हैं मगर टीचर्ज नहीं हैं क्योंकि टीचर्ज भी अपनी सूटेबिलिटी देखते हैं। वे भी किसी-न-किसी को पकड़कर अपनी एडजस्टमैंट्स इधर-उधर करवा लेते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में रेशनलाइजेशन का प्रोसैस शुरू किया है मैं समझता हूं कि इसके शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे।

इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक-एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। इस संदर्भ में आज सुबह मैंने भी एक प्रश्न लगाया था। मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र के अंदर सिविल अस्पताल इंदौरा और सिविल अस्पताल गंगथ में डॉक्टर्ज के रिक्त पड़े पदों के संदर्भ में प्रश्न किया था। वहां पर अभी सुविधाओं की कमी हो सकती है लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनको दूर किया जाएगा क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की ओर आगे बढ़ रही है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री प्रदेश की आम जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने हेतु कार्य कर रहे हैं और यह एक प्रशंसनीय कदम है। मैं समझता हूं कि यहां पर चुने हुए सभी माननीय सदस्यों को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए और इसके लिए पहल करनी चाहिए कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में ये आदर्श संस्थान शीघ्रातिशीघ्र बनें। पिछले दिनों धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान भी मैंने माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने स्वयं जाकर सिविल अस्पताल इंदौरा व सिविल अस्पताल गंगथ का जायजा लिया था। उन्होंने सिविल अस्पताल गंगथ में दो डॉक्टर्ज भी नियुक्त किए थे परंतु उन्होंने वहां पर ज्वाइन नहीं किया। मैंने यहां पर जैसे पहले कहा कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्ज अपनी सूटेबिलिटी भी देखते हैं और यह बात

किसी से छिपी नहीं है कि वे इधर-उधर किसी-न-किसी को पकड़कर अपनी एडजस्टमैंट करवा लेते हैं।

टी सी द्वारा जारी

12.03.2028/1840/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री मलेन्द्र राजन जारी

जिसके इसके कारण कई बार जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, उसमें भी हिमाचल को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की बात कही है। इस दिशा में कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना प्रदेश सरकार लेकर आई है जोकि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में संचालित हो रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

मैं जिस इंदौर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। वहां पर गेहूं और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। हमारे माननीय कृषि मंत्री, प्रो. चंद्र कुमार जी भी यहां उपस्थित हैं, वे इस क्षेत्र को भली-भांति जानते हैं। कृषि क्षेत्र में भी पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में सरकार द्वारा कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं जिनका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है।

पिछले दिनों प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उससे हमारा विधान सभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। किसानों और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान हुआ। विशेष रूप से मंड क्षेत्र की लगभग 14 पंचायतों को काफी क्षति पहुंची। मैं मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वयं वहां जाकर नुकसान का आकलन किया। उप-मुख्य मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और कृषि मंत्री, प्रो. चंद्र कुमार जी ने भी

वहां का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को समाधान निकालने के निर्देश दिए।

हमारे क्षेत्र में लगभग 500-550 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती होती है। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसे अन्य फसलों पर किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वैसे ही गन्ना उत्पादकों को भी प्रदेश सरकार की ओर से इंसेंटिव दिया जाए। हिमाचल में गन्ने की कोई मिल नहीं है, जिससे वजह से किसान अपना गन्ना पंजाब भेजते हैं। वहां के किसानों को हिमाचल के किसानों की तुलना में 65 रुपये प्रति क्विंटल

12.03.2028/1840/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

अधिक मूल्य मिलता है। इंदौर और फतेहपुर विधान सभा क्षेत्रों में गन्ने की खेती बढ़ रही है। इसके अलावा, मैं दूध के समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रदेश सरकार की सराहना करता हूं। हमारे क्षेत्र के कई लोग दुग्ध उत्पादन पर निर्भर हैं और बड़ी मात्रा में दूध एकत्र कर डगवार भेजा जाता है। सरकार के इस निर्णय की सभी किसान और पशुपालक प्रशंसा कर रहे हैं। गेहूं और मक्की की प्राकृतिक खेती को भी सरकार ने बढ़ावा दिया है और समर्थन मूल्य बढ़ाकर 30-40 रुपये किया है जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। कुछ सदस्य पूछ रहे थे कि प्राकृतिक खेती कहां हो रही है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आकर देखें कि किसान किस तरह मेहनत कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में अवैध नशे और खनन का कारोबार बहुत अधिक है। पूर्व मुख्य मंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी इस स्थिति से परिचित हैं। वे अभी यहां नहीं बैठे हैं। हालात इतने खराब थे कि आए दिन चिट्टे के कारण बॉर्डर इलाकों जैसे डमटाल, बदरुआ और छन्नी में युवाओं की लाशें मिलती थीं।

एन0 एस0 द्वारा ....जारी

12-03-2025/1845/ns-dc/1

श्री मलेन्द्र राजन------ जारी

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि इन्होंने प्रदेश में सरकार बनते ही इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया। मैंने भी उनके समक्ष अपनी बात रखी और सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं मुख्य मंत्री जी के समक्ष जाहिर की हैं। मुख्य मंत्री जी ने उस संदर्भ में विभाग को कड़े निर्देश दिए। आज वही पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जो पूर्व की सरकार के समय में अधिकारी थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर रोज किसी न किसी युवक की लाश मिलती थी लेकिन आज उसमें कमी आई है। अब नशे का सेवने करने से 6 महीने में एक लाश देखने को मिलती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ काफी अंकुश लगा है। मैं यह नहीं कहता कि चिट्टे का पूरा खात्मा हो गया है। अगर उस वक्त पूर्व भाजपा सरकार द्वारा चिट्टे पर लगाम लगाई जाती, सख्त कानून बनाए जाते तो आज चिट्टा बॉर्डर एरिया से निकल कर पूरे प्रदेश में नहीं फैला होता। अभी यहां पर माननीय सदस्य बोल रहे थे कि शिमला में गांव के अंदर भी चिट्टा आ गया है। निश्चित रूप से अगर उस समय बॉर्डर्ज को तरीके से सील किया होता तो यह पूरे प्रदेश में नहीं फैलता।

सभापति महोदय, यहां पर श्री रणवीर सिंह (निक्का) जी ने अवैध खनन के बारे में कहा है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी समस्या हमारे विधान सभा क्षेत्रों में थी। चिट्टा व अवैध खनन पर रोक बहुत जरूरी है। आज प्रदेश सरकार इस पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका आकलन किया जाए कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में अवैध खनन पर कितनी कार्रवाई की गई? मैं समझता हूं कि इन दो सालों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्रवाई हो रही है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए। इस सदन में वर्तमान सरकार पर बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं और यह दस्तावेज झूठ का पुलिन्दा है। मैं कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ने तो यहां पर भगवान का नाम लेकर झूठ बोला है। इन्होंने पिछले बजट सत्र में खड़े होकर कहा था कि अब भगवान भी अगर नीचे आ जाए तो इस सरकार को नहीं बचा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आज सरकार कार्य कर रही है, मजबूती से कार्य कर रही

12-03-2025/1845/ns-dc/2

है और जो इनके मन में यह वहम है कि वर्ष 2027 में भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो इनका यह वहम ऐसे ही ईश्वर बनाए रखे तथा ये आने वाले समय में इससे भी कम संख्या में यहां पहुंचे। इनमें (विपक्ष) बहुत से हमारे मित्र भी हैं और वे यहां आ जाए और इनकी मंशा पूरी हो। ये इन्हीं कुर्सियों को दोबारा सुशोभित करें। मैं मुख्य मंत्री जी की मंशा पर एक शेर कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगाः-

जो सोच में हो ईमानदारी
जो नियत में हो उजाला
वह रहबर जब चले आगे
तो बढ़े प्रदेश निराला।

सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

12-03-2025/1845/ns-dc/3

सभापति : अब इस चर्चा में श्री प्रकाश राणा जी भाग लेंगे।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले काफी सदस्यों ने अपनी बात रखी है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो हिमाचल का समय चल रहा है तो आज हिमाचल इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहां पर माननीय सदस्यों ने विकास की बात रखी है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि विकास होगा तो कहां से होगा? क्या आप कर्ज लेकर विकास करना चाहते हैं?

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

12.03.2025/1850/RKS/डीसी-1

श्री प्रकाश राणा... जारी

जो आपका वर्ष 2024-25 का बजट इन ब्रीफ प्रस्तुत किया गया है कृपया इसे थोड़ा विस्तार से देखें। हमारे पास इतनी आय भी नहीं है कि हम केवल चार मुख्य कार्यों में भी पैसा खर्च कर सकें। आपने पृष्ठ संख्याः 6 में उल्लेख किया है कि हमारे बजट का 29.51 प्रतिशत हिस्सा वेतन पर, 17.4 प्रतिशत पेंशन पर और 10.70 प्रतिशत हिस्सा ऋण की अदायगी पर खर्च हो रहा है। इसके अतिरिक्त लोन पुनर्भुगतान में 16.70 प्रतिशत राशि जा रही है। ये आंकड़े वर्ष 2024-25 के बजट के हैं लेकिन अगले बजट में हालात और भी खराब होने की संभावना है। यदि हम इन आंकड़ों का कुल योग करें तो हमारे बजट का लगभग 80 प्रतिशत भाग केवल इन चार कार्यों पर ही खर्च हो रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो विकास कार्यों के लिए धन कहां से आएगा? हम आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? इस समय हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने आय के स्रोतों को कैसे बढ़ाएं। इसमें टैक्स राजस्व लगभग 18,000 करोड़ रुपये दिखाया गया है। यदि हम केंद्रीय करों के हिस्से को जोड़कर देखें तो यह 40,446 करोड़ रुपये बनता है। इसमें विकास कार्यों की बात कहीं नहीं की गई है। हम कुछ ग्रांट्स भी प्रदान करते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि लेकिन इस बजट में इन कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें जो राजस्व दर्शाया गया है वह 40,446 करोड़ रुपये है। सैलरी, पेंशन, ऋण भुगतान और ब्याज भुगतान में लगभग 46,755 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। जितना हमें रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्च इन चार मदों में हो रहा है। अब आप जो विकास की बात कर रहे हैं वह विकास कुछ केंद्र सरकार की सहायता और कुछ उधार के पैसों से हुआ है। यह प्रदेश की वास्तविक स्थिति है। हमें इसे वित्तीय दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। यहां जो वित्तीय अधिकारी बैठे हैं उनकी भी यह बड़ी गलती है कि वे सही तरीके से इसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वे इसे ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं तो हमें एक समिति गठित करनी चाहिए जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों दलों के सदस्य हों। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर सोचना होगा कि हम हिमाचल प्रदेश को इस कर्ज के बोझ से कैसे निकालें। यह आपस में झगड़ा करने का समय नहीं है। यदि हम इस स्थिति को

संभालने में विफल रहते हैं तो यह संभव है कि कभी भी इस प्रदेश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो जाए और हम सब इस सदन से बाहर हो जाएं। आप इस स्थिति में क्यों उलझे हुए हैं? हम यह चाहते हैं कि हम अपनी आय के स्त्रोतों को

12.03.2025/1850/RKS/डीसी-2

कैसे बढ़ाएं। मैं देख रहा हूं कि हर कोई अपने-अपने हितों की बात कर रहा है लेकिन इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि धन कहां से आएगा? प्रदेश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज यह प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज का बोझ ढो रहा है। अगले बजट में हमें ब्याज और ऋण पुनर्भुगतान के लिए हर महीने 17-18 सौ करोड़ रुपये जमा करने होंगे। आप यह धन कहां से जुटाएंगे? क्या आपने इस विषय पर कुछ विचार किया है? यदि यह भुगतान हमें नहीं करना पड़ता तो हर निर्वाचन क्षेत्र को 25-25 करोड़ रुपये मिलते और इस राशि से हम बहुत सारे विकास करवा सकते थे। आपने आपस में झगड़ कर प्रदेश की क्या हालत कर दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है अगर हम मिलकर कुछ कदम उठाएं तो हालात को सुधारा जा सकता है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

12.03.2025/1855/बी.एस./एच.के./-1

श्री प्रकाश राणा जारी...

मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है। हम मिलजुल करके इस प्रदेश के लिए कुछ करें। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि इस डूबते हुए हिमाचल को जो कर्ज के दलदल में फंस चुका है इसे बचा लीजिए। यह मत समझो कि हम सत्ता पक्ष में या विपक्ष में हैं। मैं न सत्ता पक्ष को कह रहा हूं और न विपक्ष को कह रहा हूं परंतु मैं सबकी बात कर रहा हूं। यह कर्ज कोई अभी का नहीं इसकी शुरूआत वर्ष 1993-94 से हुई है। अब जो आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार खजाना खाली कर गई, आप स्वयं सोचो कि प्रदेश का खजाना कब भरा

था? हम वर्ष 1993 से कर्ज ले रहे हैं तो यह खजाना कब भरा था? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? यह सबसे बड़ा मंदिर है। आप मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं तो अच्छी राय दे रहा हूं। आप इसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कोई भी बात गलत नहीं बोल रहा हूं। जब मैं इतिहास देखता हूं, मैं भी एक बिजनेस मैन हूं और फाइनेंस को हम अच्छी तरह से समझते हैं। हमने बड़ी-बड़ी कंपनियां चलाई हैं और हम बजट भी बनाते हैं। बजट क्या है? बजट एक घोषणा पत्र की तरह है, आपको अभिभाषण में दिखाना चाहिए था कि इतना पैसा हमारे पास आया, इतना हमने खर्च किया और इतने पैसे का हमने कर्ज लिया। यह कर्ज सबके ऊपर है, इसे हम, आप और हमारे बच्चे सभी भरेंगे। आप हिमाचल प्रदेश की जनरेशन को क्यों कर्ज में धकेलते जा रहे हैं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि हम तीन-चार चीजों की तरफ ध्यान दें तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। जिस तरह से मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश के जो इंकम सोर्सिज हैं उससे हम केवल चार चीजें नहीं चला पा रहे हैं। जो हमें देना ही है, मैं उस कमिटिड एक्पेंडिचर की बात कर रहा हूं, इसमें कल को इमरजेंसी नहीं लगेगी तो और क्या होगा? मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि अगर हम बड़ी-बड़ी बातें करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमें चार-पांच चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक कर्ज, दूसरा जो आज नशा फैला है, तीसरा भ्रष्टाचार और चौथा बेरोजगारी। यह ठीक है, नाबार्ड से हमें पैसा मिल रहा है। हर वर्ष 20-25 करोड़ मिल ही रहा है। उसे आज नहीं तो आगे खर्च करेंगे। लेकिन किसी के चुनाव क्षेत्र का पैसा कोई ले करके नहीं जाता है। हमारे पास यह समय आ गया है, हमें पता है कि हमारी विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न है कोई 20 मिलोमीटर पर ही खत्म हैं, कुछ 10 किलोमीटर पर खत्म है और किसी का 150-200 किलोमीटर पर खत्म हो रहा है।

12.03.2025/1855/बी.एस./एच.के./-2

आदरणीय हंस राज जी का चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। यदि हम इस पैसे का गलत इस्तेमाल न करें और एक प्रपोजल यहां पर लाते हैं, जैसे नाबार्ड का पैसा है जिन चुनाव क्षेत्रों में विकास कार्य हो चुके हैं और 10-15 किलामीटर तक ही वे क्षेत्र हैं, उन चुनाव क्षेत्रों में फैक्ट्री लगाना शुरू कीजिए। हम यह तो नहीं कह रहे हैं उस चुनाव क्षेत्र का पैसा कहीं

और ले जाओ। अब हमारे चुनाव क्षेत्र बड़े हैं। परंतु कुछ तो इस ओर काम करिए, ताकि आगे को युवाओं को रोजगार मिल सके।

जहां तक नशे की बात है यह नशा तो इस तरह से फैल गया है कि इसने पूरे प्रदेश को चपेट पर ले लिया है। मैं कहता हूं कि यदि आप नशा मुक्त प्रदेश की घोषणा कर देते हैं तो सही होगा। आज प्रदेश को नशा मुक्त करने का समय आ गया है। आप नई जनरेशन को नशे से बचा लो। मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि हम प्रदेश को नशा मुक्त करने जा रहे हैं। हम भी कहते हैं कि नशा मुक्त हिमाचल बनाइए। यदि बिहार नशा मुक्त हो सकता है तो क्या हिमाचल प्रदेश नहीं बन सकता? मैं कहना चाहता हूं कि आज नशे में ऐसे पैर फंस चुके हैं कि 90 प्रतिशत घरों में लाड़ाई झगड़े चले हुए हैं। मैं कहता हूं कि यदि प्रदेश नशा मुक्त होता है तो पुलिस का काम आधा हो जाएगा, क्राइम आधे हो जाएंगे और जेलें भी अधी हो जाएंगी। यह सब नशे की वजह से है।

हमारे शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, यदि किसी भी प्रदेश, देश और क्षेत्र को ऊपर उठाना है तो उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है लेकिन शिक्षा का स्तर नीचे गया तो वह प्रदेश अपने आप ही नीचे चला जाता है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

12.03.2025/1900/DT/HK-1

सभापति : अगर इस माननीय सदन की अनुमति हो तो इस सदन सदन की बैठक 7.30 बजे तक बढ़ा दी जाए?

(माननीय सदन की बैठक 7.30 बजे तक बढ़ाई गई।)

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि यह ठीक है कि अपने क्षेत्र की बात रखनी चाहिए, एक तो इस माननीय सदन में बोलने के लिए बहुत कम समय

मिलता है तो हमें संक्षिप्त में अपनी बात कहनी पड़ती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस प्रेदश में शिक्षा का सिस्टम बढ़ाना होगा। आप कहते हैं कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में हम नम्बर-वन हो गये। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सदन में बैठें है, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 46 प्राथमिक स्कूल हैं और अगर मैं अध्यापकों की बात करूं तो अध्यापकों के 53 पद रिक्त पड़े हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 33 मिडल स्कूल्ज हैं और इन स्कूल्ज में अध्यापकों के 63 पद रिक्त पड़े हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं और इनमें अध्यापकों के 65 पद रिक्त हैं और 11 ऐसे स्कूल्ज हैं जिनमें प्रधानाचार्य ही नहीं है। चौंतड़ा में जो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है और उसमें 600 के लगभग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में दो साल राजनीति विज्ञान के अध्यापक का पद लगभग 2 वर्ष से रिक्त है जबकि इस विषय को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 200 है। मैंने इस विषय में बोला भी था कि जोगिन्द्र नगर से जिस अध्यापक को इस स्कूल में प्रतिनियुक्त किया गया है उससे इस स्कूल में काम नहीं चल रहा। मैं आज फिर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस पद को नियमित रूप से भरा जाए। मैं प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अटल आदर्श विद्यालय के लिए इन्होंने जगह ली और लोगों ने भी जगह दान में दे दी। 40 बीघा जमीन ली गई थी जिसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था। अब आपकी सरकार बन गई और जब सरकार नई बनती है तो पुराने कार्य समाप्त हो जाते हैं और नये शुरू हो जाते हैं। ...(व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है कि जो लोगों ने लैंड दान दी है आप उसे वापिस कर दें। जिन लोगों ने लैंड दी है वे मेरे घर में बैठ रहे हैं। मैं आपको कई बार बोल चुका कि आप राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ही खोल दें लेकिन आप वह भी नहीं कर रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप कुछ हल निकालिए।

12.03.2025/1900/DT/HK-2

मेरे क्षेत्र में सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि वहां 2 सालों में 10 किलोमीटर टारिंग भी नहीं हुई है। आप कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते लेकिन यह तो भेदभाव ही है। जो नोहली का पुल मंडी को जोड़ता है वह डिजास्टर में बह गया था। श्री अनिल शर्मा जी ने भी

इस पुल के बारे में बड़ी बार बात की। उस पुल के पुनर्निमाण के लिए फाउंडेशन स्टोन रखे हुए डेढ़ साल हो गए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर को कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर बनाया जिसके लिए मैं पूर्व मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। पहले उस सेंटर में दो डॉक्टर्ज तैनात थे क्योंकि यह चौंतड़ा शहर पोपुलेटिड एरिया है और कम्यूनिटी सेंटर बनने पर वहां एक ही डॉक्टर सेवा दे रहा है। सिविल होस्पिटल, लडभड़ोल में 6 डॉक्टर्ज हुआ करते थे। इस अस्पताल को भी सिविल हॉस्पिटल बनाने में श्री जय राम ठाकुर जी का ही योगदान है और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। वहां आज एक भी डॉक्टर तैनात नहीं है। मैंन इस विषय में आपसे बात की और आपने अभी एक डॉक्टर वहां भेजा है जिसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं।

श्री एन.जी.द्वारा जारी

12.03.2025/1905/वाई.के.-एन.जी./1

श्री प्रकाश राणा.....जारी

जिसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वह सिविल अस्पताल है और वहां पर कम-से-कम एक डॉक्टर तो 24 घण्टे उपलब्ध होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि वहां पर एक डॉक्टर को दिन के लिए और एक डॉक्टर को रात के लिए नियुक्त कर दीजिए। इसी प्रकार सिविल अस्पताल, जोगिन्द्रनगर एक बड़ा अस्पताल है और वहां पर डॉक्टर्स तो हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। इसके अलावा वहां पर दवाइयां ही नहीं हैं और मशीनें इत्यादि तो कुछ भी नहीं है। एक छोटे से मामले के लिए भी मेडिकल कॉलेज टांडा रैफर करना पड़ता है।

यहां पर माननीय उप-मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की अनेक पंचायतों में तीसरे दिन पानी मिल रहा है। अब गर्मियों का मौसम आने वाला है और मेरा आग्रह है कि इस समस्या की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। यदि मैं एच0आर0टी0सी0 की बात करूं तो मेरे क्षेत्र के अनेक बस रूट्स बंद हो चुके हैं। खुड्डी-

मण्डी बस रूट जोकि वाया जोगिन्द्रनगर था, वह लगभग एक साल से बंद पड़ा हुआ है। जोगिन्द्रनगर से चौकी होकर दो रूट्स चलते थे, वे दोनों रूट्स भी बंद हैं। बैजनाथ से लड़भड़ोल बस रूट भी काफी समय से बंद पड़ा है। मेरा आग्रह है कि नए रूट तो बेशक न दो लेकिन जो रूट चल रहे थे उन्हें ही दोबारा शुरू कर दीजिए। ...(घण्टी)...

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ वाइंडअप कीजिए।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जोगिन्द्रनगर में जो बस स्टैंड बनाया गया था उसमें अभी तक वर्कशॉप व डीज़ल पम्प का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा आग्रह है कि जोगिन्द्रनगर बस डीपो में वर्कशॉप व डीजल पम्प का प्रावधान शीघ्र किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें केन्द्र सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है।

12.03.2025/1905/वाई.के.-एन.जी./2

ऐसा नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार ने सभी प्रदेशों के लिए एक समान नियम बनाए हैं। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि कौन सोच सकता था कि हिमाचल प्रदेश में इतने ज्यादा फोर-लेन्ज़ का निर्माण होगा। जब से आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं तब से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में केन्द्र में सरकार बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेट कैटेगरी का दर्जा दिया। ...(व्यवधान) गुरू जी, आपने सही से नहीं पढ़ा है। (माननीय कृषि मंत्री की ओर देखते हुए कहा) यह दर्जा पहले दिया गया था लेकिन वर्ष 2007 में वापिस ले लिया गया था। मैं यहां पर कोई झूठ नहीं बोलूंगा। इस स्पेशल स्टेट कैटेगरी से हमें यह लाभ हो रहा है कि केन्द्र सरकार की जो भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में लागू हो रही हैं उनमें हमारे प्रदेश को केवल 10 प्रतिशत पैसा देना पड़ रहा है और 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार दे रही है। यदि हमारे प्रदेश में 100 करोड़ रुपये की योजना आती है तो उसमें हिमाचल प्रदेश को केवल 10 करोड़ रुपये ही देने हैं और शेष 90 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को ही देने हैं। मैं विदेशों में रहा हूं और वहां पर वर्ष 2014 से पहले भारतीयों को कितना मान-सम्मान मिलता था, उसे मैंने स्वयं महसूस किया है। आज भारतवर्ष का दर्जा बहुत ऊपर ऊठा है। आज हम जब

विदेश में जाते हैं तो हमें रिस्पैक्ट मिलती है। मैं यहां पर एक-दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

Chairman : Please wind-up.

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश कर्ज के दलदल में फंस चुका है और हम सभी को मिलजुल कर इस दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए।

Chairman : Please wind-up.

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस अभिभाषण में समर्थन करने की कोई बात ही नहीं है। मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने जिस प्रकार से बजट पेश किया था और माननीय राज्यपाल ने जो पढ़ा है उसमें कुछ खास नहीं है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

12.03.2025/1905/वाई.के.-एन.जी./3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री भुवनेश्वर गौड़ भाग लेंगे।

श्री भुवनेश्वर गौड़ : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत हुए धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले दो वर्षों से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इन्हीं दो वर्षों में प्रदेश में दो बार आपदा भी आई है। भारी आपदा से जूझते हुए प्रदेश में विकासात्मक काम और जो योजनाएं under privilege लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, वे बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही हैं। चाहे वह सुखाश्रय योजना हो और चाहे महिलाओं के लिए स्कीम्ज़ हों। मैं समझता हूं कि विपरीत.....

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

12.03.2025/1910/YK-PB/-1

श्री भुवनेश्वर गौड़ जारी....

मैं समझता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। जैसे माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी ने जो बात कही कि आज के समय में इस बात की जरूरत है कि पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर प्रदेश के हितों के लिए एक साथ होकर चलना चाहिए। उसमें चाहे फिर वह दिल्ली जाने की बात हो या केन्द्र सरकार से सहायता लेने की बात हो हमें मिलकर चलना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी ने सही बात कही है और नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इसका संज्ञान लें और जल्दी-से-जल्दी एक कमेटी बनाकर इस संदर्भ में कार्य करें। सभापति महोदय, जितनी भी स्कीम के बारे में मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बात की चाहे वह लोक निर्माण विभाग की बात हो या अन्य स्कीम्ज की बात हो, मैं मुख्यतः अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि बीते दो वर्षों में मनाली विधान सभा क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग की और से मनाली में सीवरेज और ड्रिंकिंग वॉटर के लिए 389 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और आज के समय में इस स्कीम का कार्य पूरे जोर शोरों से चला हुआ है, जिसके लिए 130 करोड़ रुपए भी अभी तक सैंक्शन हो गए हैं और 100 करोड़ रुपए जो हमारी पोर्टेबल वॉटर और ड्रिंकिंग वॉटर स्कीम है उसका कार्य भी चल रहा है। हम बहुत से समय में सुनते आ रहे हैं कि ब्यास नदी का तटीयकरण होने जा रहा है। कभी यह स्कीम 1200 करोड़ रुपए की थी तो कभी यह स्कीम 1600 करोड़ रुपए की थी । परंतु इस बार भी यह स्कीम नाबार्ड को भेजी गई थी लेकिन यह स्कीम नाबार्ड से रिजेक्ट होकर वापिस आ गई। हम हिमाचल प्रदेश सरकार के धन्यावादी हैं जिसने स्टेट मिटिगेशन हैड में हमें तकरीबन 67 करोड़ रुपए फ्लड प्रोटेक्शन के लिए दिए। जिसका कार्य आज के समय में पूरे जोर-शोर से चल रहा है और आज तक जो हमने देखा है हमारे क्षेत्र में फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य कभी नहीं हुआ था। मनाली एक पर्यटन और होर्टीक्लचर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके बावजूद, हम हिमाचल प्रदेश सरकार के आभारी हैं कि राज्य मिशन के तहत हमें

12.03.2025/1910/YK-PB/-2

लगभग 77 करोड़ रुपये फ्लड प्रोटेक्शन के लिए दिए गए, जिन पर कार्य पूरे जोर-शोर से जारी है। आज तक हमारे क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हुआ था लेकिन अब इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। मनाली पर्यटन और बागवानी से जुड़ा प्रमुख क्षेत्र है और इसी कड़ी में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सेब के एम.एस.पी.मूल्य को 2 रुपये से बढ़ाकर बागवानों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। आज के समय में किसान नई-नई वरायटी के पौधे लगा रहे हैं। आड़ू और प्लम जैसी विभिन्न किस्मों की नवीनतम वरायटी उद्यान विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। पर्यटन की दृष्टि से मनाली को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक हेलिकॉप्टर सेवा भी स्वीकृत हो गई है, जिससे बाहरी पर्यटकों को यहां पहुंचने में आसानी होगी।

मनाली में ही एक वैलनेस सेंटर भी स्वीकृत किया गया है जो लगभग 46.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होगा। इस परियोजना की निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। नगर कैसल जो कि यहां की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है उसकी हालत जर्जर हो गई है। हम प्रदेश सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए 11.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके पूरा होने के बाद यह ऐतिहासिक होटल एक बार फिर से कार्यरत हो जाएगा। मनाली एक प्रमुख पर्यटन हब है, लेकिन यहां पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण स्थानीय लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी ...

12.032025/1915/A.P/A.G/01

श्री भुवनेश्वर गौड़ द्वारा जारी .....

मनाली शहर एक टूरिस्ट हब है यहां टूरिस्ट जाम से लोग बहुत परेशान होते हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों की काफी अरसे से यह डिमांड थीं कि यहां पर एक वाई-पास का निर्माण किया जाएं। हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री जी मनाली आएं, तो उस समय उन्होंने मानाली वाई-पास का शिलान्यास किया जोकि तकरीबन 32 करोड़ रुपये से बनने जा रहा है। मनाली मैं जो हमारे दो छौर एक लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, यहां पर तकरीबन 12 करोड़ की लागत से एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो मैं समझता हूं पर्यटन, हॉर्टिकल्चर व एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग है उनको भी इससे आसानी होगी। आज के समय मे जिस तरह से पूरे प्रदेश की बात की जा रही हैं, मैं यह समझता हूं कि आने वाले समय में अभी हमारी सरकार के पास तकरीबन तीन वर्ष शेष हैं। प्रदेश के विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है और पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। आज के समय में एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने जीवन की पूरी पूंजी आपदा के समय मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की थीं। मैं समझता हूं कि इस तरह की इनकी शक्सियत और पूरी टीम आने वाले समय में हिमाचल को सही दिशा में लेकर जाएंगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

12.03.2025/1915/ A.P/A.G/02

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी भाग लेगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी : माननीय सभापति महोदय, 10 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पर अपने अभिभाषण को पढ़ा और उस समय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय, अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करना के लिए आएं और कैबिनेट के द्वारा लिखा हुआ भाषण पड़ा। जब हम इस अभिभाषण को शुरू करते है तो हमने देखा की आपने इसमें गारंटियों का जिक्र तो किया है, लेकिन धरातल में एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई है और इसका जिक्र सभी माननीय वक्ताओं द्वारा किया। आप एक तरफ कह रहें है कि हमने 1500 रुपये सम्मान राशि महिलाओं को दी और वहीं आप इस वक्तव्य के पेंज 23 पर लिखते हैं कि इंदिरा गांधी प्यारी बेहना सुख समृद्धी योजना 30,000 महिलाओं को दी गई। सभापति महोदय, इसके साथ आप कह रहें है कि राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप

योजना के तहत 680 करोड़ रुपये का बजट रखा है, लेकिन आज ही यहां पर राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना पर प्रश्न लगा था और उसके जवाब पर सरकार ने कहा कि 2 वर्षों के अंदर मात्र 105 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें 75 आवेदन ही सही निकले, यानी की इस योजना के अतंर्गत मात्र 2 वर्षों के अंदर 75 लोगों को ही रोज़गार दिया गया जबकि श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार जब थीं तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में चार हजार से ज्यादा यूनिटे चल रहीं थीं। सभापति महोदय आज नवार्ड के विषय में यहां पर काफी चर्चा हुई, मैं भी माननीय सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नवार्ड के अंदर जो अंतिम 20 करोड़ रुपये की राशि सभी विधायकों को अपनी विधान सभा क्षेत्रों में काम करने के लिए दी गई हैं।

ए0टी0 द्वारा जारी .....

12.03.20205/1920/AT/ ए0जी0 /.1

श्री सरेन्द्र शौरी जारी ....

नाबार्ड के अंदर जो अंतिम 20 करोड़ रुपये की राशि सब विधायकों को अपनी विधानसभा के अंदर काम करने के लिए मिली है उसमें जो नाबार्ड को स्कीमें में दी उन्होंने कहा यह तो सिर्फ जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगे हैं या इलेक्ट्रिक बसों के लिए है और उसके साथ या नई सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा की भौगोलिक स्थिति अलग है हमारे विधानसभा में नई सड़कें बनी है और लोगों ने स्वयं मेहनत करके और डिपार्टमेंट से मिलकर के एफ0सी0ऐ0 किया हुआ है और उसके बाद वह सड़के निर्माण से इसलिए वापिस हो रही है कि उसने अंतिम किस 20 करोड़ की है वह नहीं दी जा रही है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 20 करोड़ अंतिम किसत जारी की है उसमें नई सड़कों को भी शामिल किया जाए ताकि हमारी जो दुर्गम क्षेत्रों की सड़के बनी है वह उसे राशि से बन सके क्योंकि हमीरपुर ऊना और बिलासपुर में हो सकता है कि सारी सड़कें सारी बन चुकी हों इसलिए अपग्रेडेशन की जरूरत है लेकिन हमारे विधानसभा में अभी नई सड़के बननी है और सभापति महोदय यह सरकार जैसे सत्ता में आई शुरू से ही बजट का रोना रहा और मुझे

लगता कि जिस तरह से यह सरकार बजट नहीं दे पा रही है जब हमने शपत ली तो उसके बाद हमको विधायक निधि नहीं थी और लगातार 3 वर्ष हम देख रहे हैं की अंतिम किस्त जो विकास कार्य के लिए प्लानिंग से जारी होती है और अंतिम किस्त हमारी दिसंबर से मार्च महीने तक की आती है वह लगातार 3 सालों से जारी नहीं हुई इस बार भी ना एस0डी0पी0 का पैसा आ रहा है ना विकास में जन सिहोग का पैसा आ रहा है ना मुख्यमंत्री पद योजना का पैसा आ रहा है एस0डी0पी0 का पैसा भी नहीं आया है और सभापती महोदय उसके बाद हालत क्या है एक तो बजट के लिए पैसा नहीं है दूसरा अपने क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारे विधानसभा की एकमात्र सड़क जो की पूरे क्षेत्र को जोड़ती है वह एन0एच0 305 है और एन0एच0 305 कि 2021 में हमने टायरिग की और उसके बाद वह काम सब स्टैंडर्ड हुआ लगातार टाइरिग उखड़ गई आज और आज उस सड़क की हालत खच्चर रोड से भी खराब है उस पर चलना मुसिकल है मैं यह कहना चाहूंगा कि जब एक कंपनी ने इस पर टयरिग की थी उसको 5 साल तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत उसमें काम करना था उसने काम नहीं किया अभी

12.03.20205/1920/AT/ ए0जी0 /.2

सरकार ने फिर से डी0पी0आर0 दिल्ली भेजी है लेकिन वह इसलिए रिजेक्ट हो गई की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत उसे ठेकेदार को सड़क की 5 साल तक मुरमत करनी थी लेकिन वह उसने नहीं की तो हमने एन0एच0 के अधिकारियों से कहा कि उसे कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए उसे कंपनी कि सिकियोर्टी जपत करनी चाहिए और दिल्ली में जब विवाह के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब 5 साल से पहले पैसा रिलीज नहीं होगा वह एक ही शर्त पर हो सकता है जब वह कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी तो उसे आधार पर फिर जल्दी हम पैसा देंगे । आज सड़क की बहुत जादा आबशयकता है अगर टायरिग नहीं हुइ तो हमार बंजार घटी का पूरा पर्यटन आज तहस-नहस हो गया है, इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि उस कंपनी को ब्लेक लीस्ट किया जाएं और उसकी प्रोफोर्मेंस चैक की जाएं और उनकी सिक्योरिटी जब्त की जाएं।

श्री एम0डी0 द्वारा जारी.....

12.03.2025/1925/**MD/AS/1**

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

यहां पर कृषि मंत्री श्री चन्द्र कुमार जी, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वह कह रहे थे कि प्रदेश में ऐसे कौन से अधिकारी है जिनको पैंशन नहीं मिली है या वेतन नहीं मिल रहा है? मैं कहना चाहूंगा कि (***)हमारे कुल्लू जिले के तांदी गांव में भीषण अग्निकांड हुआ। यह एक दुखदायी घटना थी। प्रदेश सरकार ने उस गांव के लिए विशेष राहत पेकेज जारी किया उसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग की थी कि जिस दिन तांदी गांव में आग लगी उस से कुछ दिन पहले बंजार क्षेत्र में चार-पांच गांवों कें 8-9 मकानों में भी आग लगी थी। उन गांवों को भी उसमें शामिल किया जाए। उन गांवों को भी विशेष राहत पेकेज दिया जाए। वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है तब से व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगातार लगाती आ रही है और व्यवस्था परिवर्तन के कारण यह सरकार चर्चा में आई। समोसा- मुर्गा ऐसी बातों के कारण चर्चा में रही। अब मुझे भी समझ आ रहा है कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर क्या किया। नया-नया विधायक बनने के बाद जब मैं ब्लॉक के अंदर पंचायत समिति की बैठक में गया, क्योंकि श्री जय राम ठाकुर जी ने 4 करोड़ रुपये की लागत से बंजार के ब्लॉक का भवन बनाया था और इस भवन को बनाने के बाद जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई और जब मैं उस भवन में बैठक करने के लिए गया तो मुझे उस समय लगा कि वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है क्योंकि जो बंजार का ऑडिटोरियम था पहले वहां पर बहुत अच्छी और सुंदर कुर्सियां लगी थी, सोफा सेट लगे थे, राउंड टेबल लगा था, मैंने सोचा कि सरकार का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि कि पूर्व सरकार ने जो 4 करोड़ रुपये का भवन बनाया था, उसमें वर्तमान सरकार ने फर्निचर की व्यवस्था कर दी। जब छः महीने बाद मैं फिर से उस हॉल के अंदर बैठक करने के लिए गया तब मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि जिस भवन में लाखों

12.03.2025/1925/MD/AS/2

रुपये का फर्निचर लगा था वहां पर प्लास्टिक की दो-चार टूटी-फूटी कुर्सियां पड़ी थी और कुछ और फर्निचर था। मैं हैरान हो गया कि जो फर्निचर वहां पर था, जैसी कुर्सी पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय बैठते हैं वैसा ही सोफा वहां लगा था, तो वह कहां गया? जब मैंने इसके बारे में जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि जिस ठेकेदार ने इस भवन में फर्निचर रखा था उसकी पेमेंट नहीं हुई है इसलिए दो दिन पहले ही वह गाड़ी लेकर आया और गाड़ी में फर्निचर भरकर ले गया और उसकी जगह पर टूटी-फूटी कुर्सिया रख दी।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

Speaker: Hon'ble Member, please now conclude.

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, दुसरा उदाहरण हमने आज तक ऐसा नहीं देखा एच.पी.पी.सी.एल का 100 मेगा वॉट का प्रोजेक्ट मेरे विधान सभा सैंज क्षेत्र में लगा है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी....

12.03.2025/1930/केएस/एएस/1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी---

पिछले साल फरवरी के महीने में वहां पर एक एक्सिअन के ऑर्डर होते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया कन्क्लूड कीजिए। Please conclude, now the time is over.

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए बड़ी इंट्रस्टिंग बात है। एक एक्सिअन के ऑर्डर होते हैं और दूसरा एक्सिअन वहां पर मंडी-कोटली से ज्वाइन करने के लिए आता है

लेकिन जिस एक्सिअन की ट्रांसफर होती है, वह इतना प्रभावशाली होता है, वह अपने ऑर्डर कैंसल कर देता है। एक साल से मैं क्या देख रहा हूं, व्यवस्था परिवर्तन क्या हुआ कि एक कुर्सी पर दो एक्सिअन बैठे हैं। जब मैंने इसके बारे में डी.जी.एम. को पूछा कि यह क्या चल रहा है?

Speaker: This part of the speech of Shri Surender Shourie will form a part of the record. Before that I adjourn the House, he has referred to Part Time Karamchari and some other sections of karamchari, they are not pensioners. So, that part of his statement is also removed from the record.

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 13 मार्च, 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 12 मार्च, 2025 **सविव।**